ई-पत्रिका
₹ 49/-

▶ खाड़ी में बहती बदलाव की बयार

▶ आर्कटिक में भारत: रूस संग नई राह

# CULT CURRENT

वर्ष: 8 अंक: 6 जून, 2025

WE MAKE VIEWS

# सीज़फायर या मिसफायर

क्या ऑपरेशन सिंदूर में 'सीज़फायर' का श्रेय लेने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश कहीं कूटनीतिक 'मिसफायर' तो नहीं साबित हो गई?

# Let's 360°

- Media Consultancy
- Web solution
- Advertising
- Publication
- Languages Services
- Survey & Research
- Branding
- AV Production
- Campaign management
- Event organizer
- PR partner, PR associate
- Content writer & provider
- Media analyst

URJAS MEDIA VENTUE IS PERHAPS THE ONLY CONSULTING FIRM THAT CAN GIVE YOUR ORGANISATION A 360 DEGREE MEDIA BUSINESS GROWTH CONSULTING THROUGH IT'S 360 CAPABILITIES. FOR US, CONSULTING DOES NOT ONLY MEAN MECHANICAL COST REDUCTION THROUGH BETTER IT APPLICATIONS, WE FIND OUT WHAT YOUR ORGANISATION REALY NEEDS AND GIVE YOU AN INTELLECTUAL SOLUTION THAT HELP YOU REDUCE COST AS WELL AS HELPS YOURS BUSINESS GROW AND BEAT THE COMPETITION.

NOW!! OUR CONSULTANT WILL GET BACK TO YOU IN 24 HOURS AND PUT YOU IN TO THE HIGH GROWTH PATH

URJAS MEDIA
VENTURE

BEAT THE COMPETITION

www.urjasmedia.com

SMS 'BUSINESS GROWTH'
TO +91-8826-24-5305 OR
E-MAIL info@urjasmedia.com

# गुमनाम नायिका

## केसर की खुशबू से बदली किस्मत

सुजाता अग्रवाल

ओडिशा की सुजाता अग्रवाल ने यह साबित कर दिया कि जुनून और नवाचार से कुछ भी संभव है। लोगों ने कहा, "केसर तो सिर्फ कश्मीर में उगता है," लेकिन सुजाता ने अपने घर के एक 10x10 कमरे में हाइड्रोपोनिक सिस्टम से केसर उगाकर सबको चौंका दिया। डांस टीचर से उद्यमी बनी सुजाता ने लॉकडाउन में माइक्रोग्रीन्स से शुरुआत की और फिर 10 लाख रुपये निवेश कर 'Bloom In Hydro' ब्रांड लॉन्च किया। आज वह केसर से बने हेयर सीरम, कावा टी और फेस पैक जैसे उत्पाद बेचकर सालाना 24 लाख रुपये कमा रही हैं। उनकी सफलता से प्रेरित होकर कृषि के छात्र भी केसर की खेती की ओर आकर्षित हो रहे हैं। उनके प्रोडक्ट्स की बिक्री में 40% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

# संपादकीय


**राष्ट्रीय संपादक**
संजय श्रीवास्तव

**संपादक**
श्रीराजेश

**प्रबंध संपादक**
सच्चिदानंद पाण्डेय

**रोमिंग संपादक**
डॉ. राजाराम त्रिपाठी

**राजनीतिक संपादक**
अंशुमान त्रिपाठी

**मेट्रो संपादक**
शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव
डॉ. रुद्र नारायण

**अंतर्राष्ट्रीय संपादक**
श्रीश पाठक

**कारपोरेट संपादक**
गगन बत्रा

**खेल संपादक**
जलज श्रीवास्तव

**डिजीटल संपादक**
सुनीता त्रिपाठी

**सहायक संपादक**
संदीप कुमार

**उप संपादक**
मनोज कुमार
संतु दास

**साहित्य संपादक**
अनवर हुसैन

**कला संपादक**
जया वर्मा

**वेब एवं आईटी विशेषज्ञ**
अनुज कुमार सिंह

**फोटो संपादक**
विवेक पाण्डेय

**विशेष संवाददाता**
कमलेश झा
विकास गुप्ता

**संवाददाता**
संदीप सिंह
अनिरुद्ध यादव

**ब्यूरो प्रमुख (अंतर्राष्ट्रीय)**
अकुल बत्रा (अमेरिका)
सी.शिवरतन (नीदरलैंड)
जी. वर्मा(लंदन)
डॉ. मो. फहीम अकबर (पाकिस्तान)
ए. असगरजादेह (ईरान)
डॉ. निक सेरी (मलेशिया)

**ब्यूरो प्रमुख (राष्ट्रीय)**
आर. रंजन (नई दिल्ली)
संजय कुमार सिंह (लखनऊ)
कैप्टन सुधीर सिन्हा (रांची)
निमेष शुक्ल (पटना)
नागेन्द्र सिंह (कोलकाता)
राकेश रंजन (गुवाहाटी)

**विपणन**
**सत्यजीत चौधरी**
महाप्रबंधक

**ऑनलाइन प्रसार**
**सृजीत डे**



CULT CURRENT
WE MAKE VIEWS
DELENG19447

वर्षः 8 अंकः 6 जून, 2025

Editorial/Business office

Follow us:
fb.com/cultcurrent @Cult_Current cultcurrent@gmail.com

**URJAS MEDIA VENTURE**
**Head office:** Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109, INDIA, Tel: +91 6289-26-2363
**Corporate Office:** 14601, Belaire Blvd, Houston, Texas 77083 USA Tel: +1 (832) 670-9074
Web: http://cultcurrent.in

Cult Current is a monthly e-magazine published by Urjas Media Ventures from Swastik Apartment, GF, Pirtala, Agarpara, Kolkata 700 109.
**Editor: Srirajesh**



**Disclaimer:** All editorial and non-editorial positions in the e-magazine are honorary. The publisher and editorial board are not obligated to agree with all the views expressed in the articles featured in this e-magazine. Cult Current upholds a commitment to supporting all religions, human rights, nationalist ideology, democracy, and moral values.

# CONTENT

## COVER STORY 26

## 6G

## 12 दूरदर्शिता या जल्दबाज़ी?

## 16 बांग्लादेश में स्टारलिंक
## जुआ या ज़रूरत?

## 54 ISKP v/s BLA
### एक भू-राजनीतिक दुष्चक्र

**ट्रंप का दांव, भारत का खेल:** तकनीकी वर्च स्व की दौड़ 58

**अमेरिकी सुरक्षा** पर चीन की छाया 62

**खाड़ी में बहती** बदलाव की बयार 70

## 66 आर्कटिक में भारत
### रूस संग नई राह

लिसा मिश्रा

**'पचासों बार हुई रिजेक्ट'** 74

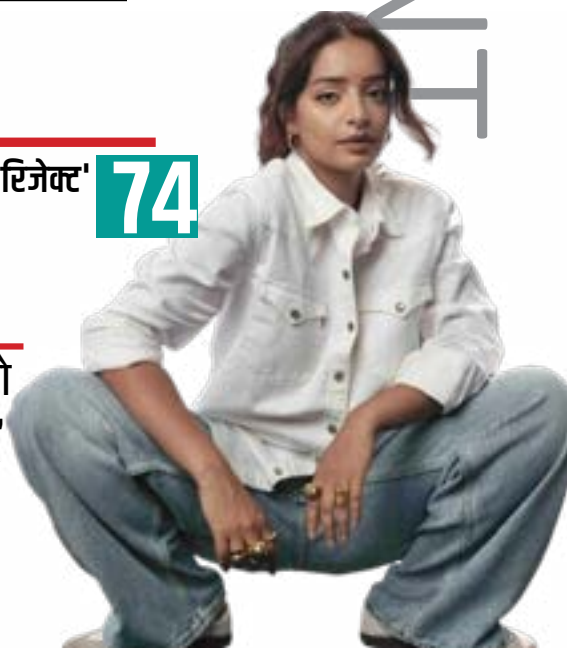

पंकज त्रिपाठी

**'थोड़ा गुरूर चढ़े तो मैं खुद को संभालूं'**

## 76

# Small talk

## मैं बहुत रोमांटिक लड़की रही हूं: अनन्या पांडे

इंडस्ट्री में 6 साल पूरे कर चुकी अनन्या पांडे को उनकी हालिया रिलीज 'केसरीःचैप्टर 2' की भूमिका के लिए पसंद किया जा रहा है। फिल्म 'गहराइयां' और 'कॉल भी बे' जैसी सीरीज की इस एक्ट्रेस का मानना है कि करियर का शुरुआती दौर उनके लिए मुश्किल था, मगर अब वह अपने काम और लोगों के प्यार पर फोकस करती हैं। वह कहती हैं- मैं जब छोटी थी, तभी से मैं होपलेस रोमांटिक लड़की रही हूं। मुझे जिंदगी में प्यार, मोहब्बत, पति और बच्चे सब चाहिए। मैं और मेरे जो भी दोस्त हैं, वो भी प्यार और शादी को लेकर ऐसा ही सोचते हैं। ●

# 2025 में तहलका मचाने वाली खोजें

### साहसी खटमलों ने बदला इतिहास!

60,000 साल पहले, कुछ खटमल चमगादड़ों को छोड़कर नीएंडरथल पर चढ़ गए। इनसे ही मानव-खटमल संबंध शुरू हुआ। Virginia Tech के शोध में मानव-खटमल का इतिहास सामने आया है। चमगादड़ों वाले खटमलों की आबादी हिमयुग के बाद घटी, जबकि मानवों वाले खटमलों की बढ़ी। यह अध्ययन Biology Letters में प्रकाशित हुआ है और बताता है कि खटमल शायद पहले शहरी कीट हैं। ●

### अंतरिक्ष में 'क्वेसार' का हमला!

खगोलविदों ने पहली बार एक आकाशगंगा को दूसरी पर शक्तिशाली विकिरण की किरण से हमला करते देखा है। नेचर में प्रकाशित इस अध्ययन में पता चला कि हमलावर आकाशगंगा की ऊर्जा से लक्ष्य आकाशगंगा की नई तारे बनाने की क्षमता कमज़ोर हो जाती है। VLT और ALMA जैसे उन्नत दूरबीनों का उपयोग कर, वैज्ञानिकों ने विस्तृत अध्ययन किया। इनमें से एक 'क्वेसार' नामक शक्तिशाली विकिरण छोड़ रही थी। ●

### शारीरिक गतिविधि से दिमाग रहता है स्वस्थ!

The Lancet में प्रकाशित शोध के अनुसार, शारीरिक गतिविधि से मस्तिष्क स्वस्थ रहता है। Endurance training और अच्छी फिटनेस डिमेंशिया का खतरा कम करते हैं और स्वस्थ मस्तिष्क को बढ़ावा देते हैं। छोटे स्तर की शारीरिक गतिविधि भी मस्तिष्क की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा कर देती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि सक्रिय रहना हृदय के साथ-साथ मस्तिष्क के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रतिदिन थोड़ी कसरत भी लाभदायक है। ●

## ठोस बैटरी: तेज़ चार्जिंग का रास्ता खुला!

ठोस-अवस्था बैटरी को ऊर्जा भंडारण का भविष्य माना जा रहा है। अब, म्यूनिख तकनीकी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने लिथियम, एंटीमनी और स्कैंडियम से बनी एक नई सामग्री विकसित की है। यह सामग्री लिथियम आयनों को 30% तेज़ी से स्थानांतरित करने में मदद करती है, जिससे बैटरी तेजी से चार्ज होंगी और अधिक कुशल बनेंगी। ●

## Tata Altroz Facelift: प्रीमियम हैचबैक का नया अवतार

टाटा मोटर्स ने 2025 Altroz फेसलिफ्ट को 6.89 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। यह प्रीमियम हैचबैक पेट्रोल, डीज़ल और CNG विकल्पों में उपलब्ध है। नई Altroz में 10.25-इंच टचस्क्रीन, 360 कैमरा, 6 एयरबैग्स और ALFA आर्किटेक्चर जैसी सुविधाएँ शामिल हैं। इसके चार ट्रिम्स—Smart, Pure, Creative, और Accomplished—में से चुन सकते हैं। ●

## नियुक्ति

### डॉ. अजय कुमार
**अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग**

13 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पूर्व रक्षा सचिव डॉ. अजय कुमार को UPSC का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने 15 मई को पदभार ग्रहण किया। IIT कानपुर से बी.टेक और अमेरिका से पीएच.डी. धारक डॉ. कुमार को रक्षा क्षेत्र में सुधारों के लिए जाना जाता है। उनकी नियुक्ति UPSC में अनुभव और नेतृत्व क्षमता को और मजबूत करेगी।

## इस्तीफा

### एन. चंद्रशेखरन
**चेयरमैन व निदेशक, टाटा केमिकल्स**

टाटा संस के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने 29 मई 2025 को टाटा केमिकल्स के चेयरमैन और निदेशक के पदों से इस्तीफा दे दिया। कंपनी के बोर्ड ने उनकी जगह एस. पद्मनाभन को नया चेयरमैन नियुक्त किया है।

## उन्होंने कहा

**इमैनुएल मैक्रों**
राष्ट्रपति, फ्रांस

"यदि हम यूक्रेन युद्ध से ध्यान हटाकर केवल इंडो-पैसिफिक और चीन पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम दोनों मोर्चों पर हार सकते हैं।"

**व्लादिमीर पुतिन**
राष्ट्रपति, रूस

"रूस संघर्ष समाप्त करने को तैयार है, लेकिन तभी जब यूक्रेन एक तटस्थ राष्ट्र बना रहे, हमेशा के लिए नाटो की सदस्यता की महत्वाकांक्षा छोड़े।"

## श्रद्धांजलि

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत के एक महान सपूत, शिक्षाविद् और दूरदर्शी राजनेता थे, जिन्होंने जम्मू-कश्मीर को भारत का पूर्ण और अभिन्न अंग बनाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने संसद में अपने ओजस्वी भाषणों में धारा 370 को समाप्त करने की पुरजोर वकालत की, जिसे वे भारत के बाल्कनीकरण की संज्ञा देते थे। अगस्त 1952 में जम्मू कश्मीर की एक विशाल रैली में उन्होंने अपना संकल्प व्यक्त किया था कि 'या तो मैं आपको भारतीय संविधान प्राप्त कराऊंगा, या फिर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना जीवन बलिदान कर दूंगा।' अपने संकल्प को पूरा करने के लिए डॉ. मुखर्जी 1953 में बिना परमिट लिए जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर निकल पड़े, जहाँ पहुंचते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 23 जून 1953 को जेल में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिसके परिणामस्वरूप अंततः परमिट सिस्टम समाप्त हो गया। उन्होंने कश्मीर को लेकर एक नारा दिया था, 'नहीं चलेगा एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान।' उनके निधन पर उनकी माता, योगमाया देवी ने कहा था, 'मेरे पुत्र की मृत्यु भारत माता के पुत्र की मृत्यु है।' भारत माता के इस वीर पुत्र का जन्म 6 जुलाई 1901 को एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। उनके पिता, सर आशुतोष मुखर्जी बंगाल में एक शिक्षाविद् और बुद्धिजीवी के रूप में प्रसिद्ध थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक होने के पश्चात श्री मुखर्जी 1923 में सेनेट के सदस्य बने। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात, 1924 में उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में नामांकन कराया। 1926 में उन्होंने इंग्लैंड के लिए प्रस्थान किया, जहां लिंकन्स इन से 1927 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की। 33 वर्ष की आयु में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए और विश्व का सबसे युवा कुलपति होने का सम्मान प्राप्त किया।



**श्यामा प्रसाद मुखर्जी**
(06/07/1901-23/06/1953)

## अमेरिका में टैरिफ नीति को न्यायिक झटका

बीते 28 मई को अमेरिकी अंतरराष्ट्रीय व्यापार न्यायालय ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए कुछ विशेष टैरिफों को अवैध ठहराते हुए बड़ा फैसला सुनाया। ट्रंप प्रशासन ने ये शुल्क 1977 के अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियों अधिनियम (IEEPA) के अंतर्गत लागू किए थे, जिससे राष्ट्रपति को आपातकालीन स्थितियों में विशेष अधिकार मिलते हैं। लेकिन न्यायालय ने माना कि इस अधिनियम का प्रयोग इस तरह के दीर्घकालिक और व्यापक आर्थिक हस्तक्षेप के लिए नहीं किया जा सकता। इस निर्णय से अमेरिकी व्यापार नीति की वैधता पर सवाल खड़े हो गए हैं और घरेलू उद्योगों को मिली सुरक्षा को भी चुनौती मिली है। वैश्विक बाजारों ने इस खबर के बाद अस्थिरता दिखाई, विशेष रूप से यूरोपीय संघ और एशियाई देशों के साथ अमेरिका के व्यापारिक रिश्तों पर दबाव बढ़ा। ●

## माली में लोकतंत्र समर्थक जनांदोलन

इस महीने माली में सैन्य सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। 2021 से सत्ता में काबिज सैन्य शासन ने सभी राजनीतिक दलों को भंग कर दिया और राष्ट्रपति असिमी गोइता के कार्यकाल को 2030 तक बढ़ाने का ऐलान किया। इस पर नागरिक समाज संगठनों, छात्रों और विपक्षी कार्यकर्ताओं ने राजधानी बामाको समेत देशभर में प्रदर्शन किए। कई स्थानों पर हिंसा और गिरफ्तारी की घटनाएं भी हुईं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय विशेषकर अफ्रीकी संघ और संयुक्त राष्ट्र ने इस स्थिति पर चिंता जताई है। ●

## RBI द्वारा उदार प्रेषण योजना की समीक्षा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने घोषणा की कि वह 'लिबरलाइज़्ड रेमिटेंस स्कीम' (LRS) की समीक्षा करेगा, जिसके अंतर्गत भारतीय नागरिक विदेश में निवेश और खर्च हेतु प्रतिवर्ष $250,000 तक भेज सकते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक $30 बिलियन से अधिक निकासी हो चुकी है, जो एक रिकॉर्ड है। इस तेज़ी ने रुपये पर दबाव और विदेशी मुद्रा भंडार में असंतुलन पैदा किया है। RBI अब नियमों को सख्त करने पर विचार कर रहा है। जून में इस नीति की समीक्षा और संभावित बदलाव लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। ●

## बांग्लादेश में अवामी लीग के विरुद्ध छात्र आंदोलन

ढाका के शाहबाग चौक पर छात्रों और युवाओं के समूह 'स्टूडेंट्स अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन' ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। आंदोलन की मांग थी कि लंबे समय से सत्ता में रही अवामी लीग को प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि उस पर चुनावी धांधली, दमन और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं। प्रदर्शन के बाद सरकार ने पार्टी की गतिविधियों पर आंशिक प्रतिबंध लगाया और चुनाव आयोग ने उसका पंजीकरण निलंबित कर दिया। इससे बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ गई है। ●

## नेपाल में हिंदू राष्ट्र और संवैधानिक राजशाही की बहाली की मांग

महीने के अंत में काठमांडू में हजारों लोगों ने 'हिंदू राष्ट्र और संवैधानिक राजशाही' की बहाली के समर्थन में प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी (RPP) और अन्य दक्षिणपंथी संगठनों ने इस रैली का नेतृत्व किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और सांस्कृतिक संकट का समाधान नहीं कर पा रही। वे पूर्व राजा ज्ञानेंद्र को पुनः प्रतिष्ठित करने की मांग कर रहे हैं। ●

## मंगोलिया में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन

मंगोलिया की राजधानी उलानबातर में भ्रष्टाचार और आर्थिक असमानता के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन हुए। प्रधानमंत्री लुव्सन्नमसराई ओयुन-एर्डेने के पुत्र की भव्य जीवनशैली की तस्वीरें सामने आने के बाद जनता में आक्रोश बढ़ा। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की मांग की और सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। इसके परिणामस्वरूप, सत्तारूढ़ मंगोलियाई पीपुल्स पार्टी ने डेमोक्रेटिक पार्टी को गठबंधन से बाहर कर दिया। प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार जांच के लिए खुद को प्रस्तुत किया है। ●

## अमेरिका में मानवीय पैरोल नीति का अंत

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के 5 लाख से अधिक प्रवासियों के लिए दी जा रही मानवीय पैरोल सुरक्षा समाप्त करने की अनुमति दे दी। इस फैसले से करीब एक मिलियन प्रवासी निर्वासन के खतरे में आ गए हैं। साथ ही, होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने 500 से अधिक संकटग्रस्त क्षेत्रों की सूची जारी की है, जिन्हें संघीय फंडिंग से वंचित किया जा सकता है। ट्रंप प्रशासन ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययनरत विदेशी नागरिकों के लिए वीजा प्रक्रिया को और कड़ा कर दिया है। इन नीतियों ने अमेरिका में आव्रजन, मानवाधिकार और उच्च शिक्षा नीति को लेकर तीव्र बहस छेड़ दी है। आलोचकों का मानना है कि यह फैसला प्रवासियों के प्रति कठोरता और चुनावी रणनीति का हिस्सा है। ●

## हांगकांग में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना

चीन ने हांगकांग में एक नया अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन स्थापित किया, जिसका उद्देश्य वैश्विक विवाद समाधान में हांगकांग की स्थिति को मजबूत करना है। इस पहल में इंडोनेशिया, पाकिस्तान, लाओस, कंबोडिया और सर्बिया सहित 20 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। यह संगठन देशों, राज्यों और विदेशी नागरिकों के बीच विभिन्न विवादों का समाधान करेगा। हालांकि, कुछ विश्लेषकों ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से संबंधित विवादों में पक्षपात की संभावना पर चिंता व्यक्त की है। ●

## इंडोनेशिया में विदेशी निवेश पर 'प्रेमन' गिरोहों का प्रभाव

इंडोनेशिया में विदेशी निवेश, विशेष रूप से इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में, 'प्रेमन' (स्थानीय गिरोहों) और प्रणालीगत भ्रष्टाचार के कारण बाधित हुआ। चीन की BYD और वियतनाम की VinFast जैसी कंपनियों को भारी 'मुआवजा' देने के लिए मजबूर किया गया। प्रधानमंत्री प्रबोवो सुबियांतो ने 19 मिलियन नौकरियों और 8% आर्थिक वृद्धि का लक्ष्य रखा है, लेकिन इन गिरोहों की गतिविधियों से निवेशकों में असुरक्षा बढ़ी है। सरकार ने 'ठग विरोधी' टास्क फोर्स स्थापित की और 4,000 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि राजनीतिक और गिरोहों के बीच गहरे संबंधों के कारण वास्तविक सुधार कठिन है। ●

## वायुसेना प्रमुख ने रक्षा परियोजनाओं में देरी पर जताई चिंता

भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने गुरुवार को रक्षा परियोजनाओं में बार-बार हो रही देरी को लेकर गंभीर चिंता जताई। वे 2025 के सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "समयसीमा एक बड़ा मुद्दा है अब तक कोई भी परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई है।" कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में उन्होंने प्रश्न उठाया कि "हम ऐसे वादे क्यों करें जो हम निभा ही नहीं सकते?" एयर चीफ मार्शल ने अनुबंधों के क्रियान्वयन पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि कई बार समझौते पर हस्ताक्षर करते समय ही साफ हो जाता है कि लक्ष्य पूरे नहीं हो पाएंगे। उन्होंने प्रमुख रक्षा परियोजनाओं की देरी के उदाहरण दिए—जैसे तेजस मार्क 1ए की डिलीवरी में हो रही देर, तेजस मार्क 2ए का प्रोटोटाइप अब तक न आना इत्यादि। ●

## आवारा कुत्तों के लिए पुनर्वास नीति बनाने पर विचार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया कि वे राष्ट्रीय राजधानी में आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए नीति बनाने पर विचार करें। यह देखते हुए कि इस मुद्दे पर नीतिगत फैसला लिए जाने की जरूरत है, जस्टिस पुष्करणा ने मामले को दिल्ली के मुख्य सचिव के पास भेज दिया है। कानूनी मामलों की वेबसाइट 'लाइव लॉ' के मुताबिक कोर्ट ने कहा, 'यह निर्देश दिया जाता है कि हितधारकों द्वारा एक नीतिगत निर्णय लिया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि संस्थागत स्तर पर आवारा कुत्तों के पुनर्वास के लिए प्रावधान बनाए जाएं। ●

## इसी वित्तवर्ष में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा भारत

नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरमानी ने सोमवार को भरोसा जताया है कि भारत 2025-26 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इसके साथ ही भारत जापान को पीछे छोड़ देगा। अरविंद ने कहा, "डेटा अप्रैल 2026 में सामने आएगा। कई बार यह थोड़ा पहले फरवरी या मार्च में आ जाता है लेकिन हम अंतरराष्ट्रीय पुष्टि की उम्मीद केवल 2026 में कर सकते हैं।" उन्होंने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि 2025-26 में हमारा पूर्वानुमान सही साबित होगा। ●

## भारतीय निजी कंपनियां बनायेगी लड़ाकू विमान

भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को देश के सबसे एडवांस्ड स्टील्थ फाइटर जेट के निर्माण के लिए फ्रेमवर्क को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्रालय के हवाले से यह जानकारी है कि मंत्रालय के मुताबिक, यह पांचवीं पीढ़ी का दो इंजन वाला लड़ाकू विमान होगा। बयान के मुताबिक, "यह एग्जीक्यूशन मॉडल एक प्रतिस्पर्धी आधार पर निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों को समान मौके देता है। वे स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उद्यम के रूप में या संघ के रूप में बोली लगा सकते हैं। ●

## आर्ट्स और कॉमर्स स्टूडेंट भी अब बन पाएंगे कॉमर्शियल पायलट

नागरिक विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भारत में कॉमर्शियल पायलट ट्रेनिंग के लिए शैक्षिक पात्रता मानदंड को संशोधित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इस कदम के बाद आर्ट्स और कॉमर्स विषयों से 12वीं कक्षा पास करने वाले स्टूडेंट्स भी कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस (सीपीएल) हासिल कर पाएंगे। पिछले 30 सालों से विज्ञान विषयों के साथ 12वीं पास करने वाले स्टूडेंट ही सीपीएल ट्रेनिंग हासिल कर पाते थे। ●

## 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी में DMK सबसे आगे

तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने 2026 विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज करते हुए सात ज़ोनल प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। पार्टी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन 1 जून को पार्टी की जनरल काउंसिल मीटिंग में चुनावी रणनीति पेश करेंगे। वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, डीएमके ने दिसंबर 2024 में ही चुनावी काम शुरू कर दिया था और मार्च 2025 तक उम्मीदवारों की रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई थी। ●

## दिल्ली में अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई, 700 से अधिक बांग्लादेशी वापस भेजे गए

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी में बड़े पैमाने पर सघन अभियान चलाकर अवैध प्रवासियों की पहचान और निष्कासन की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस अभियान में अब तक 470 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों और 50 ऐसे विदेशियों की पहचान की गई जो वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद देश में रह रहे थे। इन सभी को हिंडन एयरबेस से विशेष विमानों द्वारा त्रिपुरा के अगरतला पहुंचाया गया और फिर भूमि सीमा के माध्यम से बांग्लादेश वापस भेजा गया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले वर्ष के अंत में अवैध बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 15 नवंबर 2024 से 20 अप्रैल 2025 के बीच लगभग 250 प्रवासियों को पकड़ा गया और एफआरआरओ को सौंप दिया गया। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि इन अवैध प्रवासियों की भारत में बसने में किसने सहायता की, कौन फर्जी दस्तावेज तैयार करता है। ●

## डंकरहित मधुमक्खियां बढ़ाएंगी खेती की उपज

मधुमक्खियों के बारे में यह रिपोर्ट इंटरनेशनल जर्नल आफ फार्म साइंसेज समेत कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय जर्नलों में छपी है। नागालैंड विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग के रिसर्चरों की एक टीम ने राज्य में पाई जाने वाली डंकरहित मधुमक्खियों पर लंबे समय तक अध्ययन किया है. इस टीम में प्रोफेसर एच.के. सिंह (अवकाश प्राप्त) और डा. इम्तिनारो एल. शामिल हैं। इस टीम ने राज्य में कीटों की इस श्रेणी की 27 में दो प्रजातियों टेट्रागोनुला इरीडीपेनिस और लेपिडोट्रिगोना आर्किफेरा की पहचान की है। ●

## भारत-पाक झड़प पर सीडीएस चौहान: शुरुआती त्रुटियां, निर्णायक प्रतिक्रिया

सिंगापुर में शांगरी-ला डायलॉग के दौरान हाल ही में एक साक्षात्कार में, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जनरल अनिल चौहान ने स्वीकार किया कि पाकिस्तान के साथ हालिया सैन्य झड़प के दौरान रणनीतिक त्रुटियों के कारण भारत को शुरुआती झटके लगे। उन्होंने माना कि भारतीय वायुसेना को शुरुआती नुकसान हुआ, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि मुख्य मुद्दा यह समझना था कि विमान क्यों खोए गए। जनरल चौहान ने कहा कि भारत ने जल्दी ही अपनी गलतियों को सुधारा और दो दिन बाद एक शक्तिशाली जवाबी हमला शुरू किया, जिसमें लंबी दूरी से पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला किया गया। उन्होंने पाकिस्तान के छह भारतीय जेट विमानों को मार गिराने के दावे को झूठा बताया।

**श्रीराजेश,** संपादक

## उड़ान जारी

# अब तीसरी पायदान की ओर

**भारत का यह उदय ऐसे समय में हो रहा है जब प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, जैसे कि अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापारिक समझौतों पर बातचीत चल रही है।**

हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने एक प्रेस ब्रीफिंग में घोषणा की कि भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है। भारत की अर्थव्यवस्था 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी से पीछे है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि अगर योजनाएं सही दिशा में आगे बढ़ती रहीं, तो अगले तीन वर्षों में भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यह उपलब्धि न केवल भारत के आर्थिक विकास की गति को दर्शाती है, बल्कि यह भी स्पष्ट करती है कि देश वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को और मजबूत करने के लिए तैयार है।

भारत की अर्थव्यवस्था का यह उत्थान कई कारकों का परिणाम है। सरकार द्वारा समर्थित नीतियों, संरचनात्मक सुधारों और घरेलू संसाधनों के कुशल उपयोग ने विकास को गति दी है। 'मेक इन इंडिया,' 'डिजिटल इंडिया,' और 'स्किल इंडिया' जैसी पहलों ने न केवल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है, बल्कि रोजगार सृजन और नवाचार को भी प्रोत्साहित किया है। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार की संपत्ति मुद्रीकरण योजना का एक नया दौर तैयार किया जा रहा है, जिसकी घोषणा अगस्त में की जाएगी। यह कदम वित्तीय संसाधनों को जुटाने और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, जिससे आर्थिक विकास को और गति मिलेगी।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार, 2024-25 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर 6.5% बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। यह दर वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितताओं के बावजूद भारत की आर्थिक लचीलापन को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2047 तक देश को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के अपने आह्वान को दोहराया है। यह लक्ष्य भारत को अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों को अधिक समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए प्रेरित कर रहा है।

भारत का यह उदय ऐसे समय में हो रहा है जब प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं, जैसे कि अमेरिका और यूरोप के साथ व्यापारिक समझौतों पर बातचीत चल रही है। भारत सरकार इन समझौतों के माध्यम से अपने निर्यात को बढ़ावा देने और वैश्विक व्यापार में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उत्सुक है। भारतीय नियामक विकास के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं, जिसमें अप्रैल में देश के केंद्रीय बैंक द्वारा प्रमुख ब्याज दरों में कटौती भी शामिल है। यह कदम आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने और निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाया गया था, लेकिन इसके साथ ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की चुनौती भी बनी हुई है।

हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार बढ़ रही है, लेकिन विश्लेषकों ने नोट किया है कि वर्तमान विकास दर पिछले वर्ष की 9.2% की वृद्धि से काफी कम है। यह गिरावट वैश्विक आर्थिक मंदी, उच्च मुद्रास्फीति और भू-राजनीतिक तनावों के कारण हो सकती है। महिंद्रा समूह के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'जैसे ही हम जश्न मनाते हैं, हमें असंतुष्ट रहना चाहिए।' उनका मानना है कि भारत की अगली छलांग न केवल जर्मनी के सकल घरेलू उत्पाद को पार करने पर केंद्रित होनी चाहिए, बल्कि प्रति व्यक्ति जीडीपी में सुधार पर भी ध्यान देना चाहिए। प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि से ही वास्तविक रूप से नागरिकों

के जीवन स्तर में सुधार होगा।

यह सच है कि भारत को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है। गरीबी, असमानता और बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समाधान करना जरूरी है। इसके अलावा, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ाना होगा ताकि सभी नागरिकों को विकास का लाभ मिल सके। कौशल विकास, रोजगार सृजन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत करना होगा ताकि कोई भी पीछे न रहे।

भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत और लचीला बनाने के लिए कई कदम उठाने होंगे- इसके लिए संरचनात्मक सुधार की आवश्यकता होगी, इसके अंतर्गत भूमि सुधार, श्रम सुधार और कर सुधार जैसे क्षेत्रों में सुधारों को जारी रखना होगा। भूमि सुधार से कृषि उत्पादकता बढ़ेगी, श्रम सुधार से उद्योग विकास को प्रोत्साहन मिलेगा और कर सुधार से राजस्व संग्रह में सुधार होगा। साथ ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ाना होगा। डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ-साथ ई-गवर्नेंस को मजबूत करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि विकास का लाभ सभी नागरिकों तक पहुंचे, खासकर गरीब और वंचित समुदायों तक। टिकाऊ विकास को बढ़ावा दे कर पर्यावरण को संरक्षित करना प्राथमिक लक्ष्य रहना चाहिए। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा और पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना होगा।

भारत का चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, लेकिन यह केवल एक शुरुआती बिंदु है। भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूत, समावेशी और टिकाऊ बनाने के लिए अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना है। सही नीतियों, निवेश और दृष्टिकोण के साथ, भारत निश्चित रूप से 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह न केवल भारत के लिए, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण होगा। भारत की सफलता वैश्विक अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी और विकास के नए अवसरों को जन्म देगी। भारत का उदय एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की ओर एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, जिसमें विभिन्न देशों को अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा।

srirajesh.journalist @srirajesh editor@cultcurrent.com

# दूरदर्शिता या जल्दबाज़ी?

अनिर्बान सरमा

**पहले की 5G तकनीक और आज की AI की तरह, 6G में भी वर्चस्व की दौड़ शुरू हो गई है। यह समय-पूर्व की कोशिश लग सकती है, क्योंकि 5G तकनीक अभी विकसित हो ही रही है।**

साल 2023 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 6G युग में प्रवेश करने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। हमें यह सफलता कई अन्य उपलब्धियों के आधार पर मिलने जा रही है। दुनिया की पांच सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में अपनी जगह बनाने के अलावा, भारत ने विश्व स्तर पर सबसे सस्ती इंटरनेट सेवाएं और मोबाइल डाटा प्लान उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा, इसने दुनिया में सबसे तेज़ी से और सबसे बड़े पैमाने पर 5G तकनीक अपनाई है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 6G दूरसंचार सेवाओं को रोमांच से भरी नई दिशाओं की ओर ले जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि भारत ने इसे सच बनाने के लिए किस तरह काम शुरू कर दिया है।

सवाल है कि 6G है क्या? और, यह क्यों इतना मायने रखता है?

## 6G को समझिए

6G, या छठी पीढ़ी का वायरलेस, मोबाइल संचार का नया मानक बनने जा रहा है। उम्मीद है, यह तकनीक 2030 के दशक के शुरुआती वर्षों में ही 5G को पीछे छोड़ देगी और कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। 5G की क्षमताओं को बेहतर बनाते हुए तैयार किए गए 6G नेटवर्क का उद्देश्य है- डाटा को अभूतपूर्व तेज़ गति में उपलब्ध कराना, अल्ट्रा-लो लेटेंसी (बहुत कम समय में डाटा को प्रोसेस करना), काफ़ी बड़ी संख्या में उपकरणों को अनुकूल बनाने की क्षमता पैदा करना और पहले से उन्नत तकनीकों, जैसे बिग डाटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), एक्सटेंडेड रियलिटी (XR) और एक ही समय में कई जगहों की सेंसिंग को आसानी से जोड़ना।

जैसा कि बेल लेब्स कहती है, '6G नेटवर्क डिजिटल, भौतिक और इंसानी दुनिया को एक साथ जोड़ देगा, जिससे अतिरिक्त संवेदी अनुभवों (देखने, सुनने, छूने, स्वाद लेने और गंध महसूस करने के अलावा मिलने वाले अनुभव) के दरवाज़े खुलेंगे। बुद्धिमान मानी जाने वाली ज्ञान प्रणालियों को मज़बूत गणना क्षमताओं से जोड़ा जाएगा, जिससे नेटवर्क, एप्लिकेशन और प्रोसेसर की भूमिकाएं एक साथ आ जाएंगी।'

6G पर अभी अनुसंधान और विकास का काम चल रहा है। हालांकि, 'अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ' (ITU) और 'थर्ड जेनरेशन पार्टनरशिप' (3GPP) जैसे संगठन जिस तरह 6G के मानक व इसकी रूपरेखा को

## 5G और 6G की तुलना

| विशेषता | 5G | 6G (संभावित) |
|---|---|---|
| पीक डाटा दर | ~10 Gbps | 1 Tbps तक |
| विलंबता | ~1 मिलीसेकंड | <0।1 मिलीसेकंड |
| बैंडविड्थ | mmWave (24-100 GHz) | THz (100 GHz -10 THz) |
| AI से जुड़ाव | आंशिक | जन्मजात और स्थायी |
| कनेक्टिविटी घनत्व | ~1 मिलियन डिवाइस प्रति वर्ग किलोमीटर | 1 करोड़+ डिवाइस प्रति वर्ग किमी |
| ऊर्जा दक्षता | 4G से बेहतर | उल्लेखनीय ध्यान |

**स्रोत- विभिन्न स्रोतों से खुद लेखक द्वारा संकलित**

परिभाषित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं या जिस तरह सुधार के अन्य काम किए जा रहे हैं, उसका मतलब यही है कि 6G नेटवर्क अगले पांच वर्षों में व्यावसायिक तौर पर उपयोग में लाने और अपनाने के लिए तैयार किया जा सकता है।

### दबदबा कायम करने की दौड़

पहले की 5G तकनीक और आज की AI की तरह, 6G में भी वर्चस्व की दौड़ शुरू हो गई है। यह समय-पूर्व की कोशिश लग सकती है, क्योंकि 5G तकनीक अभी विकसित हो ही रही है। आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 के अंत तक दुनिया भर में 5G के 320 नेटवर्क थे और विश्व की करीब 55 प्रतिशत जनसंख्या तक ही यह तकनीक पहुंच सकी थी। मगर, 6G में आगे बढ़ने के लिए चल रही दौड़ दूरदर्शी भी है और रणनीतिक भी, क्योंकि यह तकनीकी, आर्थिक और भू-राजनीतिक ताकत को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकती है।

2030 के बाद वायरलेस दूरसंचार के लिए 6G एक वैश्विक न्यूनतम मानदंड बन जाएगा। इस कारण, जो देश या गठबंधन इसके विकास की अगुवाई करेगा, उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी मानक बनाने का मौका मिलेगा, ठीक उसी तरह, जैसे हुआवेई 5G मानकों को प्रभावित कर रही है। इस तरह के देश यह सुनिश्चित कर सकेंगे कि उनकी अपनी कंपनियों और प्रौद्योगिकियों के आधार पर यह तकनीक आगे बढ़े। वास्तव में, किसी देश के 6G पारिस्थितिकी तंत्र को विश्व स्तर पर अपनाने से लंबे समय तक उस देश पर दुनिया की निर्भरता बनी रहेगी और उसका भू-राजनीतिक प्रभाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा, 6G तकनीक में रोबोटिक्स, ऑटोनॉमस सिस्टम (खुद-ब-खुद काम करने वाले तंत्र), स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग और एक्सटेंडेड रियलिटी जैसे क्षेत्रों में नई पीढ़ी के औद्योगिक साधनों को महत्व दिए जाने के कारण इस तकनीक में दबदबा रखने वाले देश प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में मुकाबलों में आगे रहेंगे। देखा जाए, तो 6G में दबदबा रखने का अर्थ होगा, रक्षा तकनीक और साइबर संचालन के मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से आगे रहना।

चीन और अमेरिका पहले से ही 6G में नेतृत्व करने के लिए एक-दूसरे से भयंकर तरीके से उलझे हुए हैं। नवंबर 2020 में चीन की सरकार ने दुनिया का पहला 6G उपग्रह लॉन्च किया, जिसे अल्ट्रा-हाई फ्रीक्वेंसी बैंड का पता लगाने और 6G उपग्रह इंटरनेट सेवा का आकलन करने के लिए तैयार किया गया था। दूरसंचार सेवा देने वाली चाइना मोबाइल, हुआवेई और ZTE कंपनियां 6G तकनीक का शुरुआती प्रयोग कर रही हैं और 2023 के बाद से कई चीनी और विदेशी दूरसंचार व स्मार्टफोन कंपनियों ने देश के 6G प्रयोगों और उसके तकनीकी पहलुओं को लेकर परीक्षण किए हैं। कुल मिलाकर, चीन 6G में अगुवा देश के रूप में उभरता हुआ दिखाई दे रहा है।

ब्रिटेन के 'द टेलीग्राफ' ने हाल ही में एक लेख में लिखा कि 'केवल अमेरिकी नेतृत्व ही चीन के 6G दबदबे वाली इस आपदा को रोक सकता है'। दरअसल, 5G के उदय के समय अमेरिका पिछड़ता हुआ और सुस्त पड़ता दिखा था। नए दूरसंचार युद्ध में वह वही गलतियां दोहराना नहीं चाहता। अमेरिका का प्रमुख 6G कार्यक्रम 'नेक्स्ट G अलायंस' अलायंस फॉर टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री सॉल्यूशंस (ATIS) के नेतृत्व में चल रहा है। ATIS, जिसके सदस्यों में एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, एटीऐंडटी और क्वालकॉम जैसी तकनीकी दिग्गज कंपनियां शामिल हैं, 6G के लिए एक कार्य-योजना लागू कर रही है, जिसमें नेटवर्क की विश्वसनीयता, वैश्विक प्रतिस्पर्धा और टिकाऊपन पर ज़ोर दिया जा रहा

है। इसके साथ ही, अमेरिकी रक्षा विभाग 6G अनुसंधान और विकास कार्यक्रम चला रहा है, जिसके माध्यम से 6G के सैन्य उपायों और सुरक्षित 'एज कंप्यूटिंग' व युद्ध के मैदान में संचार जैसे दोहरे उपयोग वाले माध्यमों में निवेश किया जा रहा है।

यूरोपीय संघ (EU) भी अपनी 'होराइजन यूरोप इनीशिएटिव' के माध्यम से 6G में अनुसंधान और नवाचार (इनोवेशन) के लिए पर्याप्त आर्थिक मदद दे रहा है। नोकिया की सहायता से 6G अनुसंधान में चल रही 'हेक्सा-X' नाम की यूरोपीय पहल में 6G के लिए ढांचा, एआई-संचालित नेटवर्क और नए स्पेक्ट्रम के निर्माण के लिए 25 सहयोगी औद्योगिक कंपनियों को एक साथ जोड़ा गया है। फैक्टरी ऑटोमेशन और इंडस्ट्री 4.0 को आगे बढ़ाने पर '6G BRAINS' का ज़ोर है। 6G BRAINS यूरोपीय संघ की आर्थिक मदद से चलने वाला एक कार्यक्रम है, जो 6G में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेंसिंग को जोड़ने की दिशा में काम कर रहा है।

दुनिया के दूसरे हिस्से, यानी पूर्वी एशिया में जापान और दक्षिण कोरिया की 6G क्षमता भी तेज़ी से विकसित हो रही है। दोनों देश अनुसंधान व विकास के मज़बूत कार्यक्रम चला रहे हैं और प्रयोग भी कर रहे हैं।

## शांत प्रतियोगी

महाशक्तियों की आपसी होड़ से दूर, भारत भी 6G क्षेत्र में अग्रणी देश बनने की दिशा में लगातार काम कर रहा है। जैसा कि देश के संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं, 'यह हमारा विश्वास और हमारी प्रतिबद्धता है कि भारत, जिसने 4G में दुनिया का अनुसरण किया और 5G में साथ-साथ आगे बढ़ा, 6G में विश्व का नेतृत्व करेगा।'

हालांकि, अभी प्रगति का आकलन करना जल्दबाज़ी होगी, लेकिन भारत अपने 6G पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सक्रियता से बुनियाद तैयार कर रहा है। इसके लिए दूरदर्शी नीतियां तो बनाई ही गई हैं, उसके अनुसार रणनीतिक निवेश भी जुटाए जा रहे हैं। सरकार, शिक्षाविदों व उद्योग के बीच साझेदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

मार्च 2023 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'भारत 6G विज़न डॉक्यूमेंट' जारी किया था, जो 6G विकास का एक रोडमैप है और 6G के तीन सिद्धांतों- सामर्थ्य, स्थिरता और सर्वव्यापकता पर ज़ोर देता है। विज़न डॉक्यूमेंट में बहु-हितधारकवाद (इस तकनीक से प्रभावित होने वाले सभी समूहों, लोगों अथवा संगठनों के बीच सहयोग करके फ़ैसले लेना) पर ज़ोर दिया गया है। इसे 6G पर एक नवाचार समूह TIG-6G ने तैयार किया है, जिसमें मंत्रालयों, शोध संस्थानों, मानकीकरण निकायों, दूरसंचार सेवा देने वालों और तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल थे। इस विज़न का मुख्य मक़सद यह सुनिश्चित करना है कि भारत न केवल 6G तकनीक विकसित करें, बल्कि इसकी तरक़्क़ी में प्रमुख योगदान देने वाला देश भी बने। इसके साथ-साथ भारत ने उभरती हुई 6G तकनीक के परीक्षण और सत्यापन के लिए शिक्षाविदों, उद्योगपतियों और स्टार्टअप के लिए एक मंच के रूप में '6G R&D टेस्ट बेड' भी लॉन्च किया है। इससे 6G नवाचार, क्षमता निर्माण और इसे तेज़ी से अपनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

बहु-हितधारक सोच को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 'भारत 6G अलायंस' (B6GA) का भी गठन किया है, जिसके सदस्य 6G तकनीक के डिजाइन और उसके इस्तेमाल को लेकर काम कर रहे हैं, जो न सिर्फ़ सस्ता होगा,

बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों जैसा भी होगा। मानकों को एक समान बनाने के इस अभियान में 6G पर 100 से अधिक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय शोध प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है और B6GA ने यूरोप के '6G स्मार्ट नेटवर्क्स ऐंड सर्विसेज इंडस्ट्री एसोसिएशन' (6G-IA) के साथ एक समझौता-पत्र (MoU) पर भी हस्ताक्षर किया है, ताकि आपस में मिलकर प्रोजेक्ट किए जा सकें, ज्ञान के आदान-प्रदान वाले कार्यक्रम चलाए जा सके और मानकों को तैयार किया जा सके।

इसके अलावा, 100 समर्पित सहायक प्रयोगशालाओं की स्थापना और विदेशी तकनीकी कंपनियों की शोध सुविधाओं को आकर्षित करके उच्च-स्तरीय 6G अनुसंधान और विकास पर ध्यान दिया जा रहा है। भारत वैश्विक 6G पेटेंट पुल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने पर भी काम कर रहा है। अभी भारत के पास 6G से जुड़े 200 से अधिक पेटेंट हैं और सरकार का लक्ष्य 2030 तक कुल वैश्विक 6G पेटेंट में कम से कम 10 प्रतिशत पेटेंट हासिल करना है।

## निष्कर्ष

6G की यह रेस समय-पूर्व की महत्वाकांक्षा नहीं है, बल्कि यह एक रणनीतिक ज़रूरत है। हालांकि, इस दौड़ में ऐसा नहीं होना चाहिए कि तकनीक रूप से विकसित शक्तियां एक-दूसरे को नुकसान पहुंचाकर अपना फ़ायदा कमाने की सोचें। चीन के अत्याधुनिक 6G प्रयोग और अमेरिका व यूरोपीय संघ के समर्पित कार्यक्रमों से लेकर पूर्वी एशिया के उच्च-प्रभाव वाले परीक्षण-प्रयोग और भारत के उभरते बाज़ार के आधार पर तेज़ विकास के प्रयास- यही बता रहे हैं कि कोई भी देश कनेक्टिविटी का भविष्य अकेले नहीं बना सकता।

साफ़ है, बहुपक्षीय निकायों और सदस्य देशों को अंतरराष्ट्रीय मानक बनाने, स्पेक्ट्रम तक एकसमान पहुंच पर सहमत होने और समावेशी शोध व विकास (R&D) के तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए आपस में मिलकर काम करना चाहिए। सार्वजनिक निवेश इस तरह किया जाना चाहिए कि कम समय वाले आर्थिक लाभों की तुलना में लंबे समय वाले नवाचार व क्षमता विकास को महत्व मिले। इतना ही नहीं, पूरी संवेदनशीलता के साथ नीतियां बनानी चाहिए और निजता, साइबर सुरक्षा, नैतिकता, पर्यावरणीय प्रभाव और पुरानी पीढ़ी के नेटवर्क के साथ ताल-मेल से जुड़ी चिंताओं का समाधान तलाशना चाहिए।

6G युग में लोगों की मांग इंटरनेट की गति और पैमाने तक नहीं होगी, बल्कि इससे भी अधिक की होगी, जिसके लिए दूरदर्शिता और ज़िम्मेदारी की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे में, 'विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस' (WTISD) सरकारों, व्यवसायों और अन्य लोगों को यह याद दिलाने का उचित अवसर है कि हमें 'जीतने' से आगे सोचना चाहिए और सहयोग के नए रास्ते तलाशने चाहिए।

---

**(अनिर्बान सरमा ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में सेंटर फॉर डिजिटल सोसाइटीज के निदेशक हैं और ये लेख राष्ट्र, नेटवर्क और नैरेटिव: विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 2025 श्रृंखला का हिस्सा है।)**

# बांग्लादेश में स्टारलिंक
# जुआ या ज़रूरत?

चैतन्य गिरि

**बांग्लादेश की सरकार ने जल्दबाज़ी में स्टारलिंक की सेवाओं को शुरू करके, पहले से ही गरीबी से पीड़ित इस क्षेत्र में सैटेलाइट-संचालित संघर्ष की आशंका बढ़ा दी है.**

अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश ने स्टारलिंक की शुरुआत के लिए मज़बूत कदम उठाए हैं। 20 मई, 2025 को बांग्लादेश के डाक और दूरसंचार मंत्रालय में विशेष सहायक (राज्य मंत्री के बराबर का पद) फ़ैज़ अहमद तैयब ने देश में स्टारलिंक के लॉन्च की घोषणा की। इसके दो सेवा-पैकेज शुरू किए गए हैं- एक, स्टारलिंक रेजिडेंस, जो मासिक 6,000 बांग्लादेशी टका (लगभग 4,200 रुपये) में उपलब्ध है, और दूसरा, स्टारलिंक रेजिडेंस लाइट, जिसके लिए हर महीने 4,200 टका (क़रीब 3,000 रुपये) चुकाने होंगे। स्टारलिंक सेट-अप उपकरण लगवाने के लिए 47,000 टका (लगभग 38,000 रुपये) का ख़र्च भी एक दफ़ा करना होगा। साफ़ है, ये इंटरनेट सेवाएं काफ़ी महंगी हैं और बांग्लादेश की सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों से मेल नहीं खा रहीं।

उल्लेखनीय है कि इंटरनेट सेवाओं पर दुनिया में सबसे अधिक कर बांग्लादेश में ही वसूला जाता है। भारत के उलट, जहां दूरसंचार सेवाओं पर 18 प्रतिशत टैक्स चुकाना पड़ता है, बांग्लादेश की हुकूमत 18 प्रतिशत वैट (मूल्य वर्धिक कर) और फिर, दूरसंचार क्षेत्र का 21 प्रतिशत कर लगाती है। कॉरपोरेट टैक्स के मामले में, दूरसंचार सेवा देने वाली सार्वजनिक कंपनियों पर 40 प्रतिशत का टैक्स लगाया जाता है, जबकि गैर-सार्वजनिक कारोबार करने वाली कंपनियों को 45 प्रतिशत का भारी कर चुकाना पड़ता है। राजस्व में भारी कमी से बांग्लादेश का दूरसंचार क्षेत्र लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। 2015 से बांग्लादेश के दूरसंचार क्षेत्र की कंपनियों को प्रत्येक ग्राहक से औसतन 56 प्रतिशत

# भारत में स्टारलिंक

## प्रगति या खतरा?

भारत और स्टारलिंक के बीच समझौता दूरदराज के क्षेत्रों तक परिवर्तनकारी इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने और शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देने का वादा करता है। हालाँकि, एक विदेशी निजी इकाई को भारत के डिजिटल बुनियादी ढांचे तक व्यापक पहुंच प्रदान करना डेटा गोपनीयता, साइबर संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाता है। सरकार द्वारा शर्तें निर्धारित किए जाने के बावजूद, उनका कड़ाई से पालन सर्वोपरि है।

भारतनेट और बीएसएनएल जैसी स्वदेशी डिजिटल अवसंरचना परियोजनाओं का भविष्य भी अधर में लटका हुआ है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि तकनीकी प्रगति से डिजिटल निर्भरता न बढ़े और स्थानीय उद्यम हाशिए पर न चले जाएं।

जबकि स्टारलिंक डिजिटल सशक्तिकरण की क्षमता प्रदान करता है, भारत को अपनी संप्रभुता और रणनीतिक स्वायत्तता को प्राथमिकता देनी चाहिए। प्रगति की खोज अनजाने में तकनीकी-औपनिवेशवाद के एक नए रूप का मार्ग प्रशस्त नहीं करनी चाहिए। भारत के हितों की रक्षा करने वाली मजबूत नीतियां इस डिजिटल सीमांत पर जिम्मेदारी से नेविगेट करने के लिए आवश्यक हैं।

20 मई, 2025 को बांग्लादेश के डाक और दूरसंचार मंत्रालय में विशेष सहायक (राज्य मंत्री के बराबर का पद) फ़ैज़ अहमद तैयब ने देश में स्टारलिंक के लॉन्च की घोषणा की।

राजस्व घाटा हुआ है। अभी यहां प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU) सिर्फ़ 1.3 अमेरिकी डॉलर है, जो दुनिया में सबसे कम है। इतना ही नहीं, वहां 44 प्रतिशत आबादी तक ही इंटरनेट की पहुंच है, इसलिए बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था में दूरसंचार क्षेत्र का योगदान आज भी बहुत कम है।

## गरीब समाज

बांग्लादेश का सामाजिक-आर्थिक संकेतक भी काफ़ी चिंताजनक है। विश्व बैंक के बांग्लादेश डेवलपमेंट अपडेट में बताया गया है कि 2024 में वहां 7.7 प्रतिशत लोग अत्यधिक गरीब थे, जो 2025 में बढ़कर 9.3 प्रतिशत हो गए हैं। विश्व बैंक ने यह भी भविष्यवाणी की है कि राष्ट्रीय गरीबी दर 2024 की 20.5 प्रतिशत की तुलना में 2025 में बढ़कर 22.9 प्रतिशत हो जाएगी। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के गरीबी संकेतकों के मुताबिक, यदि कोई परिवार बुनियादी ज़रूरतों पर हर माह 3,822 टका ख़र्च नहीं कर सकता, तो उसे गरीब माना जाएगा। ऐसे में, स्टारलिंक रेजिडेंस लाइट सेवा बांग्लादेश की लगभग एक चौथाई आबादी की क्षमता से अधिक महंगी है। बांग्लादेशी बाज़ार की मांगों और वहां की सामाजिक-आर्थिक सच्चाई को देखें, तो इतनी महंगी क़ीमतों पर स्टारलिंक का

स्टारलिंक रेजिडेंस, जो मासिक 6,000 बांग्लादेशी टका (लगभग 4,200 रुपये) में उपलब्ध है, और दूसरा, स्टारलिंक रेजिडेंस लाइट, जिसके लिए हर महीने 4,200 टका (क़रीब 3,000 रुपये) चुकाने होंगे। स्टारलिंक सेट-अप उपकरण लगवाने के लिए 47,000 टका (लगभग 38,000 रुपये) का ख़र्च भी एक दफ़ा करना होगा। साफ़ है, ये इंटरनेट सेवाएं काफ़ी महंगी हैं और बांग्लादेश की सामाजिक और आर्थिक सच्चाइयों से मेल नहीं खा रहीं।

यहां आना तार्किक नहीं लगता। अंतरिम सरकार ने अमेरिकी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपग्रह संचार (सैटकॉम) इंटरनेट सेवाओं को तेज़ी से शुरू किया है और इसके लिए बाज़ार और सामाजिक-आर्थिक कारकों पर गौर भी नहीं किया गया है।

यूनुस दूरसंचार क्षेत्र की सच्चाइयों से अनजान नहीं हैं। वह ग्रामीणफोन के संस्थापक हैं, जो बांग्लादेश में दूरसंचार सेवा देने वाली कंपनी है। इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी और इसमें नॉर्वे की सेवा कंपनी टेलीनॉर की बड़ी हिस्सेदारी रही है। पिछले तीन-चार वर्षों में ग्रामीणफोन का कारोबार कम हुआ है, जिसका मुख्य कारण बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग (BTRC) द्वारा, ख़ास तौर से हसीना सरकार के दौरान की गई कार्रवाइयां हैं। 2022 में आयोग ने ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं देने में विफल रहने की बात कहकर ग्रामीणफोन को पुराने और नए, दोनों तरह के सीम बेचने से रोक लगा दिया था। यूनुस के खिलाफ हसीना सरकार की आखिरी कार्रवाई ग्रामीणफोन से ही जुड़ी थी, जहां उन पर कंपनी से कथित तौर पर 20 लाख अमेरिकी डॉलर के गबन का आरोप लगाया गया था। BTRC की जांच तब सही जान पड़ी, जब ग्रामीणफोन ने 2025 की पहली तिमाही में शुद्ध लाभ में 53 प्रतिशत का घाटा बताया। मोबाइल और इंटरनेट उपयोग में लगातार हो रही गिरावट को देखते हुए ग्रामीणफोन ने अपने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का फ़ायदा उठाते हुए मई, 2025 में मोबाइल हैंडसेट बेचने का कारोबार शुरू करने फ़ैसला किया। अब यह विशेष रूप से शेन्जेन की कंपनी ट्रांसशन होल्डिंग्स के मोबाइल हैंडसेट बेचती है। ग्रामीणफोन के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का इसी तरह का उपयोग बांग्लादेश में महंगे स्टारलिंक उपयोगकर्ता टर्मिनलों को बेचने में किया जा सकता है।

## सूचना युद्ध

7 अप्रैल, 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लिखे अपने पत्र में, यूनुस ने 'परीक्षण से जुड़ी कुछ ज़रूरतों को ख़त्म करने; पैकेजिंग, लेबलिंग और प्रमाणन ज़रूरतों को तार्किक बनाने और सीमा शुल्क प्रक्रियाओं व मानकों को आसान बनाने' का आश्वासन दिया था। क्या BTRC ने बांग्लादेश और अपने पड़ोस की दूरसंचार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन उपकरणों का परीक्षण किया है या प्रमाण-पत्र दिया है? यह अब तक पता नहीं चल सका है। यह आश्वासन 'फरवरी, 2025 से 90 दिनों के भीतर बांग्लादेश में स्टारलिंक के प्रवेश को आसान बनाने के लिए' दिया गया था। इस आश्वासन का सम्मान किया गया है और बांग्लादेशी उद्योग पर पहले से मंडरा रहे टैरिफ ख़तरे को सफलतापूर्वक टाल दिया गया है। यह देखते हुए कि अंतरिम सरकार आतंकवादी गुटों के प्रति नरम रही है, लेकिन अपने राजनीतिक विरोधियों के प्रति नहीं, बांग्लादेश में स्टारलिंक सेवाएं निश्चय ही देश के भीतर और पूरे क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियां पैदा करेंगी। दिसंबर, 2024 में मणिपुर में ज़ब्त किया गया स्टारलिंक टर्मिनल सिलहट में सक्रिय रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (RPF) और उसकी सशस्त्र इकाई पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का था। यदि यह ट्रर्मिनल बांग्लादेश में रखे गए टर्मिनलों में से तस्करी कर लाया गया है, तो स्टारलिंक सेवाओं के शुरू होने से इन टर्मिनलों तक भी सिग्नल पहुंचने लगेगा और ये काम करने लगेंगे। इससे पड़ोसी देशों के सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकी समूहों की कार्रवाइयों में इनका उपयोग शुरू हो जाएगा। बांग्लादेश में स्टारलिंक की आधिकारिक शुरुआत और म्यांमार के विद्रोहियों द्वारा इसका उपयोग करने से पद्मा-इरावदी नदी घाटियों में अमेरिका और चीन समर्थित गुटों का संघर्ष सूचनाओं के स्तर पर लड़ा जाने लगेगा, जो शायद दुनिया का पहला सूचना युद्ध होगा, जिसमें सैटेलाइट-संचालित सेवाओं का उपयोग होगा। स्टारलिंक सुंदरबन के दलदलों और चटगांव के पहाड़ी जंगलों में डिजिटल कनेक्टिविटी ज़रूर बढ़ाएगा, लेकिन इस कनेक्टिविटी का असीमित इस्तेमाल आतंकवादी समूह और राष्ट्र समर्थित गुट ही करेंगे।

**(चैतन्य गिरि ऑब्ज़र्वर रिसर्च फाउंडेशन के सुरक्षा, रणनीति और प्रौद्योगिकी केंद्र में फेलो हैं)**

# PFI

## क्या दोबारा खड़ा हो रहा है?

कंचन लक्ष्मण

मार्च 2024 में एसडीपीआई प्रमुख एमके फैज़ी की गिरफ्तारी ने प्रतिबंधित पीएफआई से जुड़े कथित वित्तीय नेटवर्क और उभरते राजनीतिक मोर्चों की जटिलता को उजागर किया, जो सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता का केंद्र बन चुका है।

फाइल फोटो

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के तहत प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस साल मार्च की शुरुआत में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एमके फैज़ी को गिरफ्तार किया। एमके फैज़ी पर पैसे की धोखाधड़ी का आरोप है। ये केस मुख्य रूप से प्रतिबंधित संगठन पीपुल्स फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़ा है। एसडीपीआई को पीएफआई का राजनीतिक अंग माना जाता है। फैज़ी 2009 तक पीएफआई का सदस्य था और उसी साल फैज़ी को एसडीपीआई में महासचिव बनाया गया था। 2018 से ही वो एसडीपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पीएफआई और गर्भनाल से एक-दूसरे से जुड़े हुए है। एसडीपीआई को पीएफआई का सिर्फ राजनीतिक मोर्चा ही नहीं माना जाता, बल्कि वो उसका संगठनात्मक माध्यम के रूप में भी काम करता है। ये काम है कट्टरपंथी इस्लामिक गतिविधियों का प्रसार का। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने से पहले उसके कार्यकर्ता ये काम करते थे।

प्रवर्तन निदेशालय ने संकेत दिया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, फैज़ी ने एसडीपीआई की गतिविधियों पर अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। देश और विदेश से पीएफआई द्वारा बड़ी आपराधिक साज़िशों के लिए जो रकम जमा की गई थी, उसका गलत उपयोग किया। फैज़ी ने ना सिर्फ इस रकम को हासिल किया, बल्कि वो उसका लाभकर्ता भी

था। ये आय अपराध के लिए जुटाई गई थी। ईडी के मुताबित फैज़ी को ये बात पूरी तरह से पता था कि पीएफआई का पैसा ऐसी आपराधिक साज़िश के लिए आया है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। इस रकम का इस्तेमाल भारत में अलग-अलग अवैध कामों, हिंसा भड़काने और आतंकी गतिविधियों में किया जाना था। इस सिलसिले में ईडी द्वारा अब तक 4।04 करोड़ रुपये का आंकलन किया गया है, जिसका उपयोग आपराधिक गतिविधियों के लिए होना था। फैज़ी की गिरफ्तारी के बाद, ईडी ने पीएफआई के खिलाफ मामले के संबंध में 10 राज्यों में 12 ठिकानों पर छापे मारे। ईडी की जांच में ये पाया गया कि इस संगठन ने मई 2009 से मई 2022 के बीच 29 खातों में 62 करोड़ रुपये से ज़्यादा की रकम प्राप्त की। इसमें से आधे से अधिक राशि नकद में जमा की गई थी। इस संगठन के खाड़ी देशों में हजारों सक्रिय सदस्य थे, जिनके माध्यम से इसने ये महत्वपूर्ण धन राशि जुटाई।

अब तक की जांच से ये स्पष्ट रूप से साबित हो गया है कि पीएफआई ने एसडीपीआई की गतिविधियों को नियंत्रित किया, उसे फंड दिया और उसके काम की निगरानी भी की। एसडीपीआई चूंकि पीएफआई का ही राजनीतिक क मोर्चा है, इसलिए इनके नेता और कैडर समान हैं। एसडीपीआई अपनी रोज़ाना के काम, नीति निर्माण, चुनावी अभियानों के लिए उम्मीदवारों का चयन, सार्वजनिक कार्यक्रमों, कैडर समारोह और अन्य संबंधित गतिविधियों के लिए पीएफआई पर निर्भर था। जांच एजेंसियों के अनुसार प्रतिबंध के बाद पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ता अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए एसडीपीआई में जा रहे हैं।

फाइल फोटो

पीएफआई पर प्रतिबंध के बाद, एसडीपीआई अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस बात से संकेत मिल रहे हैं कि ये प्रतिबंधित संगठन अब एसडीपीआई और अपने अन्य अनुषांगिक संगठनों के बैनर तले फिर पुनर्गठित होने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से देखा जाए तो एसडीपीआई की गतिविधियों में कोई भी वृद्धि पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाएगी।

## एसडीपीआई की बढ़ती गतिविधियां

हाल ही में एसडीपीआई की गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है, विशेष रूप से दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र में। जांच एजेंसियों के मुताबिक एसडीपीआई ने पीएफआई के पूर्व सदस्यों को काम में लगाने के लिए एक नई युवा शाखा शुरू की है। एसडीपीआई और इसके सहयोगियों ने कथित तौर पर अपने प्रभाव को बढ़ाने और नए सदस्यों को भर्ती के लिए 'फिलिस्तीन मुद्दे' को भावनात्मक तौर पर उछाला है। इतना ही नहीं पिछले कुछ हफ्तों में, एसडीपीआई ने वक्फ़ संशोधन अधिनियम के खिलाफ़ समर्थन जुटाने के लिए भी सक्रियता दिखाई है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वक्फ़ संशोधन बिल के खिलाफ़ एसडीपीआई के मज़बूत विरोध के बाद ही ईडी ने इस सगंठन पर नए सिरे से कार्रवाई की है।

एसडीपीआई अपने सदस्यता अभियान को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है। 10 से अधिक राज्यों में इसका असर देखा गया है। एसडीपीआई की नई युवा शाखा धीरे-धीरे मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में भी अपनी यूनिट बना रही है। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में तो ये पहले से ही मज़बूत है। माना जा रहा है कि एसडीपीआई

एसडीपीआई अपने सदस्यता अभियान को बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है. वो ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है. 10 से अधिक राज्यों में इसका असर देखा गया है.

की ये नई युवा शाखा एक खास रणनीति का हिस्सा है। इसके ज़रिए पूर्व पीएफआई कैडर को अपनी कट्टरपंथी गतिविधियों को जारी रखने का मौका मिल रहा है।

हालांकि हाल के चुनावों में एसडीपीआई का प्रदर्शन काफ़ी खराब रहा है। इसके बावजूद वो आगामी चुनावों में मुकाबला करने के लिए अपने समर्थक आधार को मज़बूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है। चुनाव में जीत है एसडीपीआई के लिए अपनी विचारधारा का प्रचार करने और वैधता प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण रास्ता है। अगस्त 2024 में आयोजित एसडीपीआई राष्ट्रीय समिति की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। संगठन ने ये तय किया है कि अगले 10 साल की अवधि के लिए आगामी विधानसभाओं के लिए उनके चुनावी अभियान की शुरुआत की जाएगी। एक महत्वाकांक्षी योजना में, एसडीपीआई ने देश भर के हर जिले में कम से कम एक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र चुनने का निर्णय लिया है, जिससे वहां अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा जा सके। केरल में एसडीपीआई अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। यही वजह है कि एसडीपीआई राज्य समिति ने केरल विधानसभा

फाइल फोटो

चुनावों के लिए हर जिले से तीन ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों का चयन करने का फैसला किया है। इसके लिए जिला समितियों से कहा गया है कि 2031 के विधानसभा चुनाव के लिए वो ऐसा निर्वाचन क्षेत्रों की पहचान कर लें। हालांकि केरल में अगले विधानसभा चुनाव 2026 में हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एसडीपीआई ने अभी तक कोई खास सफलता हासिल नहीं की है। ऐसे में एसडीपीआई फिलहाल स्थानीय निकायों में अपने सदस्यों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वर्तमान में, एसडीपीआई के पास पूरे देश में स्थानीय निकाय में 103 निर्वाचित सदस्य हैं।

## पीएफआई की सामने मौजूद कानूनी चुनौतियां

एक तरफ जहां पीएफआई उस पर लगे प्रतिबंध को कानूनी रूप से चुनौती देने में लगी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बैन लगने के बाद

गिरफ्तार किए गए उसके कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को ज़मानत भी मिली है। उदाहरण के लिए, बॉम्बे हाईकोर्ट ने 28 मार्च को शेख सादिक इसाक कुरैशी नाम के वकील को ज़मानत दे दी। शेख सादिक को एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) ने प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके अलावा, केरल हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को पीएफआई के 10 आरोपी सदस्यों को ज़मानत दी। इन सभी आरोपियों पर 2022 में केरल के पलक्कड़ जिले में आरएसएस नेता श्रीनिवासन की हत्या का आरोप था। कुल मिलाकर देखा जाए तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) द्वारा दाख़िल 19 मामलों में गिरफ्तार किए 500 पीएफआई कैडरों में से आधे से अधिक को ज़मानत मिल चुकी है। जिन आरोपियों को ज़मानत मिलने में सफलता मिली है, उनमें से ज़्यादातर कर्नाटक और तमिलनाडु के हैं। इन आरोपियों को मिली ज़मानत ने दूसरे राज्यों में बंद कैदियों के लिए उम्मीदें पैदा की हैं। पीएफआई का जो बचा-खुचा नेतृत्व है, उनके लिए भी ये अच्छी खबर है। ज़मानत के इन आदेशों को वो दूसरे राज्यों में मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं। ज़मानत मिलने की उम्मीद कर सकते हैं। डिजिटल सबूतों के अभाव में अदालतों में ये साबित करना मुश्किल हो रहा है कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, वो पीएफआई के सदस्य हैं।

## पीएफआई का पुनर्गठन

पीएफआई पर 28 सितंबर 2022 को प्रतिबंध लगा था। इस हिसाब से देखें तो पीएफआई पर पाबंदी को ढाई साल से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। अब इस तरह के संकेत मिल रहे हैं कि इस संगठन को सावधानीपूर्वक दोबारा ज़िंदा किया जा रहा है। पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ता और बचे हुए नेतृत्व के लोग शुरुआती निष्क्रियता के बाद धीरे-धीरे पुनर्गठित हो रहे हैं। ये लोग एसडीपीआई के बैनर के तहत या फिर दूसरे कई सहायक संगठनों के अधीन फिर काम शुरू कर रहे हैं। इन संगठनों में से ज्यादातर का दक्षिणी राज्यों में आधार है। पीएफआई के कुछ कार्यकर्ता अन्य कट्टर इस्लामी संगठनों में शामिल हो गए हैं, जिनमें वहदत-ए-इस्लामी (वीईएल) भी शामिल है। ये संगठन भी प्रतिबंधित ग्रुप स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (एसआईएमआई) यानी सिमी का एक मोर्चा है।

चूंकि प्रतिबंध लगे होने के वजह से ये संगठन व्यवस्थित तौर पर अपनी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकते। ऐसे में जो खुफिया सूचनाएं आ रही हैं, उसके मुताबिक एसएफआई की पूर्व कार्यकर्ता मस्जिदों, सामाजिक समारोहों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के ज़रिए फिर एक साथ जुड़ रहे हैं। केरल और जिन दूसरे राज्यों में इस समूह की उपस्थिति है, वहां पीएफआई के पूर्व कार्यकर्ताओं ने संगठन का नुकसान रोकने और कमज़ोर युवाओं की भर्ती करने के लिए नए संगठन बनाए हैं। ये समझा जाता है कि पीएफआई की रणनीति असंगठित संरचना बनाए रखना है क्योंकि सभी राज्यों में एक ही नाम वाला नया संगठन बनाने से सुरक्षा एजेंसियों को शक हो सकता है और वो कार्रवाई कर सकती है। अलग-अलग नामों से तहत नए संगठन बनाने की रणनीति पहले पीएफआई की पूर्ववर्ती संस्था सिमी ने तब अपनाई गई थी, जब उसे सितंबर 2001 में प्रतिबंधित किया गया था।

पीएफआई के पुराने सदस्यों ने सीमित स्तर पर अपनी गतिविधियां फिर शुरू कर दी हैं। रणनीति बनाने के लिए गुप्त बैठकें आयोजित की जाने लगी हैं। संगठन पर प्रतिबंध लगने के बाद से पीएफआई के नेता और सदस्य सामाजिक-राजनीतिक गतिविधियों और कल्याण कार्यों में शामिल होते रहे, जिससे वो सार्वजनिक क्षेत्र में लगातार अपनी उपस्थिति दिखा सकें। हालांकि पीएफआई पर बैन के बाद से उसकी फंडिंग पर बुरा प्रभाव पड़ा। आर्थिक मदद मिलनी कम हुई लेकिन खाड़ी क्षेत्र में स्थित अपने दूसरे संगठनों के माध्यम से धन जुटाने की कोशिशें जारी हैं। साइबर स्पेस में पीएफआई के पूर्व सदस्य संचार और विचारधारा के प्रचार के लिए वैकल्पिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं।

पुलिस से प्राप्त सूत्रों के मुताबिक केरल में पीएफआई के गढ़ में वैकल्पिक नेतृत्व धीरे-धीरे उभर सकता है। केरल पीएफआई की गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। पीएफआई ने खुद को ज़िंदा रखने के लिए यहां कई मोर्चों और संगठनों का गठन किया है। पीएफआई के पुराने नेता मस्जिद समितियों और मदरसों के कार्यकर्ताओं के साथ

**भारत के बाहर पीएफआई-एसडीपीआई और इससे जुड़े संगठन खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद से ये अपनी गतिविधियां गुप्त स्तर पर चला रहा है।**

संबंध स्थापित कर रहे हैं, जिससे उनका समर्थन हासिल किया जा सके। केरल में पीएफआई के पूर्व कैडरों से जुड़े सोशल मीडिया समूह अपनी विचारधारा का प्रचार जारी रखे हुए हैं।

केरल के बाद, पश्चिम बंगाल धीरे-धीरे पीएफआई की गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है, विशेषकर मुर्शिदाबाद जिले में, जहां एक बड़ी संख्या में इस संगठन के कार्यकर्ता हैं। ये कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में, स्थानीय परिस्थितियों के कारण पीएफआई की गतिविधियां तेज़ हो रही हैं।

संगठन की उपस्थिति मज़बूत हो रही है। इस जगह की डेमोग्राफी का इस काम में काफ़ी मदद कर रही है। तमिलनाडु में, पूर्व पीएफआई कार्यकर्ता कोयम्बटूर, सलेम, ईरोड, थेनी, रामनाथपुरम, मदुरै और तिरुनेलवेली जिलों के कुछ हिस्सों में फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे हैं। असम में पीएफआई का पुराना कैडर, युवाओं को इज़राइल जैसी एक बड़ी शक्ति को चुनौती देने वाले हमास मिलिशिया के उदाहरण से प्रेरित करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के बाहर पीएफआई-एसडीपीआई और इससे जुड़े संगठन खुलकर सामने नहीं आ रही हैं। पीएफआई पर प्रतिबंध लगने के बाद से ये अपनी गतिविधियां गुप्त स्तर पर चला रहा है। हालांकि, नए बैनरों के तहत फिर से संगठित होने, अपनी विचारधारा का प्रचार करने और भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की कोशिश लगातार जारी है।

## पीएफआई को लेकर भविष्यवाणी

पीएफआई पर प्रतिबंध लगाए जाने को ढाई साल से ज्यादा बीत चुका है। ऐसे में ये संगठन अब धीरे-धीरे और बहुत सावधानी से पुनर्जीवित हो रहा है। पीएफआई के कई पुराने कैडर अपनी चरमपंथी गतिविधियों को जारी रखने के लिए एसडीपीआई और अन्य मोर्चों में शामिल हो गए हैं। पीएफआई के कुछ सदस्यों को ज़मानत मिलने के बाद धीरे-धीरे इस पर लगा प्रतिबंध कमज़ोर हो सकता है। पीएफआई की गतिविधियों को दोबारा ज़िंदा करने में खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय मुस्लिम

प्रवासी समुदाय की अहम भूमिका होगी। पीएफआई के मज़बूत होने से इस समुदाय में सलाफीवाद का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पीएफआई इस वक्त जिस गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रहा है, उसे ख़त्म करने में भी खाड़ी क्षेत्र में रहने वाले भारतीय मुसलमान मदद कर सकते हैं। को धन जुटाने में मदद कर सकता है। पीएफआई-एसडीपीआई दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल में खुद को मज़बूत करने के मौके तलाशेगा। हालांकि, अगर एजेंसियों द्वारा सख्त कार्रवाई की जाती हैं, विशेष रूप से SDPI के खिलाफ, तो शायद इसके पुनर्गठन को कमज़ोर किया जा सकता है।

**कंचन लक्ष्मण एक सुरक्षा विश्लेषक हैं। आतंकवाद, कट्टरता, वामपंथी उग्रवाद और आंतरिक सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उनकी विशेषज्ञता है, उनका यह आलेख ओआरएफ में पहली बार प्रकाशित हुआ है।**

Tea
Your Tagline Here

Fresh Drink

# LEMON TEA

The Wonderful Taste Of Life

Order Now

www.lemonteaindia.in

# सीजफायर

# या मिसफायर

# सीजफायर या मिसफायर

'ऑपरेशन सिंदूर' न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन था, बल्कि यह वैश्विक हथियार बाजार के समीकरणों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। 7-10 मई, 2025 के बीच हुए इस 'लो-इंटेंसिव वार' में भारत ने पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए अमेरिकी, चीनी और तुर्की निर्मित हथियारों को प्रभावी ढंग से मात दी। इस 'लो-इंटेंसिव वार' का 'सीज़फायर' कराने का श्रेय लेने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की कोशिश कहीं 'मिसफायर' तो नहीं हो गया?

श्रीराजेश

हिंदी में एक कहावत है- 'गये छब्बे बनने, दूबे बन कर लौटे।' कूटनीति में भी अक्सर यह कहावत चरितार्थ होती रहती है, और यह कोई नई बात नहीं है। इस घटनाक्रम का विस्तृत विश्लेषण करने से पहले, एक नज़र पृष्ठभूमि पर डालना आवश्यक है। हाल ही में, भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में 'ऑपरेशन सिंदूर' लॉन्च किया और पाकिस्तान स्थित नौ आतंकी ठिकानों पर 7 मई, 2025 को हमला किया। पाकिस्तान ने इसे अपनी सार्वभौमिकता पर हमला माना और जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश की। यह 'कार्रवाई' की प्रक्रिया बढ़ी और चार दिनों तक चली। इस दौरान भारत के सटीक हमलों ने न केवल पाकिस्तान के 11 एयर बेस को ध्वस्त किया, बल्कि उसके जेएफ-17, एफ-16 सहित पांच लड़ाकू विमान मार गिराए। इसके अलावा, चीनी एयर डिफेंस सिस्टम एचक्यू-09 और अमेरिकी एडब्ल्यूएसीएस सिस्टम को भी निष्प्रभावी किया गया। भारतीय स्वदेशी वायुरक्षा प्रणाली 'आकाश' ने तुर्की के बायरख्तर टीबी 2 ड्रोन को और रूस से प्राप्त एस-400 ने पाकिस्तानी फाइटर जेट तथा शाहीन मिसाइलों को सरहद लांघने से पहले ही ध्वस्त कर दिया। इससे न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं

का प्रदर्शन हुआ, बल्कि वैश्विक हथियार बाजार और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति पर भी गहरा प्रभाव डाला। इस ऑपरेशन के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत-पाकिस्तान के बीच सीज़फायर की घोषणा और उसके बाद की बयानबाजी ने भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव उत्पन्न किया। एक तरह से कहा जाए तो ट्रम्प के लिए यह 'सीज़फायर' वास्तव में 'मिसफायर' कर गया।

ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण सामरिक जीत है लेकिन जीत का जश्न तो पाकिस्तान में मनते दुनिया ने देखा और मजे भी लिये। इस पूरे घटनाक्रम में न केवल पाकिस्तान के भीतर स्थित आतंकी ठिकानों को भारत ने सफलतापूर्वक निशाना बनाया, बल्कि पाकिस्तान की सैन्य क्षमताओं की कमजोरियों को भी उजागर किया। इस ऑपरेशन के दौरान, भारत ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं- चीनी हथियारों की पोल खोल दी। ऑपरेशन में, भारत ने चीन के जेएफ-17 थंडर लड़ाकू विमान और पीएल-15ई मिसाइलों को मार गिराया। यह चीन द्वारा निर्मित हथियारों की क्षमताओं पर एक बड़ा प्रश्नचिह्न लगाता है। यह घटना चीनी हथियार उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि यह उनके उपकरणों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर संदेह पैदा करता है। इससे उन देशों में भी चिंता बढ़ गई है जो वर्तमान में चीनी हथियारों पर निर्भर हैं या भविष्य में उन्हें खरीदने पर विचार कर रहे हैं। वहीं अमेरिकी वायु रक्षा प्रणालियों को बेअसर करते हुए भारत ने अमेरिका के एएन/टीपीएस-77 मल्टी-रोल रडार और वायु रक्षा प्रणालियों को भी निष्क्रिय कर दिया, जिससे अमेरिका की रक्षा तकनीक की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हुआ। एएन/टीपीएस-77 एक अत्याधुनिक रडार प्रणाली है जिसका उपयोग हवाई निगरानी और लक्ष्य पहचान के लिए किया जाता है। इस प्रणाली को निष्क्रिय करने की भारत की क्षमता अमेरिकी रक्षा उद्योग के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह दर्शाता है कि उनकी प्रणालियाँ अप्रभेद्य नहीं हैं। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान यूक्रेन ने बड़े पैमाने पर तुर्की के बायरख्तर ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम 'आकाश' के सामने तुर्की के बायरख्तर ड्रोन पानी भरते नजर आए और ड्रोन तकनीक में तुर्की की श्रेष्ठता का दावा कमजोर हो गया। यह तुर्की के रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि बायरख्तर टीबी2 ड्रोन उनके सबसे सफल निर्यात उत्पादों में से एक है। इस घटना से ड्रोन की बिक्री कम हो सकती है और तुर्की की रक्षा क्षमताओं पर सवाल उठने लगे हैं। इस ऑपरेशन में भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों का सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। भारत सरकार पिछले कुछ वर्षों से स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों का सफल उपयोग इस रणनीति की सफलता का प्रमाण है। भारत ने रूसी और फ्रांसीसी निर्मित हथियारों का भी प्रभावी ढंग से उपयोग किया, जो इन देशों के साथ भारत के रक्षा संबंधों को और मजबूत करता है। रूस और फ्रांस भारत के प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता हैं। ऑपरेशन सिंदूर में उनके हथियारों का सफल उपयोग भारत के साथ उनके रक्षा संबंधों को और मजबूत करेगा।

ऑपरेशन सिंदूर के बाद जे-10 फाइटर जेट बनाने वाली चीन की कंपनी एविक चेंगदू एयरक्राफ्ट के शेयर लगभग 11.50% गिर गए। वहीं, 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारतीय सेना द्वारा अमेरिकी हथियार प्रणालियों को निष्क्रिय करने की खबरें सामने आने के बाद 14 मई को लॉकहीड मार्टिन के शेयरों में लगभग 3% की गिरावट आई। हालांकि, कंपनी ने आकर स्पष्ट किया कि शेयरों की कीमत में गिरावट का कारण ऑपरेशन सिंदूर नहीं, बल्कि कंपनी के आंतरिक वित्तीय मुद्दों और प्रबंधन द्वारा की गई घोषणाओं के कारण हुई। इसलिए, शेयर मूल्य में गिरावट को सीधे तौर पर 'ऑपरेशन सिंदूर' से जोड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन कंपनी चाहे जो स्पष्टीकरण दे, ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव को दरकिनार नहीं किया जा सकता। यह घटनाक्रम दिखाता है कि सैन्य कार्रवाई का असर न केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित रहता है, बल्कि यह वैश्विक अर्थव्यवस्था और शेयर बाजारों को भी प्रभावित कर सकता है।

राष्ट्रपति ट्रम्प के 'मिसफायर' को समझने के लिए, पहले ऑपरेशन सिंदूर के बाद के वैश्विक हथियार बाजार में आ रहे महत्वपूर्ण बदलाव को देखना आवश्यक है- भारत ने अमेरिकी हथियारों की कमजोरियों को उजागर करके अमेरिका के वैश्विक हथियार बाजार में प्रभुत्व को चुनौती दी है। यह अमेरिका के रक्षा उद्योग के लिए एक वेक-अप कॉल है, क्योंकि यह दर्शाता है कि उनकी प्रणालियाँ अप्रभेद्य नहीं हैं। अमेरिका को अब यह सुनिश्चित करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी कि उनके हथियारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनी रहे। जबकि रूसी हथियारों ने इस ऑपरेशन में बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिससे उनकी विश्वसनीयता बनी हुई है। रूस- यूक्रेन युद्ध के दौरान रूसी हथियारों के प्रदर्शन पर कई सवाल उठे थे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने उनकी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करने में मदद की है। वहीं फ्रांस के हथियारों की प्रभावशीलता ने उन्हें वैश्विक बाजार में अधिक आकर्षक बना दिया है। फ्रांस पिछले कुछ वर्षों से अपने रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में फ्रांसीसी हथियार खास कर राफेल का सफल और सटीक उपयोग उनके प्रयासों को और बढ़ावा देगा। भारत ने अपने स्वदेशी हथियारों की क्षमताओं को साबित करके अन्य देशों को भी स्वदेशी हथियार विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित किया है। कई देश विदेशी हथियारों पर अपनी निर्भरता कम करने और स्वदेशी रक्षा उद्योग विकसित करने के लिए उत्सुक हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि यह संभव है।

चीनी हथियारों के विफल प्रदर्शन ने उनकी गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि चीन को लेकर यह आम धारणा रही है कि चीनी तकनीक 'कहीं का ईंट, कहीं का रोड़ा' इक्कट्ठा कर विकसित की गई तकनीक है, लिहाजा इसकी गुणवत्ता हमेशा से सवालों के घेरे में रहे हैं। हालांकि एक बात गौर करने वाली है कि तुर्की के बायरख्तर ड्रोन्स कम से कम यूक्रेन द्वारा आजमाया तो गया था, लेकिन चीन के हथियार का कहीं किसी युद्ध में इसका कोई परीक्षण नहीं हुआ था। ऐसे में चीनी हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठना लाजिमी है।

आलेख लिखे जाने तक, भारत-रूस के द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस के अलावा भारत के स्वदेशी डिफेंस सिस्टम आकाश तथा अन्य हथियार पिनाका की



मांग बड़ी तेजी से बढ़ी है। लगभग 20 से अधिक देशों ने इन हथियारों को खरीदने की रुचि दर्शाई है। यह भारत के लिए एक बड़ा अवसर है, क्योंकि यह अपने रक्षा उद्योग को बढ़ावा दे सकता है और हथियारों का एक प्रमुख निर्यातक बन सकता है।

यदि वैश्विक स्तर पर देखें, तो वर्तमान में वैश्विक हथियार व्यापार का वित्तीय मूल्य लगभग 111.6 बिलियन डॉलर से 138 बिलियन डॉलर के बीच अनुमानित है। यह आंकड़ा शीत युद्ध के बाद का उच्चतम स्तर है। प्रमुख हथियार निर्यातक देशों में अमेरिका (43%), फ्रांस (9.6%) और रूस (7.8%) शामिल हैं। वहीं, प्रमुख हथियार आयातक देशों में यूक्रेन और भारत शामिल हैं। भारत, फ्रांस से सबसे अधिक हथियार आयात करता है, जो फ्रांसीसी हथियार निर्यात का 28% है।

2014 से 2024 तक वैश्विक हथियार व्यापार के वित्तीय मूल्य में लगातार वृद्धि हुई है। 2024 में, यह मूल्य 111.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। यह वृद्धि यूक्रेन में संघर्ष और अन्य भू-राजनीतिक तनावों के कारण हुई है, जिसके चलते देशों ने अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए हथियारों की खरीद बढ़ा दी है।

पाकिस्तान के पास विभिन्न देशों से प्राप्त उन्नत हथियार प्रणालियाँ और वायु रक्षा प्रणालियाँ हैं, जिनमें से अधिकांश चीन से प्राप्त की हुई हैं। इनमें एचक्यू-9पी/एचक्यू-9बीई लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, एलवाई-80/एलवाई-80ईवी मध्यम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली, जेएप-17 थंडर लड़ाकू विमान, जे-10सी फाइटर जेट और पीएल-15 सीरिज की मिसाइलें शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान के पास तुर्की से प्राप्त बायरख्तर टीबी2 और एकिंकी ड्रोन्स भी हैं। अमेरिका से प्राप्त एएन/टीपीएस-77 मल्टी-रोल रडार और एफ-16 भी पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली का हिस्सा है।

ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया है कि इन हथियारों और वायु रक्षा प्रणालियों के बावजूद, पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। यह पाकिस्तान के रक्षा के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि यह दर्शाता है कि उनके हथियारों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार

# भारत की नई आतंकवाद विरोधी नीति

भारत की नई आतंकवाद विरोधी नीति तीन ठोस स्तंभों पर आधारित है, जो पारंपरिक रक्षात्मक रुख से आगे बढ़ते हुए एक आक्रामक, सक्रिय और आत्मनिर्भर रणनीति की ओर इशारा करती है। यह नीति भारत की सुरक्षा दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन को दर्शाती है, जहां आतंकवाद के विरुद्ध केवल प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि अग्रसक्रियता और निवारण को प्राथमिकता दी गई है।

## पहला स्तंभ: सटीक और निर्णायक कार्रवाई

नई नीति का पहला स्तंभ है – दृढ़ और लक्षित कार्रवाई की क्षमता। इसका उद्देश्य आतंकवाद के स्रोतों पर सीधा प्रहार करना और आतंकवादी सरगनाओं को लक्ष्य बनाना है। 6-7 मई, 2025 की रात ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपनी इस क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि पाकिस्तान अब भी अपने झूठ और इनकार की नीति पर कायम है – जैसा उसने 26/11 के बाद अजमल कसाब जैसे स्पष्ट प्रमाणों के बावजूद किया था – भारत ने स्पष्ट किया है कि वह अब केवल प्रतीक्षा नहीं करेगा, बल्कि हमला भी करेगा।

इस नीति के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रबल खुफिया नेटवर्क और उन्नत जांच कौशल अनिवार्य हैं। भारत अब उस दुश्मन से जूझ रहा है जो षड्यंत्रों, प्रचार अभियानों और अंतरराष्ट्रीय भ्रम फैलाने में माहिर है। पाकिस्तान की रणनीति, जिसमें वह बार-बार आतंकवाद को 'राजनीतिक हथियार' बताकर भारत पर ही दोषारोपण करता है, अब भारत की नज़र में अप्रासंगिक हो चुकी है।

## दूसरा स्तंभ: परमाणु ब्लैकमेल के आगे न झुकना

दूसरा स्तंभ भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत वह अब पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की धमकी से नहीं डरता। 1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद से लेकर 1999 के कारगिल युद्ध और 2016-2019 के सर्जिकल और हवाई हमलों तक, भारत ने बार-बार यह सिद्ध किया है कि वह परमाणु धमकियों के सामने भी पारंपरिक सैन्य

की आवश्यकता है।

ग्लोबल फायरपावर रैंकिंग के अनुसार, भारत चौथे और पाकिस्तान 12वें स्थान पर है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान की तुलना में लगभग नौ गुना अधिक है। 2025 में, भारत ने रक्षा क्षेत्र के लिए 6.8 लाख करोड़ आवंटित किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 2.12 लाख करोड़ आवंटित किए हैं। यह अंतर दोनों देशों की सैन्य क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण अंतर दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार ने अतिरिक्त 50 हजार करोड़ रुपये रक्षा तैयारियों को मजबूत बनाने के लिए आवंटित किया है। यह दर्शाता है कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा रणनीति में आत्मनिर्भरता के महत्व को उजागर किया है। भारत सरकार ने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत स्वदेशी हथियार उत्पादन को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया है। इसका उद्देश्य विदेशी हथियारों पर निर्भरता को कम करना और भारत को एक प्रमुख हथियार निर्यातक बनाना है।

भारत ने हाल के वर्षों में कई स्वदेशी हथियार प्रणालियों का विकास किया है, जिनमें ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस लड़ाकू विमान और अर्जुन टैंक शामिल हैं। इन हथियारों ने भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है और देश को बाहरी खतरों से निपटने में अधिक सक्षम बनाया है। अब यदि फिर से बात करें भारत-अमेरिका संबंधों की, तो अमेरिका, भारत के साथ व्यापार संतुलन को बनाए रखने के लिए भारत पर एफ-35 खरीदने का दबाव बना रहा है। हालांकि, भारत ने अभी तक इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है। वहीं, अपुष्ट खबरें तो यहां तक आ रही हैं कि अमेरिका के हाथ से यह डील फिसल सकती है और भारत रूस के एसयू-57 पर भी विचार कर रहा है। वैसे भी भारत, अमेरिका से हथियार खरीदने के साथ-साथ रूस और फ्रांस से भी हथियार खरीदता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उसकी रक्षा आपूर्ति विविध बनी रहे। रूस के साथ भारत के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और भारतीय बेड़े में शामिल हथियारों में सर्वाधिक हिस्सा रूसी हथियारों का है। रूस इस मामले में भारत का एक भरोसेमंद साथी रहा है।

जबकि, अमेरिका और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से सैन्य संबंध रहे हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य साजो-सामान से लैस करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, ऑपरेशन सिंदूर ने इन संबंधों पर सवाल खड़े किए हैं, क्योंकि भारत ने अमेरिकी हथियारों को मात देकर अपनी सैन्य श्रेष्ठता साबित की है। यह अमेरिका के लिए एक चुनौती है, क्योंकि उसे अब यह तय करना होगा कि वह भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अपने संबंधों को

कैसे संतुलित करता है।

ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है। इसने न केवल भारत की सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया, बल्कि वैश्विक हथियार बाजार में भारत की स्थिति को भी मजबूत किया है। भारत ने स्वदेशी हथियारों के विकास और रूसी और फ्रांसीसी हथियारों के प्रभावी उपयोग के माध्यम से अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाया है। इस ऑपरेशन ने पाकिस्तान की सैन्य कमजोरियों को उजागर किया है और चीन, अमेरिका और तुर्की जैसे देशों के हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं।

भविष्य में, भारत को स्वदेशी हथियार उत्पादन को बढ़ावा देने, रूसी और फ्रांसीसी रक्षा सहयोग को मजबूत करने और एक संतुलित रक्षा रणनीति बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि भारत बाहरी खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहे और वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरे। इसके अतिरिक्त, भारत को अपने साइबर सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने, अपनी खुफिया जानकारी एकत्र करने की क्षमताओं को बेहतर बनाने और अपने सशस्त्र बलों को आधुनिक बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए।

ट्रम्प के 'मिसफायर' की बात करें तो, यह स्पष्ट है कि उनकी बयानबाजी ने भारत-अमेरिका संबंधों में तनाव उत्पन्न किया है। हालांकि, यह संभावना नहीं है कि यह तनाव दीर्घकालिक होगा। भारत और अमेरिका के बीच कई साझा हित हैं, जिनमें आतंकवाद का मुकाबला करना, क्षेत्रीय स्थिरता को बढ़ावा देना और मुक्त व्यापार सुनिश्चित करना शामिल है। यह उम्मीद की जाती है कि दोनों देश इन साझा हितों के आधार पर अपने संबंधों को मजबूत करना जारी रखेंगे।

प्रतिक्रिया देने में संकोच नहीं करेगा।

2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा पाकिस्तान को 'दुष्ट परमाणु राष्ट्र' घोषित किया जाना और उसके परमाणु शस्त्रागार को अंतरराष्ट्रीय निगरानी में रखने की मांग, इस नीति की स्पष्टता को दर्शाता है। यह संदेश केवल पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिया गया है कि परमाणु हथियार आतंकवाद के कवच नहीं हो सकते।

## तीसरा स्तंभ: आतंकवादी और उनके समर्थक - दोनों समान

तीसरा और निर्णायक स्तंभ है – आतंकवादियों और उनके संरक्षकों के बीच कोई भेद नहीं। भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचों पर हमले, केवल आतंकियों पर नहीं, बल्कि उनपर राज्य प्रायोजित समर्थन पर भी हमला हैं। 7 मई, 2025 को MOD की प्रेस विज्ञप्ति में यह संकेत दिया गया कि भारत ने सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाया, लेकिन यदि पाकिस्तान प्रतिक्रिया स्वरूप अपनी सेना को शामिल करता है, तो भारत हर स्तर पर जवाब देगा।

पाकिस्तान का आतंकवादियों को 'रणनीतिक संपत्ति' मानना – चाहे वह मसूद अज़हर पर 14 करोड़ खर्च करने की योजना हो या लश्कर मुख्यालय के पुनर्निर्माण का निर्णय – यह स्पष्ट करता है कि वहां आतंकवाद राज्य नीति का हिस्सा है।

## वैश्विक सन्दर्भ और भारत की स्थिति

प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम हमले को 9/11 और लंदन बम धमाकों की तरह वैश्विक आतंकवाद से जोड़ा है, जिससे आतंकवाद के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय नैरेटिव गढ़ा जा सके। पाकिस्तान की संलिप्तता को नकारने की उसकी आदत के बावजूद, दुनिया को बार-बार यह याद दिलाना जरूरी है कि ओसामा बिन लादेन और खालिद शेख मोहम्मद जैसे आतंकियों के गढ़ पाकिस्तान में ही थे।

हालांकि पाकिस्तान को अतंरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की बेलआउट जैसी अंतरराष्ट्रीय राहतें मिल सकती हैं, लेकिन उसने अतीत में बार-बार इन निकायों को धोखा दिया है। सिंधु जल संधि जैसे दबावों का प्रभाव देर से दिखेगा, और पाकिस्तानी सेना इन संसाधनों का उपयोग अपनी तैयारियों में करती रहेगी।

आतंकवाद के खिलाफ इस नई नीति के तहत भारत को निरंतर अपनी रणनीति को अपग्रेड करना होगा। आत्मनिर्भरता, तकनीकी श्रेष्ठता, तेज और बहुस्तरीय प्रतिक्रिया अब सफलता की कुंजी हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत घरेलू क्षमताओं के बल पर आतंकवाद से निर्णायक लड़ाई लड़ सकता है।

इस नीति का सार यही हैः भारत अब इंतजार नहीं करेगा। वह प्रत्येक हमले का उत्तर अपने शर्तों पर देगा – ठोस, स्पष्ट और वैश्विक संदर्भों में न्यायोचित। प्रधानमंत्री मोदी का संदेश स्पष्ट है – अब भारत आतंकवाद के खिलाफ सिर्फ लड़ नहीं रहा, वह उसकी परिभाषा बदल रहा है।

अंततः भारत की यह तीन-स्तरीय नीति केवल एक रणनीतिक बदलाव नहीं, बल्कि एक वैश्विक सन्देश है – कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा और उसे परास्त करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति, सैन्य ताकत, और वैश्विक नैतिक आधार के साथ हर कदम उठाएगा।

# भारत-अमेरिका संबंधों में असहजता बढ़ते तनाव, बदलती प्राथमिकताएं

सीमा गुहा

**भारत-अमेरिका संबंधों में हालिया तनाव एक गहरी समस्या का संकेत है, जो दोनों देशों के बीच हितों के टकराव, अलग-अलग प्राथमिकताओं और भू-राजनीतिक बाध्यताओं से उत्पन्न होती है। भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है, और अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने, अपने पड़ोस में स्थिरता को बढ़ावा देने और अपनी आर्थिक ताकत को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तभी भारत एक सच्ची वैश्विक शक्ति बन सकता है, जो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सकारात्मक योगदान देने में सक्षम हो...**

जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारत और पाकिस्तान को 'सीजफायर करने' के लिए मनाने का श्रेय खुद को दिया और सार्वजनिक रूप से धमकी दी कि यदि वे उनकी बात नहीं मानते तो दोनों देशों के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ देंगे, तो उनके ये बयान न केवल नई दिल्ली के लिए अप्रत्याशित थे, बल्कि जिस असंवेदनशील अंदाज़ में उन्होंने ये बातें कहीं, उसने भी भारतीय कूटनीतिज्ञों को सकते में डाल दिया।

एक बार फिर, भारत को पाकिस्तान के साथ एक ही श्रेणी में रखा जा रहा था - ये एक ऐसी तुलना है जो नई दिल्ली को नागवार गुजरती है और जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसने पिछले दो दशकों में अथक कूटनीतिक प्रयास किए थे। अब, जब भारत के लिए सब कुछ ठीक होता दिख रहा था, ट्रम्प ने अचानक इस धारणा पर ठंडा पानी डाल दिया। भारतीय नीति निर्माताओं के लिए, ये बयान महज़ एक कूटनीतिक चूक नहीं थी, बल्कि एक गहरी समस्या का संकेत था। ये एक ऐसी समस्या थी, जो भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों की दीर्घकालिक स्थिरता और विश्वसनीयता पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर रही थी।

इसके बाद रक्षा विशेषज्ञों और विदेश नीति विश्लेषकों ने सवालों की झड़ी लगा दीः भारतीय विदेश नीति में कहां चूक हो गई? क्या भारत फिर से उसी मोड़ पर आ गया है, जहां उसे पाकिस्तान के साथ एक ही पलड़े में तोला जा रहा है? अमेरिका के साथ भारत की व्यापक और वैश्विक साझेदारी का क्या हुआ? क्या ये साझेदारी सिर्फ एक खोखला वादा थी? यूरोपीय सहयोगी, मध्य-पूर्व और ग्लोबल साउथ के नेताओं ने भी तुरंत तनाव कम करने का आह्वान किया। लेकिन जब मुश्किल वक्त आया, तो इनमें से किसी ने भी साथ नहीं

दिया। इस उदासीनता ने भारत के रणनीतिक समुदाय को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या बहुपक्षीयता और वैश्विक कूटनीति के प्रति भारत का दृष्टिकोण वास्तव में फलदायी है, या फिर ये केवल एक भ्रम है।

जर्मनी के पूर्व राजदूत गुरजीत सिंह कहते हैं, 'पहलगाम में हुए आतंकी हमले के लिए भारत को सहानुभूति और समर्थन मिला। लेकिन 'ऑपरेशन सिंदूर' को अक्सर कश्मीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच के एक मुद्दे के तौर पर देखा गया।' वे आगे कहते हैं, 'हमें अपना नज़रिया समझाने के प्रयासों को और तेज़ करना होगा। 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (TRF) को UNSC 1267 समिति के दायरे में लाने के लिए हमें समर्थन की ज़रूरत है। हमें अपने रणनीतिक साझेदारों के साथ आतंकवाद विरोधी बातचीत को सक्रिय करना होगा।' सिंह के ये शब्द भारतीय विदेश नीति की जटिलताओं और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के हितों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की चुनौतियों को दर्शाते हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज़बरदस्त अंतर्राष्ट्रीय पहुंच, दुनिया भर में उनकी लगातार यात्राएं और ट्रम्प, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जैसे वैश्विक नेताओं के साथ उनकी गर्मजोशी भरी दोस्ती के बावजूद, मौजूदा संकट के दौरान व्यक्तिगत संबंध काम नहीं आए। सबने पहलगाम हमले की निंदा तो की, लेकिन पाकिस्तान की तरफ उंगली उठाने से परहेज किया। ये उस दौर से बिल्कुल उलट था जब 2000 में अपनी इस्लामाबाद यात्रा के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने राष्ट्रपति परवेज़ मुशर्रफ़ को फटकार लगाई थी। इस विरोधाभास ने भारतीय कूटनीति के एक बुनियादी पहलू पर सवाल खड़े कर दिए: क्या व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर विदेश नीति का संचालन दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ और प्रभावी है?

संयुक्त राष्ट्र में भारत के पूर्व राजदूत अशोक मुखर्जी कहते हैं, 'ये संकट एक आतंकवादी हमला था जिसमें निर्दोष नागरिक मारे गए। हमें राजनयिक प्रतिक्रिया का आकलन इसी आधार पर करना चाहिए, न कि भारत-पाकिस्तान संबंधों के आधार पर।' वे आगे कहते हैं, 'अगर हम आतंकवाद का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि अमेरिका, पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को ध्वस्त करके, उसकी फंडिंग रोककर और उस पर प्रतिबंध लगाकर भारत के साथ अपनी एकजुटता दिखाएगा।' मुखर्जी की प्रतिक्रिया भारत में आम लोगों की भावनाओं और ट्रम्प द्वारा भारत और पाकिस्तान को एक समान मानने पर उनकी निराशा को दर्शाती है। ये निराशा इस तथ्य से और बढ़ जाती है कि भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका का लगातार समर्थन किया है, और इसके बदले में उसे केवल सतही समर्थन और उदासीनता मिली है।

कई भारतीयों को अमेरिकी कार्रवाई विश्वासघात जैसी लगती है। आखिरकार, मोदी सरकार ने ट्रम्प को लुभाने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी थी। पहलगाम में हुए नरसंहार के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जनभावनाएं अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं। आलम ये है कि भारतीय पर्यटक, संकट के दौरान पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए तुर्किये और अज़रबैजान जाने से भी इनकार कर रहे हैं। इस जन आक्रोश ने मोदी सरकार पर अमेरिका के साथ अपने संबंधों पर पुनर्विचार करने का दबाव बढ़ा दिया है।

पुराने लोगों को अमेरिका की पाकिस्तान के साथ पिछली दोस्ती याद है, और वो दौर भी याद है जब बांग्लादेश युद्ध में अमेरिका ने खुलकर इस्लामाबाद का साथ दिया था। उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के बारे में जानकारी देने के लिए वाशिंगटन और यूरोपीय राजधानियों

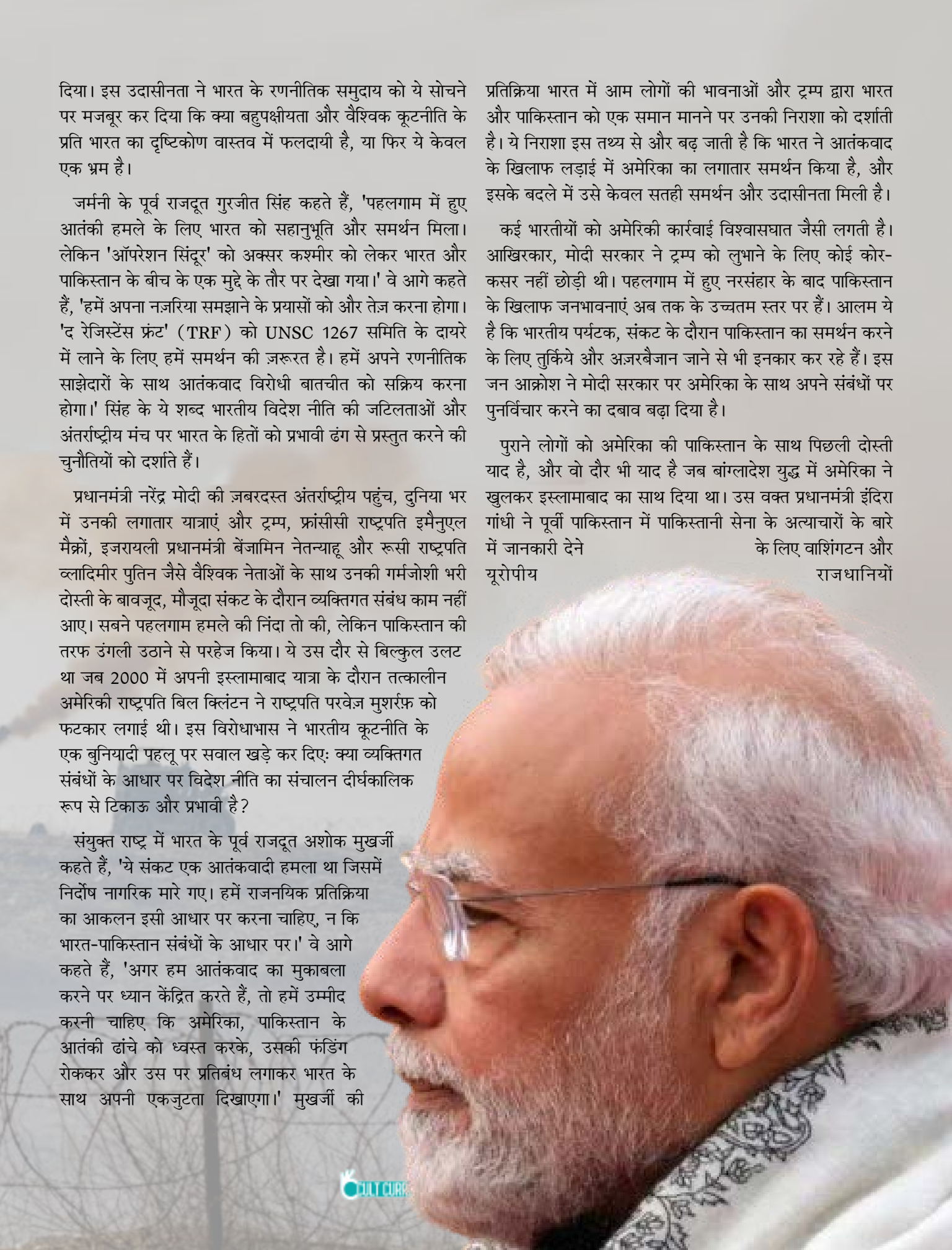

का दौरा किया था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में, उन्होंने भारतीय सेना को मुक्ति वाहिनी की मदद करने और एक स्वतंत्र बांग्लादेश बनाने भेजने से पहले रूस के साथ एक मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए। हालांकि, वो बात बहुत पुरानी हो गई। ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य भारत-अमेरिका संबंधों में निहित अविश्वास और संदेह की गहरी परत को उजागर करता है।

आज, संबंधों में आई इस हिचकी के बावजूद - जिसका कारण ट्रम्प की बिना सोचे समझे बोलने की आदत और हर चीज़ का श्रेय खुद लेने की उनकी भूख है - दिल्ली और वाशिंगटन अपने रिश्ते को खराब नहीं होने देंगे। दोनों देशों को चीन के उदय को लेकर रणनीतिक चिंताएं हैं। वाशिंगटन का भारत के प्रति मौजूदा झुकाव और उसकी गर्मजोशी का बहुत बड़ा कारण चीन की बढ़ती राजनीतिक और आर्थिक ताकत का मुकाबला करना है, जो आने वाले सालों में अमेरिका की महाशक्ति की स्थिति को चुनौती दे सकती है। भारत के लिए, अमेरिका के साथ दोस्ती एशिया में चीन के खिलाफ एक बीमा की तरह है। फिलहाल, भारत नाराज़ ज़रूर है, लेकिन आने वाले हफ़्तों में अमेरिकी प्रशासन उसे मनाने की कोशिश करेगा। फिर दोनों पक्षों को द्विपक्षीय संबंधों को सुधारने की दिशा में काम करना होगा। इस प्रक्रिया में कुछ महीने लगेंगे जब तक कि कोई व्यापार समझौता अंतिम रूप नहीं ले लेता। बातचीत से जुड़े लोगों के अनुसार, ये साल के अंत तक हो सकता है। अमेरिका भी भारत के विशाल बाज़ार पर नज़रें गड़ाए हुए है, जबकि भारत उच्च तकनीक सहयोग के लिए अमेरिका की ओर देख रहा है। ये कारक संबंधों को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाते रहेंगे। भारत-अमेरिका संबंधों को मौजूदा संकट से पहले वाली स्थिति में वापस आने में कुछ समय लगेगा। इन आर्थिक और भू-राजनीतिक कारकों के बावजूद, भारत को अमेरिका के साथ अपने संबंधों को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है।

वाशिंगटन के इलियट स्कूल ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स की जोआना स्पीयर कहती हैं, 'मुझे लगता है कि रिश्ते की नींव मज़बूत है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रम्प बदलते घटनाक्रमों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं और कम समय के लिए नीतियां बनाते हैं जो रिश्तों की ताकत को कम आंकती हैं। भारत इस क्षेत्र में एक अहम साझेदार है और अमेरिका उससे चीन के खिलाफ संतुलन बनाने में मदद चाहता है। इसलिए रिश्तों को खराब करना अमेरिकी भू-रणनीतिक हितों के खिलाफ होगा।' स्पीयर की ये टिप्पणी दर्शाती है कि अमेरिका भारत को एक रणनीतिक उपकरण के रूप में देखता है, जिसका उपयोग चीन के प्रभाव को कम करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह के लेन-देन वाले दृष्टिकोण से भारत की संप्रभुता और स्वायत्तता पर गंभीर सवाल उठते हैं।

भारत ने ट्रम्प के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा नहीं खोला। इसके

'ये संकट एक आतंकवादी हमला था जिसमें निर्दोष नागरिक मारे गए। हमें राजनयिक प्रतिक्रिया का आकलन इसी आधार पर करना चाहिए, न कि भारत-पाकिस्तान संबंधों के आधार पर।'

**-अशोक मुखर्जी,** भारत के पूर्व राजदूत, संयुक्त राष्ट्र

बजाय, उसने अपने घरेलू दर्शकों के लिए अमेरिकी कहानी को खारिज करने पर ध्यान केंद्रित किया। भारत का कहना है कि पाकिस्तान ने देश भर में अपने हवाई अड्डों पर हमले होने और नुकसान होने के बाद सीज़फायर का विकल्प चुना। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि अमेरिकी अधिकारियों ने फोन पर बातचीत की थी, लेकिन ये भी स्पष्ट रूप से इनकार किया कि बातचीत के दौरान व्यापार का कोई ज़िक्र हुआ था। भारत-पाकिस्तान मुद्दों में किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप की गुंजाइश को खत्म करते हुए, विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस हफ्ते घोषणा कीः 'इसलिए, मैं इस मौके का फायदा उठाकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते, हमारा व्यवहार द्विपक्षीय होगा, और सिर्फ द्विपक्षीय। ये कई सालों से हमारी राष्ट्रीय सहमति है।' पाकिस्तान हमेशा से भारत के साथ अपने विवादों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाने और किसी तीसरे देश से शांति कराने की कोशिश करता रहा है। भारत का ये रुख अपनी विदेश नीति में रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए, तो उन्होंने अपनी सरकार की 'पड़ोस पहले' की नीति की शुरुआत की। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ समेत सभी दक्षिण एशियाई देशों के नेताओं को उनके शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया गया था। 25 दिसंबर, 2015 को मोदी ने अफगानिस्तान की एक आधिकारिक यात्रा से लौटते वक्त बिना किसी तय कार्यक्रम के लाहौर में रुककर शरीफ को उनके जन्मदिन की बधाई देने का अप्रत्याशित कदम उठाया था। हवा में शांति की उम्मीद थी। लेकिन 2 जनवरी, 2016 को पठानकोट एयर फोर्स स्टेशन पर हुए आतंकी हमले के साथ, शांति कायम करने की सारी उम्मीदें धराशायी हो गईं। इसके बाद, 2016 और 2019 में हुए आतंकी हमलों के साथ हालात लगातार बिगड़ते चले गए। मोदी का भरोसा पूरी तरह से टूट गया और भारत ने 'आतंक और बातचीत साथ-साथ नहीं चल सकते' की अपनी नई नीति बनाई। कश्मीर की विशेष स्थिति को खत्म करने से

रिश्ते और खराब हो गए। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुआ आतंकी हमला, संबंधों को बेहतर बनाने की किसी भी उम्मीद के लिए आखिरी झटका साबित हुआ। नई दिल्ली ने बार-बार कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' अभी रुका हुआ है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इन घटनाओं से ये स्पष्ट हो गया कि पाकिस्तान के साथ शांति की कोई भी पहल आतंकवाद की निरंतर चुनौती के कारण विफल होने के लिए अभिशप्त है।

लेकिन बाकी दुनिया इस मुद्दे को एक अलग नज़र से देखती है। जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय के अली ममादोव कहते हैं, 'कश्मीर दुनिया के सबसे खतरनाक हॉटस्पॉट्स में से एक है। ये ग्रह के सबसे ज़्यादा सैन्यीकृत क्षेत्रों में से एक है, और चीन के साथ इसकी निकटता रणनीतिक जोखिम की एक और परत जोड़ती है। इसके अलावा, इससे सटा हुआ लद्दाख क्षेत्र - जहां भारत और चीन के बीच अपनी विवादित सीमा है - स्थिति को और जटिल बना देता है। हाल के सालों में हमने जिस तरह की झड़पें देखी हैं, वो दिखाती हैं कि स्थानीय स्तर पर पनपने वाले तनाव कितनी जल्दी बढ़ सकते हैं।' ये भू-राजनीतिक वास्तविकताएं भारत के लिए एक जटिल सुरक्षा वातावरण बनाती हैं, जिसमें उसे न केवल पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद की चुनौती का सामना करना पड़ता है, बल्कि चीन के बढ़ते प्रभाव को भी संतुलित करना होता है।

भले ही भारत वैश्विक मंच पर अपनी जगह बना रहा हो, लेकिन अपने पड़ोस में उसकी स्थिति अभी भी डांवाडोल है। पड़ोसी देशों के साथ उसके रिश्तों में कई उतार-चढ़ाव आए हैं। 2014 में जब मोदी पहली बार नेपाल गए थे तो वहां उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं टिक सका, क्योंकि इसके बाद संवैधानिक गतिरोध और भारत द्वारा देश की नाकाबंदी हुई। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने तक भारत का सबसे करीबी सहयोगी रहा बांग्लादेश भी अब लगभग एक शत्रुतापूर्ण पड़ोसी बन गया है। मालदीव और श्रीलंका दोनों ही देशों के साथ भारत के रिश्तों में कई बार उतार-चढ़ाव देखने को मिले हैं। चीन की बढ़ती आर्थिक ताकत और भारत के पड़ोस में उसकी मौजूदगी ने छोटे देशों को एक ऐसा विकल्प दिया है जो पहले उनके पास नहीं था। इस क्षेत्रीय अस्थिरता से भारत की विदेश नीति और सुरक्षा रणनीति के लिए और भी ज़्यादा चुनौतियां पैदा हो गई हैं।

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने दुनिया के लिए अपने बाज़ार खोले, और इसके साथ ही अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ नई दिल्ली के रिश्तों में बदलाव आना शुरू हो गया। साम्यवाद की हार और पूर्व सोवियत संघ के विघटन ने देश को नेहरू युग की समाजवादी मानसिकता और स्वतंत्रता के तुरंत बाद के सालों में हावी रही गुटनिरपेक्ष विदेश नीति को त्यागने में मदद की। दुनिया भर में मुक्ति आंदोलनों के लिए नई दिल्ली का समर्थन भी कम हो गया। नरसिम्हा राव सरकार ने इज़राइल के साथ संबंधों को बेहतर बनाया, जबकि फ़िलिस्तीनी मामलों के लिए नई दिल्ली का समर्थन धीरे-धीरे कम होता गया। भारत उन पहले गैर-अरब देशों में से एक था जिसने फ़िलिस्तीन मुक्ति संगठन (PLO) को फ़िलिस्तीनी लोगों के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में मान्यता दी थी। 1975 में दिल्ली में एक पीएलओ कार्यालय स्थापित किया गया था। पीएलओ प्रमुख यासर अराफात उस समय भारत के करीबी दोस्त थे। आज, इज़राइल के लिए भारत के समर्थन ने फ़िलिस्तीनी मामलों के लिए उसकी पिछली सहानुभूति को काफी हद तक बदल दिया है। इस बदलाव ने न केवल भारत की विदेश नीति में आए वैचारिक बदलाव को दर्शाया है, बल्कि ये भी दिखाया है कि भारत अब अपनी आर्थिक और रणनीतिक प्राथमिकताओं को कितना महत्व देता है।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा 2005 में ऐतिहासिक नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद से, भारत और अमेरिका की सरकारों ने लगातार नज़दीकी रिश्ते बनाए हैं। जो बाइडेन के कार्यकाल के दौरान, भारत को काफ़ी फायदा हुआ और वो यूक्रेन युद्ध के दौरान अपने पुराने दोस्त रूस के साथ खड़ा रहा, और वाशिंगटन द्वारा मॉस्को पर लगाए गए कड़े प्रतिबंधों के बावजूद रियायती दरों पर तेल खरीदने में कामयाब रहा। बाइडेन प्रशासन ने पाकिस्तान के साथ बहुत कम बातचीत की। लेकिन अप्रत्याशित स्वभाव वाले ट्रम्प के साथ, कुछ भी निश्चित नहीं माना जा सकता। उनका रवैया कभी गर्म तो कभी ठंडा रहता है। वे व्यावहारिक हैं और अगर हालात उनके मुताबिक नहीं हैं तो अपना रुख बदल सकते हैं। नई दिल्ली को इस मौजूदा संकट से कुछ सबक सीखने की ज़रूरत है। किसी भी अस्थिर अमेरिकी राष्ट्रपति को नाराज़ करने की कीमत पर भी राष्ट्रीय हितों के मुद्दों पर अपनी लक्ष्मण रेखा खींचना ज़रूरी है। ट्रम्प की टिप्पणियों पर चुप रहना या उन्हें नज़रअंदाज़ करना कोई मदद नहीं करेगा। विदेश नीति पर जयशंकर के शब्दों को दोहराएं तो, 'मुझे लगता है कि आगे की विदेश नीति के लिए हमें बड़ा सोचने, लंबा सोचने और चालाकी से सोचने की ज़रूरत है।' भारत को चालाकी से सोचने और अपनी अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस अस्थिर दुनिया में आर्थिक ताकत ही सबसे ज्यादा मायने रखती है।

---

**सीमा गुहा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो लगातार अंतरराष्ट्रीय मामलों पर लिखती रही हैं। यह लेख सबसे पहले आउटलुकइंडिया.कॉम में प्रकाशित हुआ था।**

# हमारे हथियार मचाते हैं

# हाहाकार

संजय श्रीवास्तव

'ऑपरेशन सिंदूर' के तहत भारतीय सेना ने भविष्य की हाई-टेक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का वह प्रदर्शन किया है, जिसने तमाम देशों को सकते में डाल दिया है...

ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद अब तक की सारी सफलता उत्कृष्ट रक्षा तकनीक और उसके इस्तेमाल के कौशल का कमाल है। इस अभियान के तहत सेना ने सीमा पार के आतंकी ठिकानों को बिना बार्डर पार किए नेस्तनाबूद किया और बौखलाए पाकिस्तान ने जब हमारे सैन्य ठिकानों, सीमा और दीगर इलाकों पर पचासों ड्रोन, मिसाइलों, बम वगैरह से हमले किए तो उन सभी को हमने, वे कोई नुकसान पहुंचा सकें उससे पेशतर, अपनी तकनीक क्षमता, दक्षता से नाकाम कर दिया। बेशक सिंदूर अभियान की सबसे अहम बात थी इसका टेक्नोलॉजी-ड्रिवन एक्जीक्यूशन— भारतीय सेना ने पहली बार किसी रक्षा अभियान में इतने बड़े पैमाने पर तकनीक संचालित हथियारों, अति उन्नत तकनीक वाली रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल किया। सीमा के भीतर से सीमा के पार वार करने के लिये स्वदेशी ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम 'नाविक' से लक्ष्य की निशानदेही हुई, इसरो के उपग्रह कार्टोसेट ने रीयल टाइम इमेज दी, डीआरडीओ के यूएवी रुस्तम और नेत्रा ने जमीनी हरकतों, हलचलों को दर्ज किया तो स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफार्म ने बढ़िया सुरागरसी की। खुफिया जानकारी जुटाई, आर्टीफीशियल इंटेलिजेंस ने सटीक, निष्कंटक रास्ता बताया। सिगनिट के जरिये संचार सेवा आबाध रही तो मूवमेंट का पता दुश्मन को ना लगने पाये इसके लिये स्पेक्ट्रा जैमिंग प्रणाली से उनके रडार

## जिन हथियारों के दिखे जौहर

**इस अभियान में जिन हथियारों, विमानों, रक्षा प्रणालियों ने खास जौहर दिखाए उनमें से कुछ स्वदेशी हैं तो कुछ आयातित। ज्यादातर पहली बार काम आये और अपनी कीर्ति गाथा लिख गए**

### स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र -1

अल्फा डिजाइन और एल्बिट सिस्टम्स द्वारा विकसित, 'नागास्त्र-1' जैसे आत्मघाती ड्रोन अब भारतीय सेना में शामिल हैं। ये झुंड में हमला करने, दुश्मन के इलाके में गश्त करने और रीयल-टाइम जानकारी प्रदान करने में सक्षम हैं। 100 किलोमीटर रेंज और 40 किलो वारहेड क्षमता वाले ये ड्रोन, चुपचाप सटीक हमला करते हैं। सैन्य विशेषज्ञ इसे 'सेंसर-टू-शूटर' युग की शुरुआत मानते हैं।

### सेल्फ गाइडेड हैमर बम

सफ्रान का हैमर (HAMMER) बम, मजबूत ठिकानों को भेदने के लिए बनाया गया है। GPS/INS नेविगेशन और इंफ्रारेड/लेजर गाइडेंस से लैस, ये 15-70 किमी की दूरी तक सटीक निशाना लगाते हैं। राफेल सहित कई विमानों से दागे जा सकने वाले, प्रत्येक 84 हजार रुपये के हैमर बम एक साथ छह लक्ष्यों को भेद सकते हैं, जो मध्यम दूरी के लक्ष्यों को तबाह करने में सक्षम हैं।

### स्काल्प मिसाइलें

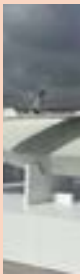

फ्रांस-ब्रिटेन निर्मित स्काल्प (SCALP) क्रूज मिसाइल, राफेल पर तैनात, 500 किमी रेंज वाली 'फायर एंड फगेट' क्षमता वाली मिसाइल है। यह सबसोनिक गति पर रडार से बचकर सटीक निशाना साधती है। लक्ष्य के पास पहुंचकर, मिलान करने के बाद यह बंकरों जैसे लक्ष्यों में सिर के बल घुस जाती है। 8 करोड़ रुपये की कीमत वाली यह मिसाइल इराक, सीरिया, लीबिया और यूक्रेन में उपयोग की जा चुकी है।

### वायु रक्षा प्रणाली एस -400, सुदर्शन चक्र

ऑपरेशन सिंदूर में वायुसेना की हवाई हमलों में सफलता सराहनीय रही। इस ऑपरेशन में, चीन से प्राप्त पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 पूरी तरह विफल रहा, जबकि रूस निर्मित भारतीय वायु रक्षा प्रणाली 'सुदर्शन चक्र' ने पाकिस्तानी विमानों और मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोका और नष्ट किया। यह भारतीय वायु रक्षा प्रणाली की श्रेष्ठता का प्रमाण है।

### स्ट्रैटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफार्म

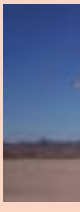

डीआरडीओ द्वारा विकसित 'स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म' का मध्य प्रदेश में सफल परीक्षण हुआ। ऑपरेशन सिंदूर से पहले, इस गुब्बारे जैसे जासूसी सिस्टम ने खुफिया जानकारी जुटाकर सटीक रणनीति बनाने में मदद की।

जाम किए गए, स्पूफिंग के जरिये नकली संकेत भेज कर उन्हें भ्रमित किया गया। इस दौरान दुश्मन की सुरक्षा को चकमा देने के लिये लाइटरिंग म्यूनेशन, कामेकाजी ड्रोन तथा प्रकाशीय गोले डिकाय फ्लेयर्स ने शानदार कारगुजारी दिखाई, इन्होंने पाकिस्तानी वायु सुरक्षा को इस बावत धोखे में रखा कि हमला कहां हो रहा है या होने को है।

अत्याधुनिक तकनीक से युक्त मल्टीरोल वाले मिराज 2000,राफेल जैसे कई विमान उड़े और अपनी सीमा के भीतर से ही रॉफेल मेटियॉर, स्काल्प मिसाइल, क्रिस्टॅल मैज़ मिसाइल, गाइडेड हैमर बम, स्पाइस 2000 बम, इस्राइल निर्मित पेववे -2 सुदर्शन लेजर बम जो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल गाइडेड बम हैं और लक्ष्य तक जाने के लिए इंफ्रारेड या प्रकाश सेंसर का इस्तेमाल करते हैं, वगैरह से स्टैंड ऑफ अटैक किया।

नौ आतंकी ठिकानों पर एक साथ हुए इस हमले और उनके तबाह हो जाने से झुंझलाए पाकिस्तान ने सीमा पर 50 से ज्यादा ड्रोन भेजे, इन के जरिये विस्फोट करने का इरादा था पर सेना ने एल-70 गन, ज़ेड यू-23 एमएम, शिल्का सिस्टम और दूसरे एंटी ड्रोन तकनीकि से उन्हें जमीन सुंघा दिया। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम सुदर्शन चक्र यानी एस-400 ने न सिर्फ पाकिस्तान के कई जेएफ -17 जेट विमान मार गिराए बल्कि लाहौर में उनकी चीन निर्मित वायुरक्षा प्रणाली एचक्यू 9 भी ध्वस्त कर दी। उधर अरब सागर में तैनात विमानवाही जंगी जहाज विक्रांत ने अपनी अत्यधुनिक मिसाइल प्रक्षेपण तकनीक का प्रदर्शन करते हुए कराची में भीषण धमाका किया तो इस्राइल के बने बेहद सक्षम और मारक आत्मघाती ड्रोन हारूप ने भी इस संघर्ष में गज़ब का कौशल दिखाया। इसके अलावा भी तमाम तकनीकि प्रविधिय भारतीय सेना ने इस अभियान में इस्तेमाल किया। पाकिस्तान के विरुद्ध भारत द्वारा अब तक चलाए गए सैन्य अभियानों में इतनी तकनीकी सघनता कभी नहीं देखी गई।

चीन और तुर्की आदि देशों से दोस्ती के चलते पाकिस्तान ने भी सैन्य तकनीक में प्रगति की है, सो दोनों देशों के बीच पारंपरिक दुश्मनी अब तकनीकी जंग का रूप ले चुकी है। लेकिन सच तो यह है कि पाकिस्तान किसी भी स्थिति में सैन्य व रक्षा तकनीक में भारतीय क्षमता का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारे पास ज्यादा तकनीकि संसाधन, बहुत बड़ी आर्थिक क्षमता और तकनीक और विज्ञान संबंधी वैश्विक स्तर की सैन्य तथा रक्षा साझेदारियां हैं। डीआरडीओ के अलावा दर्जन भर संगठन, संस्थाएं, कंपनियां, आधुनिकतम आयुध तथा रक्षा प्रणाली के विकास में रत हैं। इसके अलावा देश में डिफेंस स्टार्टअप और घरेलू निर्माण भी तेजी पर है। भारत सैन्य बल, हथियारों और रक्षा तकनीक पर खर्च के मामले में दुनिया सबसे बड़े पांच सैन्य शक्तियों में से एक है। पाकिस्तान का इस सूची में नंबर बहुत नीचे है। पाकिस्तान मात्र नाभिकीय हथियारों की संख्या में ही भारत की बराबरी कर सकता है सैनिकों की संख्या, सैन्य संसाधन, विमान, पोत, हथियार और हथियार प्रणालियों के बारे में वह मीलों पीछे है। ऑपरेशन सिंदूर' में उच्च परिशुद्धता वाले हथियारों का जिस तरह प्रयोग किया गया और सरकार जिस पैमाने पर सेना के सभी अंगों के लिए हरबे, हथियारों की खरीद फरोख्त पर ध्यान और ज़ोर दे रही है अगले एक दशक के भीतर भारत और विपन्न पाकिस्तान की सैन्य क्षमता के बीच इतना फासला होगा कि वह चीन, तुर्की की खुली मदद लेकर भी ऐसे पाट पाना तो दूर चौथाई तक भी नहीं पहुंचेगा।

भारत का अभियान इंच दर इंच इतना सटीक था कि उसने बिन भटके बस लक्षित लक्ष्य को ही तबाह किया, कोई बेजा नागरिक नुकसान नहीं हुआ। इस शानदार सटीकता, अचूकता का श्रेय है सेनाओं के सम्मिलित प्रयास, सैन्य कौशल, साहस, शौर्य, शक्ति के साथ नई वार टेक्नोलॉजी, आधुनिक हथियारों और शस्त्र प्रणालियों के अद्भुत प्रदर्शन को। भारतीय सेना ने इस प्रदर्शन से स्पष्ट कर दिया है कि अब युद्ध की परिभाषा परिवर्तित हो कर वह ताकत से ज्यादा तकनीक की लड़ाई बन गई है। इसमें सबसे आगे रहने के लिए वह आगे चल कर और भी कमाल रक्षा तकनीक विकसित और इस्तेमाल करेगी। 'ऑपरेशन सिंदूर' और उसके बाद की प्रतिक्रिया सिर्फ पाकिस्तान को ही एक माकूल जवाब नहीं है बल्कि यह भविष्य की हाई-टेक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी का ऐसा प्रदर्शन था जिसे देश के बारे में बुरा सोचने वाले बाकी मुल्क भी सहमें।

# पाकिस्तान पर भारत की खुफिया बढ़त

अर्चिश्मन रे गोस्वामी

**'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान भारत की खुफिया एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे पाकिस्तान पर भारत की रणनीतिक बढ़त मजबूत हुई है। इस सफलता को बनाए रखने के लिए भारत को और अधिक कदम उठाने होंगे।**

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की आकाशतीर वायु रक्षा प्रणाली की सफलता, भारत की तकनीकी खुफिया क्षमताओं की बढ़ती परिष्कार को दर्शाती है। भारत के कार्टोसैट उपग्रहों के नेटवर्क द्वारा वास्तविक समय में सूचित, आकाशतीर सिस्टम ने सीमा के साथ और भीतरी इलाकों में नागरिक बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाले पाकिस्तानी ड्रोन झुंडों के खिलाफ तैनात किए जाने पर लगभग सही सफलता दर हासिल की। यह न केवल भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का प्रमाण है, बल्कि निष्क्रिय संघर्ष में आकाशतीर प्रणाली का इंजीनियरिंग और परिचालन प्रदर्शन उच्च-स्तरीय रणनीतिक खुफिया (वास्तविक समय उपग्रह इमेजरी के संग्रह और प्रसंस्करण द्वारा उदाहरण) और तत्काल सामरिक अनुप्रयोग के बीच निर्बाध एकीकरण को रेखांकित करता है। नतीजतन, उम्मीद से कम नागरिक हताहत हुए हैं, और पाकिस्तानी सेना के लिए सफलता का दिखावा करने के लिए नगण्य आधार हैं।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आकाशतीर वायु रक्षा प्रणालियों की सफलता ने एक खुफिया अभिनेता के रूप में भारत की बढ़ती स्वायत्तता कोcaptured किया। 1999 के कारगिल युद्ध के विपरीत, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने राजनीतिक लाभ के लिए 'चयनात्मक उपलब्धता' की नीति के माध्यम से भारत के गैर-सैन्य जीपीएस रिसीवरों की सटीकता को सक्रिय रूप से कम कर दिया, आकाशतीर ने स्वदेशी रूप से विकसित NAVIC नेविगेशन प्रणाली का उपयोग किया। इससे अमेरिका जैसे बाहरी अभिनेताओं की संघर्ष में कोई सार्थक परिचालन भूमिका निभाने की क्षमता काफी कम हो गई। 10 मई की शुरुआती घंटों तक, भारतीय वायु सेना ने रावलपिंडी में पीएएफ बेस नूर खान पर हमला किया था - जो पाकिस्तान के परमाणु कमान प्राधिकरण, सामरिक योजना प्रभाग के सचिवालय से थोड़ी दूरी पर स्थित है - इस

प्रकार सफलतापूर्वक पुनः स्थापित किया गया, जो ऑपरेशन सिंदूर के केंद्र में स्थित निवारक उद्देश्य था।

## काउंटरइंटेलिजेंस : अज्ञात जल में

11 मई से, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) ने पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (ISI) की सहायता करने के संदेह में पूरे भारत में कई लोगों को गिरफ्तार किया है। हिरासत में लिए गए लोगों की पृष्ठभूमि भारत में इस्लामाबाद की विकसित हो रही खुफिया प्राथमिकताओं पर प्रकाश डालती है, साथ ही उन कदमों को भी उजागर करती है जो भारत की काउंटरइंटेलिजेंस सेवाओं को इन उभरते खतरों का सामना करने के लिए उठाने चाहिए।

सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी से पुलिस सूत्रों के अनुसार, ISI द्वारा शांति और युद्धकाल दोनों में दुष्प्रचार फैलाने के लिए प्रभाव एजेंटों की भर्ती पर अधिक ध्यान केंद्रित करने का पता चलता है। इस तरह के प्रयास ISI के रणनीतिक मूल्य की जानकारी तक पहुंच के साथ निचले स्तर के प्रबंधकीय पदों पर उन लोगों की भर्ती पर पारंपरिक ध्यान देने के साथ-साथ देश के रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में कम वेतन वाले नागरिकों की भर्ती के साथ जारी रहने की संभावना है। पिछले उदाहरणों में पूर्व ब्रह्मोस इंजीनियर निशांत अग्रवाल और मुजीब रहमान शामिल हैं, जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर के चरम पर आईएनएस विक्रांत के आंदोलनों पर खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक सरकारी अधिकारी के रूप में प्रतिरूपण करने के लिए गिरफ्तार किया गया था।

शुरुआती संकेत बताते हैं कि भारत की काउंटरइंटेलिजेंस सेवाएं इन चुनौतियों को पहचानती हैं और उनसे निपटने के लिए कदम उठाना शुरू कर दिया है। इनमें से कुछ प्रयास पहले से ही फलदायी होते दिख

रहे हैं - उदाहरण के लिए, हाल ही में गुजरात में एक 18 वर्षीय व्यक्ति की 'साइबर आतंकवाद' के आरोप में और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकारी वेबसाइटों के खिलाफ पाकिस्तानी साइबर हमलों को रोकने के लिए गिरफ्तारी। समानांतर में, भारतीय अधिकारियों ने तीसरे पक्ष के राज्यों द्वारा पाकिस्तानी दुष्प्रचार के प्रवर्धन के खिलाफ भी कार्रवाई की है, इसे उच्चतम क्रम की एक काउंटरइंटेलिजेंस चिंता के रूप में मानते हुए। भारतीय अधिकारियों ने चीनी और तुर्की राज्य मीडिया आउटलेट्स के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो संघर्ष के दौरान आईएसआई-संरेखित आख्यानों को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका को देखते हुए।

## खुफिया संपर्क : विस्तार के लिए गुंजाइश

यह समान रूप से महत्वपूर्ण है कि भारत भागीदार देशों के साथ खुफिया संपर्क के माध्यम से सबसे बड़ा रणनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए सक्रिय शत्रुता में चल रहे निलंबन का लाभ उठाए। हाल के दिनों में, विदेश मंत्री (EAM) एस. जयशंकर ने अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से बात की - 2021 में काबुल पर तालिबान के कब्जे के बाद दोनों के बीच पहली आधिकारिक कॉल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने अपने ईरानी समकक्ष अली अकबर अहमदियान से भी बात की है। दोनों देशों में पाकिस्तान और क्षेत्र में उसकी अस्थिर करने वाली भूमिका के प्रति एक साझा अविश्वास है - पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच संबंध अब तक के सबसे निचले स्तर पर हैं, और ईरान का पाकिस्तान पर सीमा झड़पों के साथ-साथ जासूसी का भी इतिहास रहा है। साझा चिंताओं की आपसी मान्यता मौजूदा संपर्क ढांचे के विस्तार के लिए अनुकूल हो सकती है, जिससे नई दिल्ली पाकिस्तान पर अधिक दबाव डाल सके और आतंकवाद को राज्य नीति के उपकरण के रूप में नियोजित करने की उसकी क्षमता को रोक सके। हालांकि, इन देशों के साथ किसी भी खुफिया-साझाकरण समझौते को वर्गीकृत जानकारी से समझौता किए जाने के जोखिम के लिए सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए, जो चीन के माध्यम से पाकिस्तान की पहुंच के माध्यम से किया जा सकता है, अफगानिस्तान और ईरान दोनों के हाल के वर्षों में बीजिंग के साथ बढ़ते संरेखण को देखते हुए।

दरअसल, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को प्रमुख सहयोगियों के लिए एक खुफिया संपर्क भागीदार के रूप में अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए अवसर की एक संक्षिप्त खिड़की प्रदान की है। यह एक ऐसा लाभ है जिसका उपयोग तत्काल राजनयिक या आर्थिक लाभ के लिए किया जा सकता है। पाकिस्तान द्वारा नियोजित इंटरसेप्ट किए गए चीनी पीएल -15 ई मिसाइलों और तुर्की ड्रोन का मलबा भारत को चीनी और तुर्की दोनों हथियार प्रणालियों को समझने का अवसर प्रदान करता है - खुफिया जानकारी जिसका उपयोग नई दिल्ली द्वारा किया जा सकता है या इच्छुक वैश्विक भागीदारों के साथ कारोबार किया जा सकता है।

सूत्रों का सुझाव है कि फ्रांस जैसे देशों और फाइव आइज़ गठबंधन (ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका) के सदस्य राज्यों ने पहले ही ऐसी खुफिया जानकारी हासिल करने में रुचि व्यक्त की है।

## चुनौतियां और अगले कदम

हालांकि, खुफिया क्षेत्र के भीतर बहुत कुछ किया जाना बाकी है यदि भारत ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को रोकने में हासिल किए गए लाभ को मजबूत करना चाहता है। जबकि प्रत्येक रणनीति का विशिष्ट विवरण इसकी संदर्भ और उद्देश्यों के आधार पर अलग-अलग होगा, एक आक्रामक रुख - जिसमें मानव और तकनीकी दोनों स्रोतों के माध्यम से खुफिया जानकारी एकत्र करना, साथ ही धोखे और गतिज संचालन की सक्रिय तैनाती शामिल है - हाल ही में पाकिस्तान के राज्य प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ स्थापित निवारण को बनाए रखने के लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है।

भविष्य के दुस्साहस के खिलाफ पाकिस्तान को रोकने के लिए एक प्रमुख घटक में तुर्की और चीन दोनों के साथ उसके लंबे समय से चले आ रहे रणनीतिक संरेखण की स्पष्ट समझ विकसित करना शामिल है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर ने तेज सार्वजनिक फोकस में लाया। जैसे, भारत को खुफिया संग्रह प्रयासों का विस्तार करना चाहिए, जिसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि तीनों देशों के हित कहां और कैसे अभिसरण या विचलन करते हैं, खासकर आतंकवाद के पाकिस्तान के प्रायोजन के संबंध में। इसके लिए तीसरे पक्ष के भूगोल में खुफिया संग्रह के लिए

बढ़े हुए संसाधनों को समर्पित करने की आवश्यकता हो सकती है - जहां इस्लामाबाद, बीजिंग और अंकारा के हित और गतिविधियां सबसे अधिक दिखाई देती हैं। विशेष रूप से, मध्य एशिया और काकेशस महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, यह देखते हुए कि तुर्की और चीन दोनों ने यहां अपने आर्थिक और राजनीतिक पदचिह्न का विस्तार किया है, और पाकिस्तान ने हाल ही में यहां भारत विरोधी आतंकवादियों की भर्ती और प्रशिक्षण दिया है। यह पहचानना कि पाकिस्तान के हित और नीतियां उसके दो करीबी रणनीतिक भागीदारों की तुलना में कहां सबसे करीब से मेल खाती हैं या उनसे भिन्न हैं, भारतीय नीति निर्माताओं को प्रमुख कमजोरियों की पूरी तस्वीर प्रदान कर सकते हैं जिनका उपयोग कई माध्यमों से किया जा सकता है, दोनों खुले और गुप्त, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत में मांगी गई दीर्घकालिक रोकथाम को बनाए रखने के लिए। जबकि क्षेत्रीय भागीदारों के साथ संपर्क इस रणनीति को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है (जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है), खुफिया संग्रह प्राथमिकताओं को एकतरफा संचालन पर भी जोर देना चाहिए, कई क्षेत्रीय सरकारों की आंतरिक सुरक्षा कमजोरियों और तुर्की और चीन दोनों के साथ उनके बढ़ते भू-राजनीतिक संरेखण को देखते हुए।

इसी तरह यह सिफारिश की जाती है कि काउंटर-ओएसआईएनटी (ओपन-सोर्स इंटेलिजेंस) क्षमताओं को प्राथमिकता दी जाए, पाकिस्तानी दुष्प्रचार के संक्षारक प्रभाव को देखते हुए, जिसे अक्सर तुर्की और चीनी राज्य मीडिया द्वारा बढ़ाया जाता है। जिस तरह 26/11 के हमलों के परिणामस्वरूप दो साल बाद एनआईए की स्थापना हुई ताकि मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी मुद्दों को संबोधित किया जा सके और भारत की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच संपर्क किया जा सके, उसी तरह एक समर्पित काउंटर-ओएसआईएनटी एजेंसी दुष्प्रचार के खिलाफ एक समान लक्ष्य प्राप्त करने में मदद कर सकती है। स्वीडन की मनोवैज्ञानिक रक्षा एजेंसी से सबक सीखा जा सकता है, जिसे 2022 में रूसी और चीनी दुष्प्रचार अभियानों से उत्पन्न खतरे का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। एक समान भारतीय एजेंसी संभावित रूप से राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (NTRO, भारत की प्राथमिक सिग्नल खुफिया एजेंसी, जिसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई) जैसी सिस्टर सेवाओं के साथ मिलकर काम कर सकती है, या यहां तक कि निजी क्षेत्र की पहलों के साथ सहयोग कर सकती है, जैसे कि डेटा सुरक्षा परिषद ऑफ इंडिया द्वारा संघर्ष के दौरान पाकिस्तानी डिजिटल खतरे के अभिनेताओं द्वारा लक्षित प्रकृति और कमजोरियों की जांच करने के लिए गठित टास्क फोर्स।

इसी तरह, भारतीय खुफिया एजेंसियां ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्राप्त लाभों को गुप्त कार्रवाई के निरंतर प्रयास के माध्यम से संरक्षित कर सकती हैं - काउंटर-धोखे और गतिज संचालन दोनों में। पाकिस्तानी आतंकवादियों का लक्षित तटस्थता न केवल इस तरह के समूहों के नेतृत्व को समाप्त करने का काम कर सकती है, बल्कि राज्य की उदारता पर भरोसा करने की निरर्थकता को भी संकेत दे सकती है, जो उनकी शारीरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ है। धोखे और प्रतिवाद के रचनात्मक उपयोग के माध्यम से प्रभाव एजेंटों की भर्ती के लिए पाकिस्तान के प्रयासों को संबोधित करने के लिए भारतीय काउंटरइंटेलिजेंस सेवाओं द्वारा सक्रिय कदम - शायद ऊपर उल्लिखित, काल्पनिक काउंटर-ओएसआईएनटी सेवाओं के समन्वय में - प्रतिकूल के रणनीतिक हलकों के भीतर भ्रम को काफी बढ़ा सकता है। इस तरह का दृष्टिकोण भारतीय नागरिकों को जासूसी के लिए भर्ती के माध्यम से किए गए किसी भी लाभ को बाधित करने का काम करेगा।

भारत की खुफिया एजेंसियों ने निस्संदेह ऑपरेशन सिंदूर के बैनर तले अपने रणनीतिक लक्ष्यों की उपलब्धि में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हालांकि, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन सफलताओं को उलट नहीं दिया गया है, हाल ही में प्राप्त लाभों की गति पर निर्मित एक अधिक सक्रिय रणनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। धैर्य, आत्मविश्वास, रणनीतिक स्पष्टता और संदेह की एक स्वस्थ खुराक का संयोजन भारत को हाल के हफ्तों में स्थापित निवारण को बनाए रखने में मदद करने में बहुत दूर जा सकता है।

**अर्चिश्मन गोस्वामी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में एमफिल इंटरनेशनल रिलेशन्स प्रोग्राम की पढ़ाई कर रहे स्नातकोत्तर छात्र हैं और यह लेख सबसे पहले ओआरएफ में रायसीना डिबेट्स के तहत प्रकाशित हुआ था।**

# भारत
## आंतरिक खतरे
## अदृश्य युद्ध

संदीप कुमार

**भारत एक अदृश्य युद्ध लड़ रहा है, जहाँ दुश्मन सीमा के पार नहीं, बल्कि भीतर घात लगाए बैठे हैं। ये दुश्मन जासूस, सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाले और साइबर अपराधी हैं। इनसे निपटने के लिए सजगता और आधुनिक तकनीक की आवश्यकता है।**

भारत एक बहुआयामी खतरे का सामना कर रहा है - बाहरी ताकतों के साथ-साथ 'आस्तीन के सांपों' से भी, जो हमारे बीच रहकर, हमारी भाषा बोलकर, हमारे संसाधनों का इस्तेमाल करके, राष्ट्र-विरोधी एजेंडा चला रहे हैं। ये दुश्मन, कभी जासूस बनकर सामने आते हैं, तो कभी सोशल मीडिया पर नफरत फैलाकर, और कभी किसी विदेशी शक्ति के हाथों की कठपुतली बनकर।

आज, देश की सुरक्षा के सामने खड़ा खतरा, सीमा पर तैनात दुश्मनों तक ही सीमित नहीं है। यह खतरा उन नेटवर्कों से पैदा होता है जो सूचना, विचार और डिजिटल माध्यमों के जरिए हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रहे हैं। इस अदृश्य युद्ध में, हमें सिर्फ बंदूक से नहीं, बल्कि अपने विचारों और जागरूकता से लड़ना होगा।

2024 और 2025 के शुरुआती महीनों में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने सिलसिलेवार गिरफ्तारियां कीं, जिन्होंने इस अदृश्य जाल की परतें उधेड़ कर रख दीं। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिनके चैनल पर 3.85 लाख सब्सक्राइबर हैं, तीन बार पाकिस्तान की यात्रा कर चुकी हैं। वे पाकिस्तानी राजनयिक दानिश के संपर्क में पाई गईं, जिन्हें भारत सरकार ने निष्कासित कर दिया था। उनकी यात्राएं, उनके वीडियो कंटेंट और उनकी गतिविधियां, अब जांच के दायरे में हैं।

गजाला और यामीन मोहम्मद जैसे लोग भी इसी संदिग्ध जाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने पाकिस्तानी संपर्कों से पैसे लिए और खुफिया जानकारी साझा की। ये लोग सोशल मीडिया या नकली दस्तावेजों के माध्यम से विदेशी एजेंसियों के लिए सूचना जुटा रहे थे। इसी कड़ी में पटियाला के छात्र देवेंदर सिंह को सैन्य छावनी की तस्वीरें भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नूंह (हरियाणा) के अरमान और तारीफ पर पाकिस्तानी दूतावास के एजेंटों के कहने पर सिम कार्ड और खुफिया जानकारी देने के आरोप हैं।

रामपुर के शहजाद ने मसालों और कपड़ों की तस्करी के बहाने पाकिस्तान से संबंध बनाए और जासूसी में लिप्त रहा। मोहम्मद मुर्तजा अली, एक ऐप डेवलपर, ने खुद तकनीकी माध्यम से जासूसी के लिए मोबाइल ऐप्स बनाए और डेटा लीक किया। गुरदासपुर के सुखप्रीत सिंह और करणबीर सिंह को 'ऑपरेशन सिंदूर' से जुड़ी सैन्य जानकारी लीक करने के मामले में गिरफ्तार किया गया।

रूस स्थित भारतीय दूतावास में कार्यरत सतेंद्र सिवाल, जो रक्षा मंत्रालय से जुड़ी जानकारी लीक कर रहे थे, का पकड़ा जाना इस बात का संकेत है कि अब यह खतरा किसी वर्ग, जाति या पहचान तक सीमित नहीं है। राजस्थान में साकुर खान मंगालियार, उत्तर प्रदेश के नौमान इलाही, और अन्य कई सामान्य दिखने वाले लोग भी जांच के घेरे में हैं। ये सभी मामले एक गंभीर वास्तविकता को उजागर करते हैं: आंतरिक सुरक्षा का खतरा, हर रूप में मौजूद है।

इन गिरफ्तारियों से यह सवाल उठता है कि क्या देश की सुरक्षा को केवल सीमाओं तक ही सीमित रखा जा सकता है? क्या घुसपैठिए केवल बॉर्डर से ही आते हैं? उत्तर प्रदेश के बरेली में हुई पूछताछ

में 51 संदिग्ध बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिक पकड़े गए। दिल्ली में पहलगाम हमले के बाद 520 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। इनमें से कई के पास नकली दस्तावेज़, बैंक खाते और सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने की जानकारी मिली। ये केवल प्रवासी नहीं थे - ये एक संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे।

इस संकट ने भारत-बांग्लादेश कूटनीतिक संबंधों को भी प्रभावित किया है। जब भारत ने 13 अवैध घुसपैठियों को सीमा पर लौटाया, तो बांग्लादेश ने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। ये लोग अब 'जीरो लाइन' पर फंसे हैं - न भारत उन्हें स्वीकार कर सकता है, न बांग्लादेश। यह न केवल एक मानवीय संकट है, बल्कि सीमा सुरक्षा की जटिलता का भी एक उदाहरण है।

भारत में चल रहा यह अदृश्य युद्ध अब डिजिटल क्षेत्र में भी घुस चुका है। WhatsApp, Telegram, YouTube, Facebook जैसे प्लेटफॉर्म अब केवल संवाद के माध्यम नहीं रहे, बल्कि विचारों को हथियार बनाने की प्रयोगशाला बन चुके हैं। कट्टरपंथी विचारधाराएं, फर्जी खबरें, सांप्रदायिक उन्माद फैलाने वाले वीडियो - इन सबका इस्तेमाल भारत की सामाजिक समरसता को तोड़ने के लिए हो रहा है। यह एक ऐसा डिजिटल रणक्षेत्र है, जहाँ हर क्लिक एक संभावित हथियार है।

इस डिजिटल युद्ध की आर्थिक धुरी है - क्रिप्टोकरेंसी, डार्क वेब और विदेशी फंडिंग। देश विरोधी गतिविधियों में लगे लोगों को अब पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंकों की ज़रूरत नहीं होती; क्रिप्टो वॉलेट्स और बिटकॉइन ही काफी हैं। NIA और ATS ने ऐसी कई ट्रांजैक्शन रिपोर्ट की हैं जो सीधे तौर पर भारत विरोधी संगठनों तक जाती हैं। यह आर्थिक आतंकवाद, देश की जड़ों को खोखला करने का एक नया तरीका है।

इन खतरों से निपटने के लिए देश की खुफिया एजेंसियों को और सशक्त बनाना अनिवार्य हो गया है। आज NIA, RAW, IB और राज्य स्तरीय ATS जैसे संस्थान पहले से कहीं अधिक चौकस हैं। उन्होंने दर्जनों ऑपरेशन चलाए हैं और कई नेटवर्कों को ध्वस्त किया है। लेकिन उनके पास संसाधन, तकनीकी सहायता और कानूनी दायरा सीमित है। हमें उनकी साइबर क्षमता, डेटा विश्लेषण दक्षता और ग्राउंड इंटेलिजेंस को आधुनिक तकनीकों से लैस करना होगा।

यह भी आवश्यक है कि राज्य पुलिस बलों को साइबर अपराध, संवेदनशील सूचना निगरानी और डिजिटल फॉरेंसिक की विशेष ट्रेनिंग दी जाए। पुलिस और खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल को और बेहतर बनाना होगा, ताकि सूचनाएं समय रहते साझा की जा सकें और कार्यवाही हो सके। यह समन्वय, इस अदृश्य युद्ध में हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।

इस संदर्भ में इज़राइल और अमेरिका जैसे देशों से भारत को सीख लेनी चाहिए। इज़राइल में हर नागरिक सुरक्षा का प्रहरी है - वह संदिग्धों की सूचना देने से नहीं हिचकता। अमेरिका और ब्रिटेन ने साइबर निगरानी और डिजिटल फॉरेंसिक में जो मॉडल खड़े किए हैं, वे भारत के लिए अनुकरणीय हैं। हमें उनसे सीखना होगा और अपने संदर्भ में उन्हें अपनाना होगा।

भारत को एक ऐसी 'सुरक्षा-संस्कृति' विकसित करनी होगी जिसमें हर नागरिक सतर्क हो, और हर संस्थान सजग। क्योंकि राष्ट्र की रक्षा केवल सरहद पर नहीं होती - वह होती है विचारों में, व्यवहार में और नागरिक चेतना में। हमें एक राष्ट्र के रूप में, हर पल जागरूक रहना होगा।

यदि हम आज चुप रहे, तो कल देश की आत्मा हमारी ही चुप्पी से घायल होगी। और तब, दुश्मन बंदूक से नहीं, हमारी भूलों से जीत जाएगा। यह एक ऐसा युद्ध है जिसे हम हार नहीं सकते। हमें एकजुट होकर, सजग रहकर, और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर लड़ना होगा। तभी हम अपनी अखंडता और संप्रभुता की रक्षा कर पाएंगे।

पाकिस्तान का बढ़ता रक्षा बजट (2.5 लाख करोड़) विवादों में है, जबकि देश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। भारत से तनाव के बीच रक्षा खर्च में 18% की वृद्धि, शिक्षा-स्वास्थ्य को कम आवंटन, और सेना के व्यावसायिक साम्राज्य (मिलबस) पर सवाल उठ रहे हैं। क्या पाकिस्तान की प्राथमिकताएँ सही हैं, या यह आर्थिक पतन की ओर बढ़ रहा है?

# पाकिस्तान किताबों पर राइफलें भारी

जलज श्रीवास्तव

पाकिस्तान का हालिया रक्षा बजट में 18% की बढ़ोतरी, इसे 2.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक तक पहुंचाना, काफी विवाद पैदा कर रहा है और देश की वित्तीय प्राथमिकताओं पर गंभीर सवाल उठा रहा है। यह फैसला तब आया है जब देश एक गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसमें आसमान छूती महंगाई (38% से अधिक), व्यापक बेरोजगारी और भारी सामाजिक अशांति शामिल है। ऐसे समय में, रक्षा खर्च पर इतनी बड़ी रकम का आवंटन पाकिस्तान की आर्थिक नीति के औचित्य पर सवाल उठाता है और सैन्य प्रतिष्ठान की गहरी पैठ वाली शक्ति और नागरिक कल्याण की उपेक्षा को उजागर करता है।

2025 के बजट में रक्षा खर्च में 18% की वृद्धि महज संयोग नहीं है। अप्रैल 2025 में भारत के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके जवाब में भारत द्वारा चलाए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद पाकिस्तान सैन्य संघर्ष में आ गया। भले ही यह पूर्ण युद्ध नहीं था, लेकिन इस चार दिन के 'लो इंटेसिव वार' ने इस्लामाबाद को हथियारों की ओर झुकने को मजबूर कर दिया, कारण कि भारत ने न केवल चीन और अमेरिका से प्राप्त वायु रक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया बल्कि उसके कई लड़ाकू विमानों को जमींदोज कर दिया।

लेकिन क्या यह फैसला तात्कालिक भू-राजनीतिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया है, या यह एक गहरे स्तर पर जमी, लंबी अवधि की सैन्य-केंद्रित नीति का प्रतिबिंब है? जब अस्पतालों में जरूरी दवाओं की कमी है, स्कूलों में योग्य शिक्षकों का अभाव है, और लाखों नागरिक बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो इस भारी-भरकम रक्षा बजट में बढ़ोतरी को कैसे सही ठहराया जा सकता है?

सकल घरेलू उत्पाद बनाम प्राथमिकताएं: एक बिगड़ा हुआ संतुलन। वित्त वर्ष 2025 के लिए पाकिस्तान का रक्षा खर्च उसके सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 2.3% है। यह आंकड़ा भारत (1.9%), चीन (1.7%) और यहां तक कि यूरोपीय संघ के औसत (1.5%) से भी अधिक है। पाकिस्तान की गहरी आर्थिक संकट की स्थिति को देखते हुए यह बेहिसाब आवंटन विशेष रूप से चिंताजनक है।

इसके विपरीत, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को क्रमशः केवल 2% और 1.3% जीडीपी आवंटित किया गया है। यह भारी असमानता स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि कैसे पाकिस्तान अपने नागरिकों की बुनियादी जरूरतों और कल्याण की कीमत पर सैन्य प्रतिष्ठान को प्राथमिकता देता है। यह तिरछा आवंटन अविकसितता और सामाजिक असमानता के चक्र को कायम रखता है।

'मिलबस': एक समानांतर अर्थव्यवस्था। पाकिस्तान में, सेना का प्रभाव पारंपरिक रक्षा गतिविधियों से कहीं आगे तक फैला हुआ है; यह एक विशाल और व्यापक व्यावसायिक साम्राज्य का संचालन करती है। इस प्रणाली को अक्सर ₹मिलबस₹ (मिलिट्री बिजनेस) कहा जाता है, जिसका विस्तृत विवरण आयशा सिद्दीका ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक, मिलिट्री इंक. में दिया है।

फौजी फाउंडेशन, बहरिया फाउंडेशन, आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और डीएचए (डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी) जैसे संस्थान महज धर्मार्थ न्यास नहीं हैं। इसके बजाय, वे बहु-क्षेत्रीय वाणिज्यिक उद्यम हैं जो सीधे सेना द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह नियंत्रण बैंकिंग, शिक्षा, कृषि, मीडिया, निर्माण और रियल एस्टेट सहित विभिन्न क्षेत्रों तक फैला हुआ है।

अनुमानों से पता चलता है कि सेना पाकिस्तान की लगभग 12% भूमि को नियंत्रित करती है। इन सैन्य-संचालित उद्योगों को कर छूट और तरजीही सरकारी व्यवहार से लाभ होता है, जिससे निजी क्षेत्र दब जाता है। इन कार्यों की अपारदर्शिता उन्हें जवाबदेही से भी बचाती है, जिससे आर्थिक विकृतियां और बढ़ जाती हैं।

विदेशी ऋण और आत्मनिर्भरता का भ्रमः पाकिस्तान की आर्थिक भेद्यता विदेशी ऋण और सहायता पर उसकी भारी निर्भरता से रेखांकित होती है। आईएमएफ के अनुसार, पाकिस्तान का ऋण-से-जीडीपी अनुपात लगभग 73.6% है, और उसका विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से तीन महीने के आयात को कवर करता है।

2024 में, पाकिस्तान का व्यापार घाटा 25 बिलियन डॉलर के चौंका देने वाले आंकड़े पर पहुंच गया, और यहां तक कि आईएमएफ से 7 बिलियन डॉलर का बेलआउट पैकेज भी कड़ी शर्तों के साथ आता है। इन वित्तीय बाधाओं के बावजूद, सेना के बुनियादी ढांचे, बजट या विस्तार परियोजनाओं पर कोई स्पष्ट प्रतिबंध नहीं हैं।

यह स्पष्ट विरोधाभास बताता है कि पाकिस्तान की रक्षा नीति मुख्य रूप से वास्तविक ₹राष्ट्रीय सुरक्षा₹ की चिंताओं से नहीं, बल्कि अपनी शक्ति और आर्थिक प्रभुत्व को बनाए रखने में सैन्य प्रतिष्ठान के निहित स्वार्थ से प्रेरित है। राष्ट्र के सीमित संसाधनों को रणनीतिक रूप से सेना के वित्तीय साम्राज्य को बनाए रखने के लिए मोड़ दिया जाता है।

आतंकवादः सेना के लिए वरदान या जनता के लिए अभिशाप? पाकिस्तान के आंतरिक क्षेत्रों में आतंकवाद और उग्रवाद के लगातार मुद्दे विरोधाभासी रूप से सेना की स्थिति को मजबूत करते हैं। बार-बार होने वाले आतंकवादी हमले और बाद में सैन्य प्रतिक्रियाएं सशस्त्र बलों को राष्ट्र के ₹रक्षक₹ के रूप में चित्रित करने की अनुमति देती हैं, जिससे नागरिक सरकारों को वास्तविक नियंत्रण का दावा करने से रोका जाता है।

सेना ने अक्सर भारतीय कश्मीर में घटनाओं और

बढ़े हुए भारत-पाकिस्तान तनाव का लाभ रक्षा बजट में वृद्धि को सही ठहराने के लिए उठाया है। यह पैटर्न ₹संकट-प्रबंधन रणनीति₹ नहीं बल्कि ₹संकट-निर्माण रणनीति₹ को दर्शाता है, जहां चल रहे सुरक्षा खतरों का उपयोग रणनीतिक रूप से सैन्य शक्ति और संसाधनों को मजबूत करने के लिए किया जाता है।

सामाजिक क्षय और युवा निराशा। पाकिस्तान के युवा, जो आबादी का 64% (30 वर्ष से कम) हैं, लगातार बेरोजगारी, आसमान छूती महंगाई और शिक्षा तक अपर्याप्त पहुंच का सामना कर रहे हैं। यह जनसांख्यिकी, जो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश हो सकती थी, को सरकार और सेना की गुमराह प्राथमिकताओं द्वारा जनसांख्यिकीय बोझ में बदल दिया गया है।

स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, अस्पताल पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में असमर्थ हैं, विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के लिए धन की कमी है, फिर भी सेना लगातार नई परियोजनाओं और विस्तार के लिए धन सुरक्षित करती है। इससे युवा पीढ़ी में निराशा और हताशा का एक गहरा भाव पैदा होता है, जो अपने अवसरों को कम होते हुए देखते हैं जबकि सेना का प्रभाव बढ़ता रहता है।

क्या यह मॉडल टिकाऊ है? इतिहास पर्याप्त प्रमाण प्रदान करता है कि अकेले सैन्य शक्ति किसी राष्ट्र की दीर्घकालिक सफलता और स्थिरता की गारंटी नहीं दे सकती है। सोवियत संघ, म्यांमार और यहां तक कि आधुनिक उत्तर कोरिया भी चेतावनी के उदाहरण के रूप में काम करते हैं। किसी राष्ट्र की सच्ची सुरक्षा उसके नागरिकों की भलाई पर निर्भर करती है, न कि केवल सैन्य शक्ति पर। यदि किसी राष्ट्र के नागरिक भूख, अशिक्षा और व्याप्त असमानता के

बीच रहते हैं, तो उसकी कथित सुरक्षा केवल एक भ्रम है।

जब तक पाकिस्तान अपने रक्षा बजट और मिलबस प्रणाली का मौलिक पुनर्मूल्यांकन नहीं करता है, तब तक उसकी आर्थिक स्थिति बिगड़ती रहेगी और उसकी आंतरिक स्थिरता को बढ़ते खतरे का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अस्तित्व के लिए प्राथमिकताओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव आवश्यक है।

निष्कर्षः बंदूकें शांत हों तो स्कूल की घंटियाँ जोर से बजें। पाकिस्तान की वर्तमान प्राथमिकताएँ न केवल आर्थिक रूप से गलत हैं, बल्कि नैतिक रूप से भी त्रुटिपूर्ण हैं। एक राष्ट्र जो अपने बजट का एक असमानुपाती हिस्सा सेना को आवंटित करता है, जबकि स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सामाजिक कल्याण की उपेक्षा करता है, वह प्रभावी रूप से अपने ही नागरिकों के भविष्य को कमजोर कर रहा है।

शांति, कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता के माध्यम से बढ़ते तनाव को संबोधित करने के बजाय भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल होने का विकल्प चुनने से न तो पाकिस्तान सुरक्षित होगा और न ही समृद्ध होगा।

एक आधुनिक, लोकतांत्रिक और समावेशी राष्ट्र बनने के लिए पाकिस्तान को एक आदर्श बदलाव अपनाना होगा- ₹राइफलों की तुलना में किताबों और दवाओं में अधिक निवेश करना।₹ केवल अपने नागरिकों की भलाई को प्राथमिकता देकर ही पाकिस्तान वास्तव में एक सुरक्षित और समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकता है; अन्यथा, राष्ट्र के विघटन का खतरा है, चाहे बंदूकें चलाई जाएं या नहीं। जैसा कि विश्व बैंक और आईएमएफ ने बार-बार जोर दिया है, स्थायी शांति और विकास के लिए एक संतुलित दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो सैन्य व्यय पर मानव पूंजी को प्राथमिकता देता है।

यह विश्लेषण केवल पाकिस्तान की नीतियों की आलोचना नहीं है, बल्कि मानवता और विकास की आवाज को सैन्यीकरण के शोर से डूबने से रोकने की एक विनती भी है। राष्ट्र के अस्तित्व के लिए प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन महत्वपूर्ण है।

भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ अमेरिकी संबंधों के विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन के साथ संजीव कुमार बरुआ ने हाल ही में भारत-पाकिस्तान संघर्ष और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख के संदर्भ में संयुक्त राज्य अमेरिका के रणनीतिक दृष्टिकोण की पड़ताल करने के लिए एक साक्षात्कार किया। यह साक्षात्कार, वाशिंगटन, डी.सी. स्थित प्रतिष्ठित दक्षिण एशिया मामलों के विश्लेषक माइकल कुगलमैन के साथ किया गया था, जिसे मूल रूप से द वीक में प्रकाशित किया गया था। इस चर्चा में भारत की रणनीतिक स्थिति के बारे में अमेरिकी धारणाओं की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, इसलिए हम व्यापक विद्वानों की भागीदारी और सार्वजनिक विमर्श को सुविधाजनक बनाने के लिए कल्ट करंट के इस संस्करण में साक्षात्कार को पुनर्प्रकाशित कर रहे हैं।

# ट्रम्प की टिप्पणी, अमेरिकी नीति नहीं: कुगलमैन

**साक्षात्कारकर्ता: संजीव कुमार बरुआ**

**प्रश्न: भारत ने भारत-पाक संघर्षविराम का श्रेय लेने के राष्ट्रपति ट्रम्प के दावे पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है। आपके अनुसार क्या निर्देशित कर रहा है? उनकी भारत-पाक रणनीति क्या है?**

**कुगलमैन:** मुझे नहीं लगता कि यह दृष्टिकोण इतना रणनीतिक है। यह शायद ट्रंप का भारत-पाकिस्तान संबंधों की जटिलता और दुस्साध्यता से आकर्षित होने का मामला है, और वे इसे सुलझाना चाहते हैं। आखिरकार, वह ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को अंतिम सौदागर के रूप में देखना पसंद करते हैं। जब वे एक हजार साल के संकट की बात करते हैं, तो यह अतिशयोक्ति शायद उनकी उस भावना को व्यक्त करती है कि यह एक गंभीर चुनौती है जिसे वे ठीक करने की कोशिश करना चाहेंगे। वे हमेशा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो पहले किसी ने न किया हो।

**प्रश्न: यह भी लग रहा है कि ट्रंप भारत को कमजोर कर रहे हैं। आपकी राय क्या है?**

**कुगलमैन:** निश्चित रूप से, ट्रंप की टिप्पणियां नई दिल्ली में अच्छी नहीं लगेंगी, क्योंकि भारत अपने

द्विपक्षीय मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप को लेकर हमेशा से संवेदनशील रहा है, खासकर तब जब यह हस्तक्षेप सार्वजनिक रूप से किया जाए। अब सबसे अहम सवाल यह है कि भारत सरकार इस पर कैसी प्रतिक्रिया देती है। यदि भारत इसे सिर्फ ₹ट्रंप तो ट्रंप हैं₹ कहकर नज़रअंदाज़ कर देता है, और इसे उनकी अप्रत्याशितता और वास्तविक अमेरिकी नीति से अलग हटकर बिना सोचे-समझे कुछ भी बोल देने की आदत समझता है, तो संभावित नुकसान कम होगा। लेकिन, यदि ट्रम्प इस तरह की टिप्पणियां बार-बार करते रहते हैं, और अमेरिकी प्रशासन वास्तव में भारत और पाकिस्तान दोनों को बातचीत करने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने लगता है, तो भारत-अमेरिका संबंधों में कुछ तनाव आ सकता है। इसलिए यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत इस पूरी स्थिति को कैसे संभालता है और किस तरह की प्रतिक्रिया देता है।

**प्रश्नः एक प्रबल भावना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प की हालिया घोषणाओं ने भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ दिया है। नई दिल्ली का कहना है कि पीड़ित और अपराधी को समान नहीं माना जा सकता। क्या वाशिंगटन में इसके पीछे कोई सोच है?**

**कुगलमैनः** ऐसा नहीं लगता है कि ट्रंप की हालिया टिप्पणियों ने भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ दिया है, जो वास्तव में अमेरिकी नीति के संदर्भ में कई दशकों से नहीं हुआ है। हालांकि, मैं कहूंगा कि ट्रम्प ने जो कहा वह अमेरिकी नीति को बिल्कुल नहीं दर्शाता है। हमें ट्रम्प की हालिया टिप्पणियों को बिना सोचे-समझे की गई टिप्पणियों के रूप में लिया जाना चाहिए। अमेरिकी नीति में बदलाव की संभावना नहीं है; हम फिर से दोनों देशों को एक साथ जोड़े जाने की संभावना नहीं देखते हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प की अधिकांश टिप्पणियां इस तथ्य को दर्शाती हैं कि उन्हें अमेरिकी नीति में भारत-पाकिस्तान संबंधों के संदर्भ में ज्यादा जानकारी नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि हमने, ट्रम्प ने जो कहा उससे संबंधित कुछ भी कहते हुए किसी अन्य अमेरिकी अधिकारी को नहीं देखा या सुना है। इससे यह स्पष्ट होता है कि अमेरिकी नीति में इस अर्थ में बदलाव नहीं हुआ है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को अलग-अलग पटरियों पर आगे बढ़ाएगा, भले ही हम देख रहे हैं कि अमेरिका-भारत संबंधों में कुछ तनाव आ गया है, जबकि अमेरिका-पाकिस्तान संबंधों में आश्चर्यजनक रूप से बढ़ावा मिला है। ऐसा लगता है कि हम जल्द सामान्य स्थिति की वापसी देखेंगे कि अमेरिका-भारत संबंधों को बढ़ावा दिया जाएगा और अमेरिका-पाकिस्तान संबंध ₹व्यवहार्य लेकिन सीमित संबंध₹ बने रहेंगे। वाशिंगटन और नई दिल्ली दोनों के दृष्टिकोण से इस साझेदारी को सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी रणनीतिक और वाणिज्यिक अनिवार्यताएं हैं। अब अगर ट्रम्प कश्मीर से जुड़े

क्वाड यह एक ऐसी इकाई है जिसकी ताकत चीन का मुकाबला करने के साझा रणनीतिक लक्ष्य से मिलती है। यह हाल के संकट या ट्रम्प की हालिया टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा।

मुद्दों पर अपनी टिप्पणियों को दोहराते हैं, तो निश्चित रूप से इससे नई दिल्ली के लिए चीजें और मुश्किल हो जाएंगी।

**प्रश्नः ऐसा भी लग रहा है कि अमेरिका अपने सहयोगी देशों और विरोधी देशों, दोनों के साथ एक जैसा व्यवहार कर रहा है। उदाहरण के तौर पर टैरिफ (शुल्क) का मुद्दा लें। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने से इनकार करके, यानी अवज्ञा दिखाकर, भारत की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त किया है, जबकि भारत ने हमेशा अमेरिका के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाने की कोशिश की है। क्या अमेरिका अपने सहयोगी देशों को उनकी वफादारी का सही मूल्य नहीं दे रहा है?**

**कुगलमैनः** यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि ट्रम्प एक विद्रोही स्वभाव के व्यक्ति हैं, जो अमेरिकी नेताओं के लिए असामान्य और अपरंपरागत हैं। अन्य अमेरिकी राष्ट्रपतियों की तरह, वे सहयोगी देशों, भागीदारों, प्रतिद्वंद्वियों और प्रतिस्पर्धियों के साथ तयशुदा नियमों के अनुसार व्यवहार नहीं करते। यह सच है कि वे चीन को एक प्रतिस्पर्धी राष्ट्र मानते हैं और उन्होंने कई स्तरों पर चीन के साथ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया भी है। उन्होंने ईरान को भी अपने पूर्ववर्तियों की तरह एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखा है, लेकिन रूस जैसे अन्य मामलों में स्पष्ट रूप से मतभेद रहे हैं।

वास्तव में, राष्ट्रपति ट्रम्प ने यह संकेत दिया है कि यूरोप और पूर्वी एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों के साथ संबंध उतने अटूट नहीं हैं, जितना कि वे प्रतीत होते हैं। ट्रम्प रणनीतिक साझेदारियों की पारंपरिक धारणा में विश्वास नहीं रखते। उनके लिए, हर चीज का महत्व सिर्फ लेन-देन पर आधारित है, और इसी दृष्टिकोण से उन्हें दुनिया को समझने में मदद मिलती है। उनकी विदेश नीति लेन-देन संबंधी विचारों से निर्देशित होती है, जिसका मतलब यह है कि चाहे कोई देश अमेरिका का मित्र हो या विरोधी, कई मामलों में, खासकर व्यापारिक मुद्दों पर, दोस्त और दुश्मन के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं होती। हमने टैरिफ के मामले में यह देखा है। वास्तव में, अमेरिका के कुछ सबसे करीबी सहयोगी भी टैरिफ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रम्प का मानना है कि ऐसा करके अमेरिका अपने आर्थिक हितों को सुरक्षित रख सकता है। वे इस दृष्टिकोण में लेन-देन संबंधी लाभ देखते हैं।

**प्रश्नः क्वाड्रीलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग ने भी इस संघर्ष के दौरान सक्रिय रुख नहीं अपनाया। इसलिए, क्वाड का भविष्य क्या है?**

ट्रम्प रणनीतिक साझेदारियों की पारंपरिक धारणा में विश्वास नहीं रखते। उनके लिए, हर चीज का महत्व सिर्फ लेन-देन पर आधारित है, और इसी दृष्टिकोण से उन्हें दुनिया को समझने में मदद मिलती है। उनकी विदेश नीति लेन-देन संबंधी विचारों से निर्देशित होती है, जिसका मतलब यह है कि चाहे कोई देश अमेरिका का मित्र हो या विरोधी, कई मामलों में, खासकर व्यापारिक मुद्दों पर, दोस्त और दुश्मन के बीच की रेखा उतनी स्पष्ट नहीं होती।

**कुगलमैनः** क्वाड ठीक रहेगा। यह एक ऐसी इकाई है जिसकी ताकत चीन का मुकाबला करने के साझा रणनीतिक लक्ष्य से मिलती है। यह हाल के संकट या ट्रम्प की हालिया टिप्पणियों से प्रभावित नहीं होगा।

**प्रश्नः राष्ट्रपति ट्रम्प को सनकी माना जाता है। क्या यह एक बनाई हुई छवि है?**

**कुगलमैनः** वह छवि ट्रम्प के लिए सहायक हो सकती है, क्योंकि यह अमेरिकी सहयोगियों और विरोधियों दोनों को चौकन्ना रखती है। एक ऐसे नेता के लिए जो लेन-देन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रभाव का उपयोग करने के बारे में है, यह बहुत सहायक हो सकता है।

**प्रश्नः क्या पाकिस्तान के प्रति नीति में बदलाव आएगा?**

**कुगलमैनः** हमें ट्रम्प की हालिया टिप्पणियों को अमेरिकी नीति में किसी बड़े बदलाव का संकेत नहीं मानना चाहिए। अंततः, अमेरिका और भारत के हित अक्सर एक दूसरे के साथ मेल खाते हैं, जो कि अमेरिका और पाकिस्तान के मामले में कम होता है। अमेरिका, पाकिस्तान के साथ सीमित सहयोग तो जारी रखेगा, लेकिन भारत के साथ उसके संबंध कहीं अधिक गहरे और महत्वपूर्ण हैं।

यह साक्षात्कार बांग्लादेश से संचालित weeklyblitz.net पोर्टल पर प्रकाशित है।

# ISKP v/s BLA

# एक भू-राजनीतिक दुष्चक्र

संदीप कुमार

**आईएसकेपी द्वारा बलूचिस्तान में बीएलए के खिलाफ युद्ध घोषणा ने पाकिस्तान के आंतरिक हालातों को जटिल बना दिया है। यह कट्टरपंथी बनाम राष्ट्रवादी टकराव देश और क्षेत्र के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती पेश करता है, जिससे अस्थिरता बढ़ने की आशंका है।**

इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत (आईएसकेपी) द्वारा बलूचिस्तान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के विरुद्ध हाल ही में की गई युद्ध घोषणा, पाकिस्तान के आंतरिक हालातों को और अधिक जटिल बना देती है। यह मात्र एक आंतरिक संघर्ष नहीं है, बल्कि इसके दूरगामी भू-राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं, विशेषकर बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वाह (केपी), अफगानिस्तान और ईरान के समीपवर्ती क्षेत्रों में। पाकिस्तान, जो पहले से ही राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और आतंकवाद की चुनौतियों से जूझ रहा है, एक नए और खतरनाक मोड़ पर खड़ा है। यह घटनाक्रम न केवल पाकिस्तान की सुरक्षा के लिए एक चुनौती है, बल्कि यह पूरे क्षेत्र में अस्थिरता को और बढ़ा सकता है। इस विषम परिस्थिति का विश्लेषण, पाकिस्तान के मौजूदा सुरक्षा परिदृश्य, दोनों संगठनों के वैचारिक और रणनीतिक मतभेदों, और

क्षेत्रीय-वैश्विक शक्तियों की भूमिका को ध्यान में रखकर ही किया जा सकता है। यह आलेख, इस जटिल स्थिति की परतों को खोलने और भविष्य की संभावित दिशाओं का आकलन करने का प्रयास है।

दरअसल, इस संघर्ष की जड़ में दो विपरीत विचारधाराओं वाले संगठनों का टकराव है, जिनकी विचारधाराएं और उद्देश्य एक दूसरे के विपरीत हैं। बीएलए और आईएसकेपी के बीच संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है, बल्कि यह धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद और कट्टरपंथी इस्लामी विचारधारा के बीच एक गहरा वैचारिक युद्ध है। बीएलए (बलूच लिबरेशन आर्मी) एक धर्मनिरपेक्ष, राष्ट्रवादी संगठन है, जो बलूचिस्तान की स्वायत्तता या पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करता है। यह संगठन, पाकिस्तानी सेना और चीनी निवेश (विशेषकर सीपीईसी परियोजनाओं) का विरोध करता है, जिन्हें वे बलूच संसाधनों का शोषण और सांस्कृतिक पहचान के लिए खतरा मानते हैं। बीएलए का मुख्य उद्देश्य, बलूच पहचान और संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करना है, और वे बलूचिस्तान के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने का दावा करते हैं। बीएलए का उदय, बलूचिस्तान में लंबे समय से चले आ रहे भेदभाव और राजनीतिक हाशिएकरण के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में हुआ है। वहीं आईएसकेपी (इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रांत) एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन है, जिसका उद्देश्य 'खिलाफत' की स्थापना करना है। यह संगठन न केवल पाकिस्तान सरकार को अपना दुश्मन मानता है, बल्कि तालिबान, शिया समुदाय, सूफियों और अब बलूच राष्ट्रवादियों को भी इस्लाम के दुश्मन मानता है। आईएसकेपी का मानना है कि केवल इस्लामी कानून (शरीयत) के तहत शासित होने वाला एक वैश्विक खिलाफत ही सच्चा शासन हो सकता है। यह संगठन, पश्चिमी मूल्यों, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र को खारिज करता है।

आईएसकेपी, बीएलए जैसे धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्रवादी आंदोलनों को 'इस्लाम विरोधी' मानता है, क्योंकि वे राष्ट्रीय सीमाओं और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, जो आईएसकेपी के वैश्विक खिलाफत के विचार के खिलाफ हैं। आईएसकेपी, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद को इस्लाम की शिक्षाओं के विपरीत मानता है। इसलिए, आईएसकेपी ने बीएलए के खिलाफ युद्ध की घोषणा की है, जिसे वे ₹इस्लाम के दुश्मनों₹ के खिलाफ एक धार्मिक कर्तव्य मानते हैं। आईएसकेपी, बीएलए को पश्चिमी शक्तियों द्वारा समर्थित एक कठपुतली संगठन के रूप में देखता है।

आईएसकेपी द्वारा युद्ध की इस घोषणा से पाकिस्तान के दो प्रमुख संवेदनशील प्रांतों - बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वाह - में अशांति की एक नई लहर आएगी, जिससे पहले से ही अस्थिर इन क्षेत्रों में स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। बलूचिस्तान और केपी, पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण प्रांत हैं, लेकिन ये प्रांत लंबे समय से अस्थिरता और हिंसा से जूझ रहे हैं। आईएसकेपी और बीएलए के बीच संघर्ष, इन क्षेत्रों में पहले से मौजूद जटिल सुरक्षा चुनौतियों को और बढ़ा देगा। बलूचिस्तान पहले से ही पाकिस्तानी सेना और बीएलए,बीआरएएस जैसे बलूच विद्रोही संगठनों से मिल रही चुनौतियों का सामना कर रही है। इसके अतिरिक्त, चीनी परियोजनाएं (सीपीईसी) पहले से ही हमलों के निशाने पर हैं, क्योंकि बलूच राष्ट्रवादी इन परियोजनाओं को अपने संसाधनों का शोषण और स्थानीय समुदायों के लिए हानिकारक मानते हैं। अब आईएसकेपी की मौजूदगी एक तीसरा मोर्चा खोल सकती है, जो न केवल सैन्य दृष्टिकोण से चुनौतीपूर्ण है, बल्कि विदेशी निवेश को और डरा सकती है। यह क्षेत्र, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का मैदान बन सकता है, जिससे यहां की स्थिति और जटिल हो सकती है।

खैबर पख्तूनख्वाह प्रांत में पहले से ही टीटीपी (तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान) और आईएसकेपी दोनों सक्रिय हैं, जो अक्सर सरकारी बलों और नागरिक ठिकानों पर हमले करते रहते हैं। आईएसकेपी की बीएलए से दुश्मनी के चलते, अब अफगान सीमा से लगे इलाकों में भी हिंसक झड़पों की आशंका बढ़ गई है। इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सुरक्षा की स्थिति और

खराब हो सकती है, जिससे मानवीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। केपी में अस्थिरता, पूरे क्षेत्र में फैल सकती है।

इससे सुरक्षा बलों को दोतरफा संघर्ष का सामना करना पड़ेगा - एक तरफ कट्टरपंथी जिहादी संगठन, जो इस्लामी खिलाफत स्थापित करने के लिए दृढ़ हैं, और दूसरी ओर अलगाववादी राष्ट्रवादी आंदोलन, जो अपने संसाधनों और अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं।

आईएसकेपी और बीएलए के बीच संघर्ष, पाकिस्तान की सुरक्षा और राजनीतिक स्थिति पर गंभीर प्रभाव डाल सकता है। पाकिस्तान, पहले से ही कई आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहा है, और यह नया संघर्ष, पाकिस्तान को और अधिक अस्थिर देगा।

आईएसकेपी और बीएलए दोनों अलग-अलग रणनीति और नेटवर्क से काम करते हैं, जिससे पाकिस्तान की सेना के लिए एक साथ दो फ्रंट पर युद्ध जैसी स्थिति बन सकती है। सेना को दोनों संगठनों से निपटने के लिए अपनी सीमित संसाधनों को विभाजित करना होगा, जिससे उनकी प्रभावशीलता कम हो सकती है। सेना के लिए, इस संघर्ष का प्रबंधन करना एक बड़ी चुनौती होगी।

पहले से ही कमजोर लोकतंत्र, महंगाई, आईएमएफ की शर्तों और राजनीतिक विभाजन के कारण सरकार की स्थिति नाजुक है। इस स्थिति में आतंरिक संघर्ष और बदतर हो सकते हैं, जिससे सरकार को और अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार को देश को एकजुट रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाई हो सकती है। राजनैतिक अस्थिरता, विदेशी निवेश को और कम कर सकती है।

आईएसकेपी की बीएलए से लड़ाई पाकिस्तान सरकार के लिए तात्कालिक राहत जैसी दिख सकती है, क्योंकि यह दो दुश्मन ताकतों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करती है। लेकिन लंबे समय में यह और अधिक अस्थिरता का कारण बनेगी, क्योंकि यह क्षेत्र में जातीय और सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती है। इसके अतिरिक्त, यदि सरकार किसी एक समूह का समर्थन करती है, तो यह दूसरे समूह को और अधिक कट्टरपंथी बना सकती है। सरकार की यह रणनीति, क्षेत्र में दीर्घकालिक स्थिरता को कमजोर कर सकती है।

आईएसकेपी और बीएलए के बीच संघर्ष का क्षेत्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तान के पड़ोसी देशों पर इस संघर्ष का असर पड़ने की संभावना हैः

आईएसकेपी की जड़ें अफगानिस्तान में भी गहरी हैं, और यह तालिबान सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती बना हुआ है। आईएसकेपी और तालिबान के बीच लगातार संघर्ष दोनों देशों के बीच तनाव को बढ़ाता रहा है, खासकर यदि पाकिस्तान इस्लामिक स्टेट के खिलाफ संयुक्त ऑपरेशन की मांग करता है। तालिबान, आईएसकेपी को अपने शासन के लिए एक गंभीर खतरा मानता है, लेकिन वह पाकिस्तान के साथ सहयोग करने के लिए अनिच्छुक हो सकता है, क्योंकि वह इसे अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है। अफगानिस्तान में अस्थिरता, पूरे क्षेत्र में फैलने की क्षमता रखती है।

वहीं बलूचिस्तान, ईरान के सिस्तान-बलूचिस्तान क्षेत्र से सटा है, जहां पहले से ही अलगाववादी आंदोलन चल रहे हैं। आईएसकेपी की मौजूदगी से ईरान की चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि यह संगठन सीमा पार अपने प्रभाव का विस्तार करने की कोशिश कर सकता है। ईरान बलूचिस्तान में अस्थिरता को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। ईरान और पाकिस्तान के बीच सीमा सुरक्षा सहयोग और अधिक जटिल हो सकता है।

दूसरी ओर, सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में हैं, और बीएलए

पहले ही इन परियोजनाओं को निशाना बना चुका है। आईएसकेपी की सक्रियता इन परियोजनाओं को दोहरा खतरा बना सकती है, क्योंकि यह न केवल बीएलए से, बल्कि एक और आतंकवादी संगठन से भी खतरे का सामना करेंगी। चीन, सीपीईसी को अपनी बेल्ट एंड रोड पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानता है, और वह पाकिस्तान से इन परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और अधिक प्रयास करने की उम्मीद कर सकता है। चीन का बढ़ता हस्तक्षेप, क्षेत्र में और अधिक तनाव पैदा कर सकता है।

अगर बात करें भारत की तो भारत, बलूच मानवाधिकारों और पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का आलोचक रहा है। आईएसकेपी-बीएलए संघर्ष, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ 'बाहरी हाथ होने' का बहाना देगा, जिससे दक्षिण एशिया में कूटनीतिक तनाव और बढ़ेगा। पाकिस्तान, भारत पर क्षेत्र में अस्थिरता भड़काने का आरोप लगाता रहा है, जिससे दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंध और खराब हो सकते हैं। यह क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान के बीच एक प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बन सकता है।

इस जटिल स्थिति में भविष्य के लिए कई परिदृश्य उभर सकते हैं। यह संघर्ष, किस दिशा में आगे बढ़ेगा, यह कहना मुश्किल है, लेकिन निम्नलिखित तीन परिदृश्य, भविष्य की संभावित दिशाओं का संकेत देते हैं- पहले परिदृश्य में, आईएसकेपी और बीएलए के बीच संघर्ष और तीव्र हो जाता है, जिससे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वाह में व्यापक अराजकता फैल जाती है। पाकिस्तान इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन यह रणनीति, प्रतिकूल परिणामों को जन्म दे सकती है। नागरिक क्षेत्र, हिंसा की चपेट में आ जाएगा और क्षेत्र में मानवीय संकट पैदा हो सकता है। यह परिदृश्य, पाकिस्तान के लिए सबसे खराब स्थिति हो सकती है।

दूसरे परिदृश्य में, बीएलए और अन्य बलूच गुट आपसी सहयोग से एक नया 'गठबंधन' बना सकते हैं, जो आईएसकेपी के खिलाफ ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। इससे क्षेत्र में एक और अधिक शक्तिशाली और एकजुट विद्रोही ताकत पैदा हो सकती है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। यह परिदृश्य, पाकिस्तान के लिए एक दीर्घकालिक सुरक्षा चुनौती उत्पन्न कर सकता है।

तीसरे और अंतिम परिदृश्य में, पाकिस्तान, इन संगठनों को एक-दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करके ₹प्रॉक्सी युद्ध₹ मॉडल अपनाता है। यह रणनीति, पाकिस्तान के लिए और अधिक अस्थिरता और अराजकता पैदा कर सकती है। यह परिदृश्य, पाकिस्तान को एक गहरे दुष्चक्र में फंसा सकता है।

आईएसकेपी और बीएलए के बीच युद्ध की घोषणा, पाकिस्तान के लिए एक गंभीर भू-राजनीतिक और सुरक्षा चुनौती है। यह न केवल एक आंतरिक संघर्ष है, बल्कि इससे पाकिस्तान की क्षेत्रीय साख, निवेश माहौल, आर्थिक स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी गहरा असर पड़ेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वाह, अब सिर्फ सीमांत प्रांत नहीं, बल्कि भू-राजनीतिक युद्धभूमियाँ बन चुके हैं, जहां जिहाद, राष्ट्रवाद और सत्ता संघर्ष का त्रिकोण, पाकिस्तान की अखंडता और भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लगा रहा है। पाकिस्तान के लिए, इस स्थिति से निपटने के लिए एक व्यापक और सुसंगत रणनीति की आवश्यकता है, जो सैन्य, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को एकीकृत करती हो। पाकिस्तान को, क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने की भी आवश्यकता है। यदि पाकिस्तान इस चुनौती से निपटने में विफल रहता है, तो यह देश के लिए विनाशकारी परिणाम ला सकता है।

# ट्रंप का दांव, भारत का खेल
# तकनीकी वर्चस्व की दौड़

अनवर हुसैन

**ट्रम्प के दबाव के बावजूद, एपल का भारत में 1.5 बिलियन डॉलर का निवेश वैश्विक भू-राजनीति को मोड़ दे रहा है। क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक निर्णय है, या चीन से हटने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा? भारत के लिए ये स्वर्णिम अवसर है, अगर वो तकनीकी विकास पर ध्यान दे। क्या भारत इस मौके को भुना पाएगा?**

डोनाल्ड ट्रम्प के दोबारा अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद, उनकी अप्रत्याशित नीतियों और विवादित बयानों ने वैश्विक मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। टैरिफ युद्ध से लेकर अवैध प्रवासियों के मुद्दे तक, ट्रम्प की हर हरकत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हलचल मचाई है। हाल ही में मध्य पूर्व की यात्रा के दौरान, उन्होंने एपल के सीईओ टिम कुक पर अमेरिका में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए ज़ोर डाला। ट्रम्प ने खुले तौर पर चेतावनी दी कि यदि एपल भारत में बने उत्पादों को अमेरिका में बेचता है, तो उन पर 25 प्रतिशत तक का भारी टैरिफ लगाया जाएगा। यह प्रकरण, केवल एक व्यापारिक सुझाव नहीं था, बल्कि वैश्विक तकनीकी परिदृश्य को

दबाव के तत्काल बाद, एपल ने भारत में 1.5 बिलियन डॉलर के एक महत्वपूर्ण निवेश की घोषणा की। यह निवेश तमिलनाडु के ओरगडम में फॉक्सकॉन द्वारा डिस्प्ले मॉड्यूल निर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए समर्पित है। यह कदम न केवल भारत को एपल की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि एपल की रणनीति मात्र राजनीतिक दबाव के आगे झुकना नहीं है, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक दृष्टिकोण पर आधारित है।

ट्रम्प ने स्पष्ट रूप से कहा, ₹मैंने टिम कुक से कहा कि मैं चाहता हूं कि जो आईफोन्स अमेरिका में बेचे जाएं, वे अमेरिका में ही बने— भारत या कहीं और नहीं।₹ इस सीधे-सादे बयान के बावजूद, एपल का भारत में अपने निवेश को जारी रखने का दृढ़ संकल्प इस बात का प्रमाण है कि कंपनी रणनीतिक कारकों को महत्व देती है जो अमेरिका में विनिर्माण की तुलना में भारत को अधिक आकर्षक बनाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय लागत दक्षता, श्रम की उपलब्धता और एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला के दृष्टिकोण से व्यावसायिक रूप से पूर्णतः तर्कसंगत है।

वर्षों से, एपल का उत्पादन बड़े पैमाने पर चीन पर निर्भर रहा है। आईफोन जैसे प्रमुख उत्पाद शेनझेन में स्थित फॉक्सकॉन जैसे विशाल कारखानों में बनाए जाते हैं। हालांकि, अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते व्यापार युद्ध के कारण, अमेरिका की यह मंशा रही है कि टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन चीन पर अत्यधिक निर्भर न रहे। ट्रम्प के पिछले कार्यकाल में भी एपल पर अमेरिका में निर्माण के लिए दबाव डाला गया था, लेकिन कंपनी ने इस दिशा में सीमित कदम ही उठाए। ट्रम्प के दोबारा सत्ता में आने के बाद, यह दबाव और भी तीव्र हो गया है।

भारत अब एपल के लिए चीन के एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में तेजी से उभर रहा है। फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रोन जैसी प्रमुख कंपनियां पहले से ही भारत में अपनी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित कर चुकी हैं। 2023 में, एपल ने भारत में लगभग 14 बिलियन डॉलर

पुनर्गठित करने की एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा था। इस कहानी में भारत मात्र दर्शक नहीं है, बल्कि एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभर रहा है। सवाल यह है कि क्या ट्रम्प का यह दबाव भारत के लिए एक अभूतपूर्व अवसर लेकर आएगा या क्या भारत एक बार फिर वैश्विक शक्ति संतुलन का एक प्यादा बनकर रह जाएगा?

इस घटनाक्रम के समानांतर, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच, ट्रम्प ने एक अनचाहे मध्यस्थ की तरह हस्तक्षेप करते हुए सीजफायर का श्रेय लेने का प्रयास किया, जिसे भारत सरकार ने तत्परता से खारिज कर दिया। इस हस्तक्षेप से ट्रम्प की विश्वसनीयता को निश्चित रूप से ठेस पहुंची। हालांकि, इन भू-राजनीतिक उतार-चढ़ावों के बीच, यह उल्लेखनीय है कि ट्रम्प के

मूल्य के आईफोन का उत्पादन किया, जो न केवल आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि रणनीतिक दृष्टिकोण से भी भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

एपल चीन से अपनी निर्भरता अमेरिकी नीति के अनुसार ही कम की है, इसी वजह से यह भारत के लिए एक स्वर्णिम अवसर साबित हो रहा है। अमेरिका में निर्माण की लागत काफी अधिक है, जबकि भारत सस्ती श्रमशक्ति, राजनीतिक स्थिरता और एक अमेरिका-हितैषी विदेश नीति के साथ एक उपयुक्त विकल्प के रूप में उभर रहा है। यह एक ऐसा त्रिकोण है जो भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने की राह पर अग्रसर कर सकता है।

एपल का यह निर्णय भारत को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के मानचित्र पर एक प्रमुख स्थान दिलाने की क्षमता रखता है। हालांकि, इस अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाने के लिए, भारत को केवल उत्पादन पर ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि अनुसंधान और विकास, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन और श्रमिक कौशल जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण निवेश और सुधार करने होंगे। भारत को एक संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करना होगा जो नवाचार को प्रोत्साहित करे और वैश्विक मानकों को पूरा करे।

एपल द्वारा भारत में निवेश जारी रखने का निर्णय यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वैश्विक कंपनियाँ भारत को केवल एक अस्थायी विकल्प नहीं मान रही हैं, बल्कि एक दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदार के रूप में देख रही हैं। यह भारत के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिसे सही नीतियों और कुशल निष्पादन के माध्यम से पूरी तरह से भुनाया जा सकता है। इसके लिए, सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत को मिलकर काम करना होगा ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जो तकनीकी प्रगति और आर्थिक विकास को बढ़ावा दे।

ट्रम्प की रणनीति केवल आर्थिक नहीं है, बल्कि वैचारिक भी है। वह चाहते हैं कि अमेरिकी टेक कंपनियाँ केवल मुनाफा न कमाएं,

बल्कि अमेरिका की तकनीकी आत्मनिर्भरता और आर्थिक पुनरुत्थान का जरिया बनें। यह 'टेक्नोलॉजी संप्रभुता' का युग है, जहां डेटा, चिप्स, स्मार्टफोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी राष्ट्र की शक्ति के प्रतीक बन चुके हैं। ट्रम्प का यह दृष्टिकोण एक नई वैश्विक व्यवस्था की ओर इशारा करता है, जहां तकनीकी प्रभुत्व भू-राजनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है।

भारत को यह समझना होगा कि वह केवल एक 'लो-कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब' बनकर संतुष्ट न रहे, बल्कि तकनीकी नीति, नवाचार और अनुसंधान में भी अपनी पकड़ मजबूत करे। तभी वह इस वैश्विक पुनर्गठन में स्थायी और प्रभावी भूमिका निभा सकेगा। भारत को एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा जो अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करे, प्रतिभाओं को आकर्षित करे, और नवाचार को बढ़ावा दे।

यदि भारत, एपल जैसी कंपनियों को लॉजिस्टिक्स, नीति समर्थन और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला का मजबूत आधार देना जारी रखता है, तो वह अमेरिका की 'चीन से बाहर निकलने' की रणनीति का एक मुख्य स्तंभ बन सकता है। भारत को एक ऐसा अनुकूल वातावरण बनाना होगा जो विदेशी निवेश को आकर्षित करे और घरेलू उद्योगों को बढ़ने में मदद करे।

ट्रम्प का टिम कुक पर दबाव बनाना, एक बड़ी वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। यह उस अमेरिकी नीति का प्रतीक है जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र को अपने भू-राजनीतिक हितों के अनुरूप पुनर्परिभाषित कर रही है। भारत को इस रणनीति में केवल दर्शक नहीं, बल्कि निर्णायक भूमिका के लिए तैयार रहना चाहिए। भारत को एक सक्रिय और रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा ताकि वह वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके।

तमिलनाडु में स्थापित होने वाला नया प्लांट भारत में 14,000 नौकरियों का सृजन करेगा और देश को वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बना सकता है। इसके अतिरिक्त, फॉक्सकॉन को भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के तहत 2023-24 में 2,450 करोड़ (लगभग $295 मिलियन) की सब्सिडी भी मिली है, जो निवेश को और अधिक आकर्षक बनाती है।

भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और अमेरिका से प्रगाढ़ होते द्विपक्षीय संबंध इस दिशा में सहायक हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए भारत को 'विकासशील देश' की मानसिकता से ऊपर उठकर, एक 'तकनीकी नेतृत्वकर्ता राष्ट्र' की भूमिका निभानी होगी। भारत को एक ऐसा दृष्टिकोण अपनाना होगा जो नवाचार, अनुसंधान और विकास को प्राथमिकता दे और एक कुशल कार्यबल का निर्माण करे।

निष्कर्षतः, ट्रम्प के दबाव और एपल के निर्णयों के बीच, भारत को अपने दीर्घकालिक हितों की स्पष्ट समझ विकसित करनी होगी। यह वक्त है सक्रिय बनने का—दर्शक नहीं, निर्णायक की भूमिका निभाने का। भारत को वैश्विक तकनीकी परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करना होगा और एक रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा।

**अनवर हुसैन वरिष्ठ पत्रकार, लेखक एवं प्राध्यापक हैं।**

# अमेरिकी सुरक्षा पर चीन की छाया

चीन हिंद-प्रशांत में अमेरिकी विस्तारित प्रतिरोध को कमजोर करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपना रहा है। नैरेटिव गढ़ने, आर्थिक दबाव, ग्रे जोन टैक्टिक्स, सैन्य निर्माण और राजनयिक अलगाव के माध्यम से, चीन का लक्ष्य अमेरिकी विश्वसनीयता को कम करना और क्षेत्र में शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करना है, जिससे अमेरिकी सुरक्षा पर छाया पड़ रही है।

मनोजकुमार

इंडो-पैसिफिक का रणनीतिक परिदृश्य एक महत्वपूर्ण बदलाव से गुजर रहा है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्तारित प्रतिरोध (Extended Deterrence) की विश्वसनीयता को कम करने के उद्देश्य से चीन के व्यापक अभियान से प्रेरित है। यह सिद्धांत, जो संयुक्त राज्य अमेरिका को आक्रामकता के खिलाफ अपने सहयोगियों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध करता है, संभावित रूप से परमाणु हथियारों के साथ, बीजिंग द्वारा एक स्थिर शक्ति के रूप में नहीं देखा जाता है, बल्कि चीन के उत्थान को रोकने और इसके उचित प्रभाव क्षेत्र को सीमित करने के लिए डिज़ाइन किए गए एक उपकरण के रूप में देखा जाता है। जवाब में, चीन ने एक विषम युद्ध रणनीति अपनाई है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका की शक्ति और प्रभाव को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है, बिना किसी प्रत्यक्ष सैन्य टकराव को उकसाए। यह दृष्टिकोण कई प्रमुख अंतर-संबंधित क्षेत्रों में प्रकट होता है।

सबसे पहले, चीन सक्रिय रूप से स्थापित कथा को चुनौती देता है,

लगातार संयुक्त राज्य अमेरिका को क्षेत्र के भीतर एक अस्थिर करने वाली शक्ति के रूप में चित्रित करता है। हस्तक्षेप और धमकाने के आरोपों को रणनीतिक रूप से अमेरिकी सहयोगियों के निर्माण की नैतिक अधिकार को कमजोर करने के लिए तैनात किया जाता है। साथ ही, बीजिंग इस विचार को बढ़ावा देता है कि एशिया को अपने सुरक्षा मामलों का प्रबंधन स्वयं करना चाहिए, जिससे क्षेत्र की रणनीतिक संरचना में संयुक्त राज्य अमेरिका को भूमिका से स्पष्ट रूप से बाहर रखा जा सके।

दूसरा, आर्थिक लाभ का उपयोग सहयोगियों को प्रभावित करने के लिए कुशलता से किया जाता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के माध्यम से पेश की जाने वाली आकर्षक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के प्रलोभन को उन लोगों पर व्यापार प्रतिबंधों और बहिष्कार के साथ जोड़ा जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करते हैं या ऐसी नीतियां अपनाते हैं जिन्हें चीनी हितों के विपरीत माना जाता है। यह आर्थिक दबाव बीजिंग के शस्त्रागार में एक शक्तिशाली उपकरण का प्रतिनिधित्व करता है।

तीसरा, चीन सक्रिय रूप से उस में संलग्न है जिसे ग्रे ज़ोन युद्ध कहा जा सकता है। यह रणनीति विशेष रूप से समुद्री और साइबर डोमेन में स्पष्ट है, जहां चीनी तट रक्षक और समुद्री मिलिशिया को दक्षिण चीन सागर में संबद्ध जहाजों को परेशान करने के लिए तैनात किया जाता है। महत्वपूर्ण अमेरिकी बुनियादी ढांचे को लक्षित करने वाले साइबर हमले एक जबरदस्ती साधन के रूप में काम करते हैं, जो नुकसान पहुंचाने और हस्तक्षेप को रोकने के लिए बीजिंग की क्षमता का प्रदर्शन करते हैं।

चौथा, चीन एक त्वरित और दूरगामी सैन्य निर्माण कर रहा है। राष्ट्र पारंपरिक और परमाणु हथियारों के साथ-साथ साइबरस्पेस और अंतरिक्ष में उन्नत क्षमताओं में भारी निवेश कर रहा है। लक्ष्य क्षेत्रीय सैन्य प्रभुत्व हासिल करना है और, महत्वपूर्ण रूप से, आकस्मिक परिदृश्यों में अमेरिकी हस्तक्षेप को रोकना है, विशेष रूप से ताइवान पर संभावित संघर्ष। अमेरिकी सहयोगियों पर हमलों का अनुकरण करने वाले युद्ध खेलों और अभ्यासों का संचालन अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में शामिल होने के विश्वास को कम करने के लिए और अधिक डिज़ाइन किया गया है।

अंत में, चीन सक्रिय रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका को राजनयिक रूप से अलग करना चाहता है। इसमें ऑकस (AUKUS) जैसे गठबंधनों और क्षेत्र में मध्यवर्ती दूरी की मिसाइलों को तैनात करने की योजनाओं की मुखर आलोचना शामिल है। साथ ही, बीजिंग रूस के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर रहा है, अमेरिका के आधिपत्य को कमजोर करने और एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के सामान्य उद्देश्य को साझा कर रहा है।

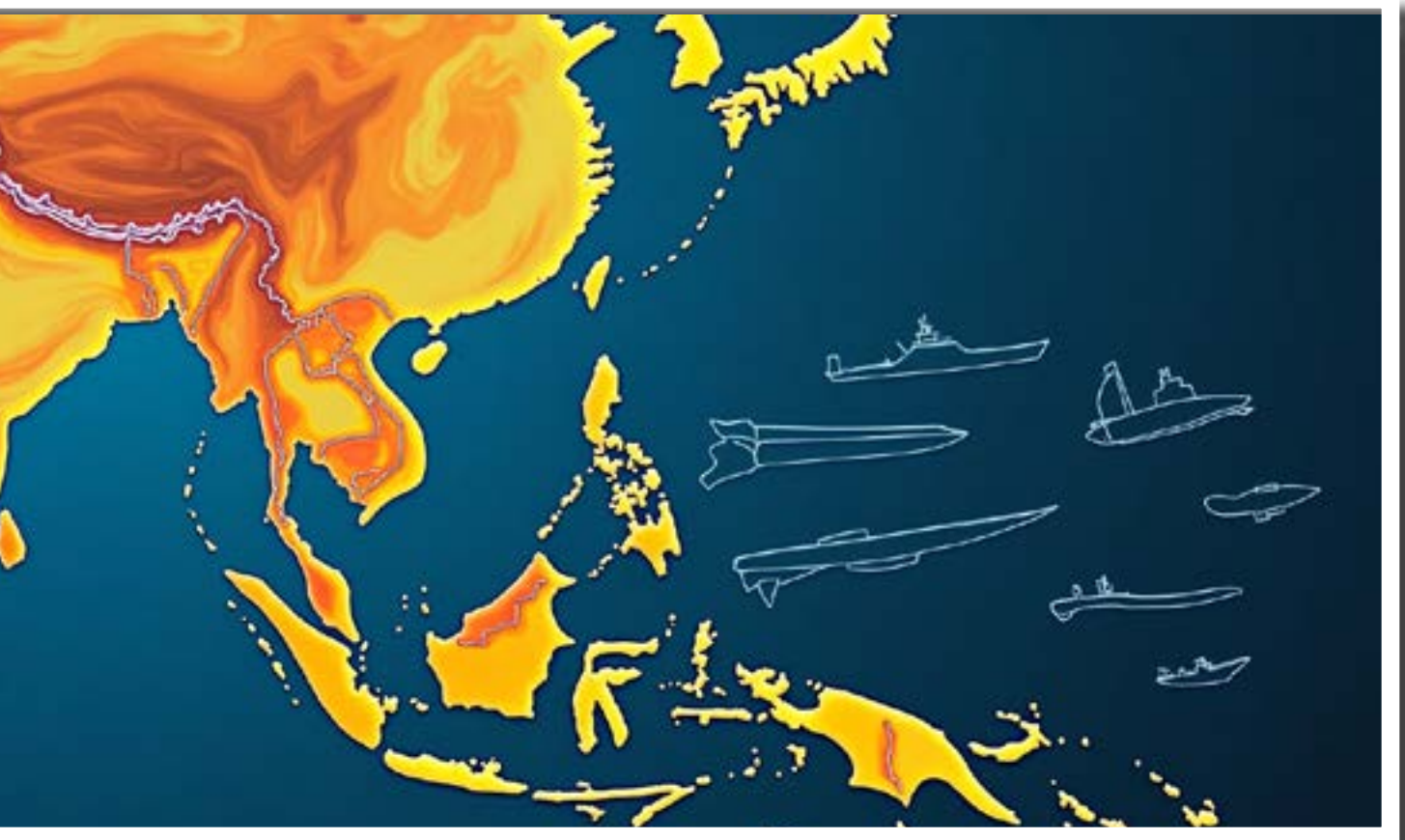

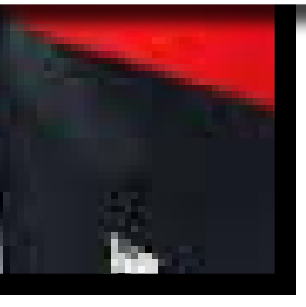

चीन की बहुआयामी रणनीति के निहितार्थ महत्वपूर्ण हैं। यदि सफल रहा, तो यह अमेरिकी सहयोगियों की ताकत को कमजोर कर सकता है, क्षेत्रीय अभिनेताओं को वाशिंगटन से स्वतंत्र रूप से अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, और अंततः इंडो-पैसिफिक में शक्ति संतुलन को चीन के पक्ष में स्थानांतरित कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चुनौती चीन की विषम युद्ध रणनीति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करना है, जबकि वृद्धि के जोखिमों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करना है।

प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका को सक्रिय रूप से कथा को आकार देना चाहिए, इंडो-पैसिफिक में एक स्थिर शक्ति के रूप में अपनी भूमिका का बचाव करना चाहिए और चीन की आक्रामक कार्रवाइयों को उजागर करना चाहिए। इसमें बीजिंग के सैन्य निर्माण, आर्थिक दबाव के इसके उपयोग और अंतरराष्ट्रीय कानून के इसके उल्लंघन पर ध्यान आकर्षित करना शामिल है। संयुक्त राज्य अमेरिका को साइबर हमलों और दुष्प्रचार के खिलाफ सुरक्षा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने और लचीलापन को बढ़ावा देने के माध्यम से अपने सहयोगियों और साझेदारी को भी मजबूत करना चाहिए। इसके अलावा, बिना पूर्ण पैमाने पर संघर्ष को बढ़ाए चीन की ग्रे ज़ोन रणनीति का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए नई सैन्य अवधारणाओं और क्षमताओं की आवश्यकता है। निवारक क्षमता को सुदृढ़ करना आवश्यक है, अमेरिकी सहयोगियों और हितों की रक्षा करने के लिए अमेरिकी संकल्प का प्रदर्शन, जिसमें अतिरिक्त सैन्य संपत्तियों की तैनाती और संयुक्त अभ्यास का संचालन शामिल है। अंत में, चीन और रूस के बीच बढ़ते सुरक्षा सहयोग को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, जो अमेरिकी सुरक्षा गारंटी को कमजोर करने के लिए उनके समन्वित प्रयासों का मुकाबला करने के लिए काम कर रहा है।

इंडो-पैसिफिक में अमेरिकी विस्तारित प्रतिरोध का भविष्य इसे कमजोर करने के लिए चीन के बहुआयामी अभियान का प्रभावी ढंग से जवाब देने की क्षमता पर निर्भर करता है। ऐसा करने में विफलता से इस क्षेत्र में अमेरिकी शक्ति, प्रभाव और समग्र सुरक्षा के लिए गंभीर परिणाम होंगे।

# आर्कटिक में भारत

## रूस संग नई राह

मनीष वैद

कभी बर्फ से आच्छादित रहने वाला आर्कटिक तेजी से एक भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक केंद्र में बदल रहा है। पिघलती बर्फ महत्वपूर्ण खनिजों, हाइड्रोकार्बन और रणनीतिक शिपिंग मार्गों के विशाल भंडार को उजागर कर रही है। जहां पश्चिम नाटो के उत्तरी विस्तार के माध्यम से आगे बढ़ रहा है, वहीं प्रतिबंधित रूस अपनी आर्कटिक क्षमता को अनलॉक करने के लिए भरोसेमंद भागीदारों की ओर रुख कर रहा है।

भारत के लिए, यह बदलाव एक दुर्लभ रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करता है। बढ़ती ऊर्जा जरूरतों, महत्वपूर्ण खनिज महत्वाकांक्षाओं और बहुध्रुवीय जुड़ाव की इच्छा के साथ, भारत आर्कटिक में एक प्रतियोगी के रूप में नहीं, बल्कि रूस

ये सभी फोटो प्रतीकात्मक है।

के भागीदार के रूप में प्रवेश कर सकता है, जो आर्कटिक तटरेखा के आधे से अधिक और इसके सबसे समृद्ध अप्रयुक्त संसाधनों का संरक्षक है।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ ईंधन की खोज को रूस की आर्कटिक एलएनजी (तरलीकृत प्राकृतिक गैस) महत्वाकांक्षाओं में एक रणनीतिक मेल मिलता है। जबकि यामल एलएनजी ने परिचालन रूप से सफल साबित किया है, आर्कटिक एलएनजी-2 परियोजना, जो लंबे समय से पश्चिमी प्रतिबंधों से बाधित है, अब एक संभावित महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी है। ऑक्सफोर्ड एनर्जी द्वारा नोट किए गए डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के बाद अमेरिका-रूस संबंधों में आई नई नरमी ने प्रमुख आर्कटिक ऊर्जा संपत्तियों पर प्रतिबंधों को कम करने की संभावनाएं खोल दी हैं।

भारत के लिए, यह बदलता परिदृश्य आर्कटिक एलएनजी बुनियादी ढांचे में निवेश करके, दीर्घकालिक गैस आपूर्ति सुरक्षित करके और उभरते आर्कटिक व्यवस्था को आकार देने में खुद को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में स्थापित करके रूस के ध्रुवीय धुरी में अपनी भूमिका को गहरा करने का एक समय पर अवसर प्रदान करता है।

यामल एलएनजी सुविधा, जो 2023 से क्षमता से 20% ऊपर संचालित हो रही है, ने 2017 से एलएनजी के 100 मिलियन टन से अधिक उत्पादन करके रूस की आर्कटिक उपस्थिति को मजबूती से स्थापित किया है। भारत के लिए, यह ऊर्जा सुरक्षा लाभ में तब्दील हो गया है, जिसमें गेल ने गजप्रोम मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग सिंगापुर के माध्यम से 2.85 एमटीपीए के लिए दीर्घकालिक अनुबंध हासिल किए हैं। ट्रांसशिपमेंट पर यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के बावजूद, वैश्विक अस्थिरता से बचाव और अपनी गैस-आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की भारत की आपूर्ति स्रोतों में विविधता लाने की रणनीति के अनुरूप, डिलीवरी निर्बाध रूप से जारी है।

फिर भी असली परीक्षा आर्कटिक एलएनजी-2 में है। 2021 में एक बार 59% पूरी हो चुकी यह परियोजना पश्चिमी प्रतिबंधों के तहत रुक गई। 2025 तक, केवल सीमित परिचालन ही फिर से शुरू हुए। भारत ने आधिकारिक दूरी बनाए रखी है, लेकिन चुपचाप बातचीत जारी है क्योंकि रूस कच्चे तेल की पहुंच के समान, भारी छूट और डीईएस (डिलीवर्ड एक्स-शिप) शर्तों के साथ भारतीय खरीदारों को आकर्षित कर रहा है। ट्रम्प के फिर से चुनाव के बाद अमेरिका-रूस तनाव में हाल ही में आई कमी एक संभावित सफलता प्रदान करती हैः यदि द्वितीयक प्रतिबंध हटा दिए जाते हैं, तो भारतीय फर्म अंततः कदम रख सकती हैं, जिससे एक महत्वपूर्ण आर्कटिक ऊर्जा अक्ष खुल सकती है।

भारत का आर्कटिक जुड़ाव उसकी ₹एक्ट फार ईस्ट₹ नीति और 2022 की आर्कटिक नीति के अनुरूप भी है। सखालिन और वांकोर्नेफ्ट में ओएनजीसी विदेश की $8.4 बिलियन की विरासत परिचालन अनुभव और राजनीतिक पूंजी प्रदान करती है जिसे आर्कटिक में फिर से तैनात किया जा सकता है, हालांकि कठिन वातावरण और भू-राजनीतिक दांव बहुत अलग हैं।

जैसे-जैसे रूस 2030 तक वैश्विक एलएनजी निर्यात का 20% हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखता है, भारत की ऊर्जा गणना को अनुकूल होना चाहिए। नई दिल्ली के लिए, आर्कटिक एलएनजी से कहीं अधिक प्रदान करता है, यह रूसी संसाधनों को भारत के बुनियादी ढांचे और रणनीतिक आकांक्षाओं से जोड़ने वाला एक नया गलियारा है।

पश्चिमी प्रतिबंधों के बीच रूस के आर्कटिक की ओर मुड़ने के साथ, भारत को उभरते ध्रुवीय रसद में रणनीतिक अवसर मिलता है। उत्तरी समुद्री मार्ग (एनएसआर), जो स्वेज नहर की तुलना में 40% छोटा मार्ग प्रदान करता है और पारगमन समय को 16 दिन कम करता है, भारत-रूसी आर्कटिक सहयोग के लिए केंद्रीय होता जा रहा है। 2023 में, एनएसआर कार्गो यातायात रिकॉर्ड 36.254 मिलियन टन तक पहुंच गया, मॉस्को ने 2030 तक 200 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है। भारत की बढ़ती हिस्सेदारी स्पष्ट है, 2023 की शुरुआत तक, यह रूस के मरमांस्क बंदरगाह पर कार्गो का 35% हिस्सा था, जो मुख्य रूप से कोयला आयात में वृद्धि से प्रेरित था।

इसके पूरक के रूप में, चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा (ईएमसी), जो 2024 के अंत में शुरू हुआ, सीधे भारत के पूर्वी समुद्र तट को रूस के आर्कटिक प्रवेश द्वार से जोड़ता है। ईएमसी के साथ व्यापार में तेजी आई है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2024-25 में कोयला शिपमेंट में 87% और कच्चे तेल में 48% की वृद्धि हुई है। यह गलियारा न केवल भारत की रूस के विशाल आर्कटिक और सुदूर पूर्व संसाधनों तक पहुंच को सुगम बनाता है, बल्कि इसकी समुद्री उपस्थिति को भी मजबूत करता है। भारत अपने बंदरगाहों और शिपयार्डों को आर्कटिक रसद में महत्वपूर्ण नोड्स के रूप में स्थापित कर रहा है, और $750 मिलियन मूल्य के रूसी आइसब्रेकर के संयुक्त उत्पादन का प्रस्ताव कर रहा है। साथ में, एनएसआर और ईएमसी आर्कटिक कनेक्टिविटी में भारत के एक गंभीर खिलाड़ी के रूप में उभरने का प्रतीक हैं, जहां भू-अर्थशास्त्र और रणनीति अब अभिसरण करते हैं।

कोला प्रायद्वीप, नोरिल्स्क और याकुतिया में फैला रूस का आर्कटिक सीमांत महत्वपूर्ण खनिजों का खजाना है जो

भारत की हरित और डिजिटल महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। कोल्मोजेस्कोंय जमा में रूस के लिथियम भंडार का लगभग 19% हिस्सा है, लोवोजेस्कोंय देश का सबसे बड़ा दुर्लभ-पृथ्वी तत्व (आरईई) स्रोत है, और नोरिल्स्क वैश्विक पैलेडियम का 40% से अधिक आपूर्ति करता है। रोसाटॉम और नोरनिकेल जैसे राज्य दिग्गजों के समर्थन से, रूस तेजी से विकास कर रहा है। नोरनिकेल की योजना 2025 तक कोबाल्ट उत्पादन को तीन गुना बढ़ाकर 3,000 टन प्रति वर्ष करने की है, जबकि रोसाटॉम का पोलर लिथियम जेवी वैश्विक बाजारों के लिए कोल्मोजेस्कोंय के लिथियम का दोहन करने की तैयारी कर रहा है।

भारत के लिए, जो अपने लिथियम, कोबाल्ट और निकल का 100% आयात पर निर्भर है, इन संसाधनों तक पहुंच एक रणनीतिक अनिवार्यता है। चीन के वैश्विक महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं के 60-90% पर हावी होने के साथ, रूस भारत को विविधीकरण का एक दुर्लभ अवसर प्रदान करता है। राजदूत डेनिस अलीपोव ने आर्कटिक खनिज सहयोग में आपसी हितों पर प्रकाश डाला है। भारत का रूस में तेल और गैस परियोजनाओं में $15 बिलियन का निवेश, और 2024 से चालू चेन्नई-व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा, सुरक्षित रसद और सहयोगी खनन उद्यमों के लिए आधार तैयार करता है।

रूस के आर्कटिक में अनुमानित 658 मिलियन टन दुर्लभ धातुएं हैं, जिनमें 29 मिलियन टन आरईई शामिल हैं, जो भारत के ईवी, नवीकरणीय ऊर्जा और रक्षा प्रौद्योगिकियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत टॉमटोर जैसी प्रसंस्करण परियोजनाओं के लिए प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर भी नजर गड़ाए हुए है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आरईई जमा है। महत्वपूर्ण खनिजों पर एक प्रस्तावित उत्कृष्टता केंद्र निष्कर्षण विधियों को आगे बढ़ाने के लिए गिप्रो निकल संस्थान जैसे रूसी संस्थानों के साथ साझेदारी कर सकता है।

हालांकि पश्चिमी प्रतिबंध वित्तपोषण को जटिल बनाते हैं, भारत का 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार में 100 बिलियन डॉलर का लक्ष्य संरचित सौदों के लिए एक ढांचा प्रदान करता है। भारत के लिए, आर्कटिक खनिज केवल आर्थिक संपत्ति नहीं हैं, बल्कि रणनीतिक स्वायत्तता के स्तंभ हैं। रूस के संसाधन-समृद्ध, प्रतिबंध-अवरोधित आर्कटिक में खुद को स्थापित करके, भारत अपनी आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत कर सकता है, अपने हरित परिवर्तन को तेज कर सकता है और चीन पर निर्भरता को कम कर सकता है, यह सब तेजी से विकसित हो रहे ध्रुवीय परिदृश्य में प्रभाव कोassert करते हुए किया जा सकता है।

भारत का आर्कटिक जुड़ाव अर्थशास्त्र से परे, वैज्ञानिक जांच और जलवायु कूटनीति में निहित है। 2013 में आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने के बाद से, भारत ने आर्कटिक प्रवासी पक्षी पहल और आर्कटिक वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण कार्य समूह जैसी पहलों में सक्रिय रूप से योगदान दिया है। इसकी सबसे प्रमुख वैज्ञानिक संपत्ति न्या-एलेसुंड, स्वालबार्ड में स्थित हिमाद्री अनुसंधान स्टेशन है, जो 2008 से चालू है और राष्ट्रीय ध्रुवीय और समुद्र अनुसंधान केंद्र (एनसीपीओआर) द्वारा प्रबंधित है।

हिमाद्री ग्लेशियोलॉजी, महासागर-वायुमंडल अंतःक्रियाओं और भारतीय मानसून पर आर्कटिक के प्रभाव पर साल भर के अध्ययन का समर्थन करता है, जिसमें 200 से अधिक भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान मिशनों में भाग ले रहे हैं।

भारत की क्षमताएं रूस के साथ गहरे सहयोग की गुंजाइश प्रदान करती हैं, विशेष रूप से अंतरिक्ष-आधारित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), अपने कार्टोसैट और RISAT उपग्रहों का उपयोग करके आर्कटिक मानचित्रण, पर्यावरण निगरानी और NSR के साथ गतिविधि पर नज़र रखने में सहायता कर सकता है।

भारत और रूस की लंबी चली आ रही अंतरिक्ष साझेदारी, जो 1962 में उनके पहले समझौते से चली आ रही है, ऊर्जा, शिपिंग और रणनीतिक निगरानी में आर्कटिक सहयोग के लिए अप्रयुक्त क्षमता प्रदान करती है। जबकि वर्तमान आर्कटिक-विशिष्ट परियोजनाएं सीमित हैं, भविष्य के संयुक्त अंतरिक्ष अनुप्रयोग ध्रुवीय क्षेत्र में समुद्री क्षेत्र की जागरूकता और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ा सकते हैं।

भारत का आर्कटिक अभियान एक रणनीतिक छलांग है, जो ऊर्जा सुरक्षा, खनिज पहुंच और वैज्ञानिक ताकत को रूस के संसाधन-समृद्ध उत्तर से जोड़ता है। जैसे-जैसे आर्कटिक वैश्विक शक्ति गलियारों को फिर से आकार दे रहा है, भारत अब एक दर्शक नहीं बल्कि एक उभरता हुआ हितधारक है। रसद के साथ और 100 बिलियन डॉलर के व्यापार दृष्टिकोण के साथ, ध्रुवीय सीमांत भारत को संसाधनों से अधिक, लचीलापन प्रदान करता है। आर्कटिक की बर्फ में, भारत रणनीतिक स्वायत्तता के लिए नई जमीन पाता है।

**(मनीष वैद, जूनियर फेलो, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, जिनकी शोध रुचि रणनीतिक ऊर्जा अंतर्दृष्टि और हरित बदलावों में है और यह आलेख RT news में प्रकाशित है।)**

# खाड़ी में बहती बदलाव की बयार

राष्ट्रपति ट्रम्प की खाड़ी यात्रा ने क्षेत्र के गहरे सामाजिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक परिवर्तनों को स्वीकारा है। यह यात्रा खाड़ी देशों द्वारा आंतरिक रूप से चलाए जा रहे आधुनिकीकरण प्रयासों को मान्यता देती है, जो क्षेत्र के बारे में पुरानी पश्चिमी धारणाओं को चुनौती दे रहा है।

संतु दास

राष्ट्रपति ट्रम्प की हाल की फ़ारस की खाड़ी की यात्रा, जो सतही तौर पर वाणिज्यिक समझौतों और औपचारिक प्रदर्शनों से भरी एक नियमित राजनयिक कोशिश प्रतीत होती है, एक गहरा महत्व रखती हैः परिवर्तनकारी ताकतों की एक लंबे समय से प्रतीक्षित स्वीकृति जो इस क्षेत्र को फिर से आकार दे रही हैं। ट्रम्प द्वारा इन सामाजिक, आर्थिक और भू-राजनीतिक बदलावों का सार्वजनिक समर्थन, खाड़ी के भीतर कई लोगों द्वारा लंबे समय से मानी जा रही बात को विश्वसनीयता प्रदान करता है - यह क्षेत्र सक्रिय रूप से मुस्लिम दुनिया के भीतर आधुनिकीकरण को फिर से परिभाषित कर रहा है, जो लंबे समय से चली आ रही पश्चिमी धारणाओं को चुनौती दे रहा है।

बहुत लंबे समय से, खाड़ी को एक संकीर्ण दृष्टिकोण से देखा गया है, जिसकी विशेषता तेल की दौलत, धार्मिक रूढ़िवाद और सत्तावादी शासन है। पश्चिमी नीति निर्माताओं और मीडिया संस्थानों द्वारा प्रचारित इस सीमित परिप्रेक्ष्य ने इस क्षेत्र को परिवर्तन का विरोध करने वाले पेट्रो-राजतंत्रों

के एक कार्टून में बदल दिया। हालांकि, यह छवि अब पुरानी हो चुकी है। 2017 में सऊदी अरब में ट्रम्प की पहली यात्रा के बाद से, आर्थिक विविधीकरण और नवाचार के प्रति इस क्षेत्र की प्रतिबद्धता तेज हुई है, इस हालिया यात्रा के साथ औपचारिक रूप से वैश्विक स्तर पर इन प्रयासों को मान्यता दी गई और मान्य किया गया है। परिवर्तनों को सही मायने में समझने के लिए, प्रमुख खिलाड़ियों और उनके पीछे प्रेरक शक्तियों की महत्वपूर्ण परीक्षा आवश्यक है।

सऊदी अरब, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मार्गदर्शन में, इस परिवर्तनकारी भावना का उदाहरण है। विजन 2030, सामाजिक-आर्थिक सुधार के लिए एक व्यापक खाका है, जो पहले अकल्पनीय बाधाओं को तोड़ रहा है। संगीत कार्यक्रमों, सिनेमाघरों, महिला ड्राइवरों, सार्वजनिक त्योहारों और सरकारी और कॉर्पोरेट नेतृत्व पदों में महिलाओं की बढ़ती उपस्थिति का परिचय तेजी से सामान्य हो रहा है। यह परिवर्तन सतही मनोरंजन उदारीकरण या बढ़ी हुई महिला कार्यबल भागीदारी से परे फैला हुआ है; यह मौलिक रूप से राष्ट्रीय लोकाचार को नया आकार देता है।

जबकि महत्वपूर्ण चुनौतियाँ बनी हुई हैं, विशेष रूप से राजनीतिक असंतोष और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में, इन सुधारों का पैमाना और दिशा निर्विवाद है, जो किंगडम के लिए एक नए युग का वादा करता है। ट्रम्प का समर्थन एक गहरी समझ का संकेत देता है कि गहरी पारंपरिक समाजों के भीतर सार्थक परिवर्तन बाहरी थोपने के रूप में नहीं, बल्कि व्यवस्थित रूप से उभरना चाहिए। सऊदी अरब और पड़ोसी राज्यों में होने वाले सुधारों की अवधारणा, वित्त पोषण और कार्यान्वयन इस क्षेत्र के अपने नेतृत्व द्वारा की जाती है, अक्सर परिवर्तन के लिए उत्सुक एक बढ़ती युवा जनसांख्यिकी के सहयोग से। यह नीचे-ऊपर दृष्टिकोण अधिक स्वीकृति और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करता है।

जहां सऊदी अरब आंतरिक सुधार का नेतृत्व कर रहा है, वहीं संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) इन सुधारों की संभावित उपलब्धियों का प्रमाण है। दुबई और अबू धाबी भविष्य के शहरी विकास, उन्नत तकनीक-आधारित सार्वजनिक सेवाओं और अत्याधुनिक नवाचार का पर्याय बन गए हैं। मंगल ग्रह पर यूएई के सफल मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक अग्रणी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटल शासन में इसके पर्याप्त निवेश ने इसे एक वैश्विक ट्रेंडसेटर के रूप में स्थापित किया है। यूएई का परिवर्तन मात्र तकनीकी प्रगति से परे है; यह अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और ज्ञान-आधारित समाज को बढ़ावा देने की एक रणनीतिक दृष्टि का प्रतिनिधित्व करता है।

इसके अलावा, यूएई ने वैश्विक प्रतिभा के लिए एक संपन्न पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया है, जो स्टार्टअप, बहुराष्ट्रीय निगमों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति के लिए एक आश्रय बन गया है। ट्रम्प की यात्रा ने देश के रणनीतिक महत्व को उजागर किया, न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में, बल्कि एक अस्थिर क्षेत्र में एक प्रमुख राजनयिक खिलाड़ी के रूप में भी। इजरायल के साथ संबंधों को सामान्य करते हुए, अब्राहम समझौते को कराने

में यूएई की महत्वपूर्ण भूमिका, पुरानी विचारधाराओं में कम निहित एक अधिक व्यावहारिक विदेश नीति दृष्टिकोण की ओर बदलाव का प्रतीक है। यह साहसिक कदम क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति यूएई की प्रतिबद्धता और आपसी हितों के आधार पर नई साझेदारी बनाने की उसकी इच्छा को रेखांकित करता है।

कतर ने भी अपने छोटे भौगोलिक पदचिह्न के बावजूद एक उल्लेखनीय परिवर्तन किया है। 2022 फीफा विश्व कप की सफल मेजबानी ने राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा और क्षमता के एक शक्तिशाली बयान के रूप में कार्य किया, अपेक्षाओं को पार करते हुए और एक वैश्विक दर्शकों के लिए एक आधुनिक, पॉलिश छवि का प्रदर्शन किया। जबकि इस कार्यक्रम को श्रम अधिकारों और सांस्कृतिक रूढ़िवाद के संबंध में आलोचना का सामना करना पड़ा, इसने निर्विवाद रूप से कतर के अंतरराष्ट्रीय कद को बढ़ाया।

खेलों से परे, कतर ने रणनीतिक रूप से खुद को अफगानिस्तान से लेकर लेबनान तक क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में एक अपरिहार्य मध्यस्थ के रूप में स्थान दिया है। अल जज़ीरा की वैश्विक मीडिया पहुंच द्वारा प्रवर्धित एक सुविधाकर्ता और शांति दलाल के रूप में इसकी भूमिका ने इसकी राजनयिक साख को बढ़ाया है और मध्य पूर्व में एक महत्वपूर्ण आवाज के रूप में अपनी जगह सुरक्षित कर ली है। कतर के बढ़ते राजनयिक प्रभाव के ट्रम्प के अभिस्वीकृति दुनिया के मंच पर राष्ट्र की बढ़ती प्रोफ़ाइल को दर्शाती है। जटिल राजनीतिक परिदृश्यों को नेविगेट करने और विरोधी पक्षों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाने की कतर की क्षमता शांतिपूर्ण संघर्ष समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

इन परिवर्तनों के अंतर्निहित शिक्षित युवाओं के लौटने वाले प्रवासी का महत्वपूर्ण योगदान है। सऊदी अरब, यूएई और कतर के हजारों छात्र, जिन्होंने सरकारी छात्रवृत्ति और सहायता कार्यक्रमों के माध्यम से विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त की है, न केवल शैक्षणिक डिग्री, बल्कि दुनिया भर से नए दृष्टिकोण और सर्वोत्तम प्रथाओं को वापस ला रहे हैं। ये युवा पेशेवर नई ऊर्जा और विशेषज्ञता को सरकारी मंत्रालयों, स्टार्टअप, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों में इंजेक्ट कर रहे हैं।

इस लहर को जो चीज अलग करती है, वह केवल उनका तकनीकी ज्ञान ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीय विकास के प्रति उनकी भावना और प्रतिबद्धता भी है। खाड़ी के नेताओं ने इन युवा पेशेवरों

के मूल्य को पहचाना है, उन्हें रणनीतिक भूमिकाएं सौंपी हैं और उन्हें अपने राष्ट्रों के भविष्य में वास्तविक हिस्सेदारी दी है। युवाओं में विश्वास का यह प्रदर्शन दर्शाता है कि परिवर्तन केवल कॉस्मेटिक नहीं है, बल्कि गहराई से संरचनात्मक बन रहा है।

हालांकि, पश्चिमी राजधानियों में संदेह बना रहता है, जहां खाड़ी में सुधारों को अक्सर सार्वजनिक संबंध अभ्यासों या चल रहे दमन के कार्यों को छिपाने वाले सतही लिबास के रूप में खारिज कर दिया जाता है। आलोचकों का तर्क है कि वास्तविक राजनीतिक उदारीकरण के बिना, ये परिवर्तन खोखले हैं और इनमें सार की कमी है। यह द्विआधारी सोच - यह धारणा कि एक समाज को पूर्ण उदार लोकतंत्र और सत्तावादी शासन के बीच चयन करना चाहिए - क्षेत्रीय शासन और सांस्कृतिक परिवर्तन की जटिलताओं की अनदेखी करता है। खाड़ी राज्य अपनी गति से आर्थिक प्रगति को सांस्कृतिक संरक्षण और क्रमिक राजनीतिक सुधार के साथ संतुलित करने की मांग कर रहे हैं।

ट्रम्प की यात्रा ने इस संकीर्ण कथा को चुनौती देने में मदद की। उनके द्वारा यह सार्वजनिक स्वीकृति कि सुधार बाहरी ताकतों द्वारा तय नहीं किए गए हैं, बल्कि आंतरिक रूप से संचालित किए जा रहे हैं, ने इस क्षेत्र की एजेंसी को मान्य किया। यह मान्यता, हालांकि दिखने में सरल है, महत्वपूर्ण है। यह संकेत देता है कि खाड़ी राष्ट्र केवल अंतरराष्ट्रीय नीति के विषय नहीं हैं, बल्कि अपने भविष्य के वास्तुकार हैं। यह क्षेत्र के अनूठे संदर्भ को समझने और इसे अपनी गति से विकसित करने की अनुमति देने के महत्व को रेखांकित करता है।

ट्रम्प की यात्रा के सबसे कूटनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षणों में से एक सऊदी अरब द्वारा सुगम सीरियाई नेतृत्व के साथ उनकी बैठक थी। प्रतिबंधों को उठाने की घोषणा ने अमेरिकी नीति में संभावित बदलाव का सुझाव दिया और मध्य पूर्व के भविष्य को आकार देने में खाड़ी की बढ़ती भूमिका पर प्रकाश डाला। पश्चिमी ढांचे पर पूरी तरह से भरोसा करने के बजाय, सऊदी अरब जैसे देश सक्रिय रूप से क्षेत्रीय संवादों को सुविधाजनक बना रहे हैं, जिसका उद्देश्य स्थिरता को बढ़ावा देना और कट्टरपंथी विचारधाराओं पर अंकुश लगाना है। यह सक्रिय दृष्टिकोण क्षेत्रीय स्वामित्व और क्षेत्र के भविष्य के लिए जिम्मेदारी लेने की इच्छा को प्रदर्शित करता है।

यह स्थिरता और सुधारकों के रूप में यह भूमिका ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब चरमपंथी विचारधाराएं मुस्लिम दुनिया के अन्य हिस्सों में मोहभंग का फायदा उठाना जारी रखती हैं। सह-अस्तित्व, नवाचार और व्यावहारिक उद्देश्य को बढ़ावा देकर, खाड़ी राज्य कट्टरपंथ के कपटी ताकतों को चुनौती देने वाली एक सम्मोहक जवाबी कथा पेश करते हैं। आर्थिक अवसर, सामाजिक स्वतंत्रताएं और शिक्षा और तकनीकी प्रगति के प्रति प्रतिबद्धता जो खाड़ी में पेश की जाती हैं, निराशा और निराशा का एक आकर्षक विकल्प प्रस्तुत करती हैं जो अतिवाद को ईंधन देती हैं।

अंततः, ट्रम्प की यात्रा को विशिष्ट समझौतों और नीतियों से कम और जो दर्शाती है उसके लिए अधिक याद किया जा सकता हैः खाड़ी के चल रहे परिवर्तन की वैश्विक मान्यता में एक महत्वपूर्ण मोड़। किसी भी राष्ट्र के सुधार एजेंडे का मूल्यांकन करते समय महत्वपूर्ण विश्लेषण और सावधानी आवश्यक है, लेकिन प्रगति की वास्तविक स्वीकृति भी आवश्यक है। खाड़ी राज्य परिपूर्ण नहीं हैं, और उनके सुधार पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन वे उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं जो क्षेत्र और दुनिया के लिए आशा प्रदान करता है। यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पुरानी मान्यताओं से आगे बढ़ सकता है और खाड़ी को उसके बदलते मैदान पर मिल सकता है, तो सहयोग, समझ और प्रगति का एक नया युग पहुंच के भीतर हो सकता है। खाड़ी के प्रति अधिक सूक्ष्म और खुले विचारों वाला दृष्टिकोण, इसकी प्रगति को स्वीकार करना और इसकी विकसित गतिशीलता के साथ जुड़ना, क्षेत्र के लिए एक अधिक स्थिर और समृद्ध भविष्य को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है।

उड़ीसा में जन्मी और शिकागो में पली-बढ़ी लिसा मिश्रा पिछले 7 सालों से मनोरंजन जगत में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने बॉलीवुड के कई गानों के कवर गाए हैं और 'कॉल मी बे' के बाद अब 'द रॉयल्स' वेब सीरीज में भी नजर आई हैं।

# लिसा मिश्रा

# 'पचासों बार रिजेक्ट हुई'

**लिसा मिश्रा** अब अपने बैकग्राउंड के बारे में वह कहती हैं, 'मैं बरमपुर उड़ीसा की पैदा हुई हूं। मेरे पापा-मम्मी दोनों उड़ीसा से हैं। मेरे पापा स्टेट बैंक के कर्मचारी थे, जबकि मम्मी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थीं। जिस वक्त मैं महज 6 साल की थी, मेरे पिता को कैंसर हो गया था, उसी वक्त हम शिकागो में शिफ्ट हो गए। हालांकि मेरा पैतृक परिवार आज भी उड़ीसा में है, मगर तब मैं, मेरी बड़ी बहन, मम्मी और पापा शिकागो शिफ्ट हो गए। मैंने पूरे 18 साल अमेरिका में बिताए। मगर इतना जरूर कह सकती हूं कि बाहरी तौर पर भले मैं अमेरिकन लगूं, मगर घर के अंदर मैं और मेरा परिवार काफी देसी रहा, क्योंकि मेरे माता-पिता नहीं चाहते थे कि हम अपनी जड़ें भूलें।'

लिसा का मानना है कि संगीत हमेशा उनका पहला प्यार रहा। वह कहती हैं, ' जब मैं शिकागो में थी, तो इंडियन क्लासिकल संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं ले पाई, क्योंकि मेरे पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं थे, मगर मैं 3-4 साल की उम्र से बॉलिवुड गाने गाने लगी। बॉलिवुडका वो संगीत मेरे भीतर रह गया। मैं मात्र 13 साल की रही होऊंगी, जब मैंने पहली बार अपना यूट्यूब चैनल खोला था। तब मैं इंग्लिश गाने गाती थी, मगर ये अहसास होने में मुझे काफी समय लग गया कि मुझे हिंदी गाने गाने चाहिए।

बालीवुड के संघर्षों पर वह कहती हैं, 'इंडस्ट्री में नए कलाकारों को ऑडिशन की राह से तो गुजरना ही पड़ता है। मैं अब तक अनगिनत ऑडिशन दे चुकी हूं और मुझे पचासों बार रिजेक्ट किया गया है, मगर मैं इसे बुरा नहीं मानती। यह मेरी ट्रेनिंग है और इसी के जरिए मैं अपनी कमियां जान पाती हूं। मैं हमेशा ये जानने को उत्सुक रहती हूं कि अगली बार क्या सुधार करूं।

# पंकज त्रिपाठी

# 'थोड़ा गुरूर चढ़े तो मैं खुद को संभालूं'

**अममून सफलता** इंसान के दिमाग पर चढ़ ही जाती है, उसे बदल भी देती है, मगर इंडस्ट्री के सबसे व्यस्त और चहेते कलाकारों में शुमार होने के बावजूद पंकज त्रिपाठी जस के तस हैं। व्यक्तित्व में वही सरलता, बोली में वही मिठास ! कैसे? पूछने पर वह मजाकिया अंदाज में कहते हैं- मैं तो चाहता हूं कुछ बदलाव आए, पर कुछ केमिकल लोचा है कि मेरे दिमाग में आता ही नहीं है कि मैं सफल हूं।

अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ वह कहते हैं, 'मैं तो चाहता हूं कि कुछ बदलाव आए, लेकिन नहीं आ पा रहा है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। कुछ तो होना चाहिए यार कि लगे कि मैं सफल हूं। ये मेरे दिमाग में तो होना चाहिए। मेरे दिमाग में भी नहीं आता है। मैं तो चाहता हूं कि दिमाग पर सक्सेस चढ़े और मैं अपने विचार और बुद्धि से उसे नियंत्रित करूं कि विनम्र रहना है, ये सक्सेस का गुरूर है, पर वही नहीं आ रहा है और यही प्रॉब्लम है कि क्यों नहीं आ रहा है? थोड़ा तो आना चाहिए ना, कोई केमिकल लोचा है।'

यही नहीं, पिछले कुछ समय में धड़ाधड़ कई फिल्में और सीरीज करने वाले पंकज त्रिपाठी इतनी व्यस्तता भी पसंद नहीं करते। उनका कहना है, 'हम ऐक्टिंग के लिए नहीं जी रहे हैं।

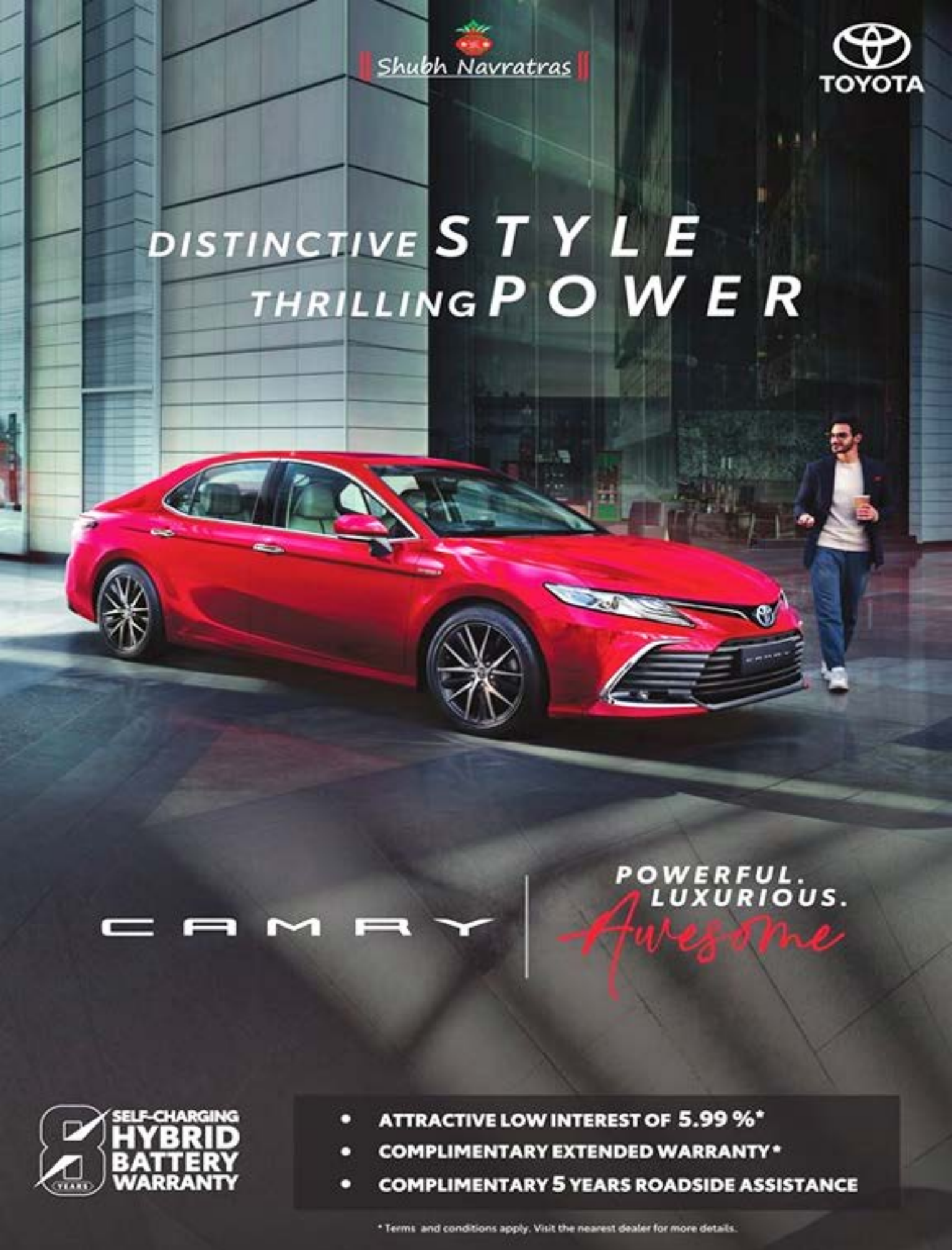

Shubh Navratras
TOYOTA
DISTINCTIVE STYLE
THRILLING POWER
CAMRY
POWERFUL.
LUXURIOUS.
Awesome
SELF-CHARGING HYBRID BATTERY WARRANTY
8 YEARS
• ATTRACTIVE LOW INTEREST OF 5.99 %*
• COMPLIMENTARY EXTENDED WARRANTY*
• COMPLIMENTARY 5 YEARS ROADSIDE ASSISTANCE
* Terms and conditions apply. Visit the nearest dealer for more details.

RNI TITLE CODE : DELENG19447

Experience it. Look at it from all angles. Check out the contours, the craftsmanship, the perfection of form and the waterfall...

Glamour ▪ Convenience ▪ Technology

MARC®
Bathing Luxury

**MARC SANITATION PVT. LTD.**

A-2, S.M.A. Co-op. Industrial Estate, G.T. Kamal Road, Delhi-110 033
Ph: 27691410, Fax: 011-27691445/27692295 E-mail: info@marcindia.com Website : www.marcindia.com